www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार, 10 अगस्त, 2026

दैनिक जागरण

भाव के अभाव में भक्ति का कोई अर्थ नहीं

मेटा को चेतावनी

यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार ने इंस्टाग्राम, वाट्सएप और फेसबुक का संचालन करने वाली कंपनी मेटा को यह चेतावनी दी कि उसे भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। इसके साथ ही सरकार ने मेटा से अपने एल्गोरिदम को लेकर भी जवाब तलब किया है। यह सुनिश्चित करना होगा कि इस निर्देश का वास्तव में पालन हो, क्योंकि मेटा अथवा अन्य इंटरनेट मीडिया कंपनियां एल्गोरिदम का मनमाना उपयोग करती हैं। एआइ के आगमन के बाद उनके लिए ऐसा करना और आसान हो गया है। अब वह किसी से छिपा नहीं कि इंटरनेट कंपनियां एक विशेष एजेंडे का प्रचार-प्रसार करती हैं। वे यह सुनिश्चित कर रही हैं कि लोग क्या देखें और क्या नहीं? ऐसा करके वे लोगों के चिंतन को प्रभावित कर रही हैं। चिंताजनक यह है कि यह काम प्रायः संकीर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह एक तथ्य है कि इंटरनेट कंपनियां कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने का काम कर चुकी हैं। वे ऐसा भारत में भी कर चुकी हैं और इसका पता कैंब्रिज एनालिटिका मामले से चलता है। वैसे तो इंटरनेट मीडिया कंपनियां अपने को 'सोशल मीडिया' कहती हैं, लेकिन सच यह है कि वे असामाजिक और अराजक तत्वों को भी प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। वे ध्रुवीकरण के साथ ही सामाजिक विभाजन की खाई भी चौड़ी कर रही हैं। वे कई बार अपने गलत इरादों की पूर्ति करती हुई पाई गई हैं। हर बार वे माफी मांगकर बच निकलती हैं। भारत सरकार को अब केवल माफी से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि कोई इंटरनेट मीडिया कंपनी अनुचित कार्य करती पाई जाए तो उसे वैसे ही कठोर दंड का भागीदार बनाया जाना चाहिए जैसे अनेक पश्चिमी देश समय-समय पर बनाते हैं और उन पर भारी जुर्माना लगाते हैं। अभी हाल में अमेरिका ने मेटा पर भारी जुर्माना लगाया। इंटरनेट मीडिया कंपनियां दुनिया भर में लोगों को लती भी बना रही हैं।

अभी हाल में मेटा ने प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को हटाने को लेकर जो माफी मांगी, उसे खारिज कर सरकार ने उचित ही किया। समस्या केवल यह नहीं कि मेटा ने किसी खास एजेंडे के तहत शरारतपूर्ण ढंग से प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाया, बल्कि यह भी है कि उसने यह माना कि उसके प्लेटफार्म पर बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के साथ-साथ डीपफेक वीडियो को बढ़ावा दिया गया। यह भी स्वीकारा कि उसने पैसे लेकर हानिकारक सामग्री को बढ़ावा दिया। ये सब ऐसी हरकतें हैं, जिनके लिए मेटा अथवा अन्य इंटरनेट कंपनियों को जवाबदेह बनाना अनिवार्य है। यह सही समय है कि भारत सरकार मेटा एवं अन्य इंटरनेट मीडिया कंपनियों को जवाबदेह बनाने के साथ ही इस पर भी विचार करे कि आखिर विदेशी इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर निर्भर रहना कहां तक उचित है?

प्रेरक पहल

सफल व्यक्तित्व से साक्षात्कार मन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करता है। किताबी ज्ञान तो सफलता की सीढ़ी है ही, किंतु सफल व्यक्तियों के साथ परस्पर संवाद से मिली व्यावहारिक समझ भी जीवन की राह आसान बनाती है, आगे बढ़ने को प्रेरणा भी देती है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश में शासन स्तर से हो रही नई पहल से छात्रों को रोशनी मिलेगी। अब जिलों में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के युवा अधिकारी इंटरमीडिएट कक्षा के बच्चों के साथ संवाद कर उनका मार्गदर्शन करेंगे। इस शासकीय पहल से जेन-जी की पीढ़ी को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। वैसे शासन के स्तर से यह प्रयास होना चाहिए कि केवल आइएएस-आइपीएस या आइएफएस अधिकारी ही नहीं, जिले के डाक्टर-प्रोफेसर व अन्य क्षेत्रों के सफलतम लोगों को भी इस संवाद में भागीदार बनाया जाए। ऐसे अवसर पाकर छात्र करियर, प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और जीवन की चुनौतियों से निपटने के तरीके जान सकेंगे। जीवन में यही मोड़ होता है, जहां लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। बड़ा होकर क्या बनना है? यह तो बचपन से ही पूछा-सोचा जाने लगता है, पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई के साथ ही जीवन में कुछ होने की प्रतिबद्धता अंतिम रूप से तय होने लगती है। अच्छी बात है कि स्टार्टअप, सरकारी योजनाओं, वित्तीय साक्षरता और व्यापार प्रबंधन से जुड़े विकल्पों पर भी इस कड़ी में संवाद होगा।

इस प्रयास से जेन-जी को सफल व्यक्तित्व का जीवंत उदाहरण मिलेगा और वे उन जैसा होने की चेष्टा कर सकेंगे

खाड़ी पर ऊर्जा निर्भरता के खतरे

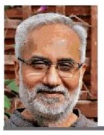

शिवकांत शर्मा

ईरान युद्ध ने दर्शाया कि ऊर्जा की आत्मनिर्भरता ही वास्तविक निजी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा है और इसकी कुंजी स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन में निहित है

एक पुरानी कहावत है कि नमाज छुड़ाने गए थे, लेकिन रोजे गले पड़ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही हुआ। ट्रंप ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने चले थे, लेकिन होर्मुज बंद करा बैठे। उन्होंने अमेरिका के साथ-साथ पूरी दुनिया को आर्थिक संकट में डाल दिया। लगभग चार महीनों की बमबारी के बाद ईरान 17 जून को 60 दिनों के युद्धविराम के साथ होर्मुज खोलने पर सहमत हुआ था। इसी दौरान उसके परमाणु निरस्त्रीकरण के साथ-साथ जिहादी गुटों का समर्थन बंद करने पर बातचीत होनी थी, लेकिन मामला होर्मुज किसकी निगरानी और नियंत्रण में रहे, इसी पर अटका रहा और युद्धविराम 20 दिनों के भीतर ही टूट गया। इस बार ट्रंप की 13 दिनों की बमबारी के बावजूद ईरान ने होर्मुज नहीं खोला। उलटे यमन के हाउती विद्रोहियों से लाल सागर के रास्ते जाने वाले सऊदी तेल टैंकरों पर भी हमले कराने शुरू कर दिए। लिहाजा पश्चिमी एशिया से गुजरने वाले दोनों समुद्री व्यापार मार्ग बंद हो गए हैं। इन्हें खोलने के लिए फिर युद्धविराम की बातें हो रही हैं, जिन्हें लेकर ट्रंप आश्वस्त लगते हैं।

इस बार ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत नहीं हो रही है। ईरान और ओमान आपस में तय कर रहे हैं कि व्यापारिक यातायात खुला रखने के लिए होर्मुज का प्रबंधन कैसे हो? दोनों के बीच यातायात के एक नए मार्ग पर सहमति भी बनी है, जिसके प्रवेश पर ईरान का नियंत्रण रहेगा और निकास पर ओमान का। इसका प्रविधान पिछली सहमति के पांचवें बिंदु में भी था, परंतु ट्रंप को ईरान के नियंत्रण वाली बात नहीं भाई और सहमति टूट गई थी। इस बार ईरान ने अपना रवैया और कड़ा करते हुए कहा है कि यातायात के प्रबंधन पर ओमान के साथ सहमति बन जाने के बावजूद होर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका के बर्ताव में सुधार नहीं आता। अमेरिका को अपनी नाकेबंदी खोलकर होर्मुज से अपनी नौसेना हटानी होगी, लड़ाई बंद करके बातचीत की मेज पर आना होगा और हमलों से हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी।

राष्ट्रपति ट्रंप 2015 की परमाणु संधि तोड़ चुके हैं और तीन बार समझौता वार्ताओं के बीच हमले कर चुके हैं। ऊपर से वे इजरायल के साथ संबंध बनाने की शर्त पर सऊदी अरब को परमाणु रिएक्टर देने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी ने दो दिन पहले पाकिस्तान और तुर्किए के साथ एक त्रिपक्षीय सामरिक समझौता किया है, जिसमें सहमति बनी कि एक पर हुए हमले को तीनों पर हुआ हमला माना जाएगा। ये तीनों ही देश अमेरिकी कृपापात्र हैं। इसलिए इस समय ऐसा समझौता होना अमेरिका की शह के बिना संभव नहीं है। इसलिए ईरान अब होर्मुज का नियंत्रण किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। रणनीतिकारों का मानना है कि होर्मुज का नियंत्रण ईरान को वह कुंजी देता है, जिसके सहारे वह खाड़ी के देशों और तेल पर निर्भर देशों को अनुकूल रिश्ते बनाए रखने पर विवश कर सकता है। यह अर्थव्यवस्था की उस बीटी शक्ति की तरह है, जो उसकी ढाल बन सकती है, लेकिन ईरान की यह बीटी शक्ति दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्थायी खतरे की बात होगी।

अवधेश राजपूत

असल में खाड़ी की ऊर्जा पर निर्भरता हमेशा से विश्व अर्थव्यवस्था की कमजोर नस रही है। पश्चिम एशिया में जब-जब लड़ाई छिड़ी तब-तब विश्व में ऊर्जा संकट आए, जिनसे महंगाई और मंदी जैसी मुश्किलें बढ़ीं। 1973 के अरब-इजरायल युद्ध में तेल के दाम चौगुने हो गए थे। इससे महंगाई बढ़ी, मंदी आई और शेयर बाजार धड़ाम हो गए थे। 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति के कारण तेल के दाम दोगुने हो गए थे। 1990 में इराक के कुवैत पर कब्जा कर लेने के कारण तेल के दाम तिगुने हो गए थे। अमेरिका और रूस के तेल निर्यातक बन जाने के कारण इस बार की लड़ाई से उतना गंभीर संकट तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन कोविड की मार से उबरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए इतनी मार भी कम नहीं है। होर्मुज का नियंत्रण ईरान के हाथों में जाता दिखाई दे रहा है, जो शीर्ष नेतृत्व के मारे जाने और व्यापक विनाश होने से उथल-पुथल के दौर में है।

दूसरी ओर, अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा कर भी ईरान को परास्त और खाड़ी के मित्र देशों को बचा नहीं पाया है। उसका वर्चस्व क्षीण होने से होर्मुज के ऊर्जा आपूर्ति मार्ग पर निर्भर रहना संभव नहीं रहा है। इसलिए हर देश विकल्प तलाश रहा है। भारत रूस, अमेरिका और वेनेजुएला के अलावा यूएई के फुजेरा बंदरगाह और ओमान के रास्ते तेल और गैस लेने की व्यवस्था कर रहा है। उसने ओमान के साथ सीमा व्यापार संधि की है और ओमान से गुजरात तक पाइपलाइन बिछाने पर विचार कर रहा है। इन उपायों के साथ-साथ भारत अपने नए तेल और गैस के भंडारों की खोज में भी जुटा है।

इस सबके बीच ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि दूसरे देशों और वैकल्पिक मार्गों से जीवाश्म ऊर्जा लेना और अपने यहां नए स्रोतों की तलाश करना समाधान नहीं है। असली और स्थायी समाधान ऊर्जा की आत्मनिर्भरता हासिल करने में है, जो स्वच्छ ऊर्जा से ही हासिल हो सकती है। मसलन चीन की ऊर्जा खपत भारत से पांच गुना है, लेकिन उसका एक चौथाई से अधिक वह स्वच्छ संसाधनों से पैदा करता है। बिजली में तो वहां सौर, पवन और पनबिजली का प्रतिशत 42 से ऊपर जा चुका है। इसलिए खाड़ी से पैदा होने वाले ऊर्जा संकट का उस पर बहुत गंभीर असर नहीं हुआ। स्वच्छ ऊर्जा के पांच बड़े लाभ हैं। पहला-आप खाड़ी या रूस जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों की उथल-पुथल से पैदा होने वाले ऊर्जा संकट से बचे रहते हैं। दूसरा-होर्मुज जैसे आपूर्ति मार्गों में गतिरोध से उत्पन्न संकट से बचते हैं। तीसरा-ऊर्जा आयात में खर्च होने वाले 12-13 लाख करोड़ रुपये बचा कर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा सुधारने में लगा सकते हैं। चौथा-विश्व का सबसे गंभीर संकट बने जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में मदद करते हैं। पांचवां-ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनते हैं और तेल प्रतिबंधों की पकड़ से बाहर होकर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करते हैं। इसलिए अब घर-घर में इस जागरूकता का प्रसार आवश्यक हो गया है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता ही वास्तविक निजी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा है।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

साधना, सेवा और समरसता की यात्रा

तेजस्वी सूर्या

कांवड़ यात्रा करने वाले केवल गंगाजल नहीं उठा रहे। वे भारतीय सभ्यता की एक महान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं

हाल में मैंने अपनी पहली कांवड़ यात्रा पूर्ण की। हरिद्वार में हर की पौड़ी से ऋषिकेश स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर तक कंधे पर गंगाजल से भरी कांवड़ लेकर लगभग 26 किमी पैदल चलना मेरे जीवन के सबसे भावपूर्ण आध्यात्मिक अनुभवों में से एक था। वर्षों से मन में यह प्रश्न था कि आखिर वह कौन सी शक्ति है, जो करोड़ों लोगों को स्वेच्छा से कई दिनों तक पैदल चलने, शारीरिक कष्ट सहने और केवल भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़ने की प्रेरणा देती है। कांवड़ यात्रा जैसी महाराष्ट्र की वारकरी यात्रा, नर्मदा परिक्रमा, अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा, तमिलनाडु की कावड़ी यात्रा, केरल की सबरीमाला, कर्नाटक की धर्मस्थल पदयात्रा और आंध्र की कनक दुर्गा यात्रा भी हैं। इन सबकी बाहरी भिन्नता के बावजूद एक समानता है। मनुष्य अपने पास जो सबसे बड़ी संपदा रखता है, वही ईश्वर को अर्पित करता है-अपना श्रम, अपना पुरुषार्थ और अपना शरीर। कांवड़ यात्रा इसी भाव की अति सुंदर अभिव्यक्ति है। हर वर्ष पांच करोड़ से अधिक श्रद्धालु, जिनमें अधिकांश युवा होते हैं, हरिद्वार या ऋषिकेश से गंगाजल लेकर यात्रा पर निकलते हैं। किसी के लिए यह यात्रा एक दिन की होती है, किसी के लिए एक सप्ताह की, पर भाव सबका एक ही होता है-चलते जाना साधना है। समर्पण ही इसका अंतिम उद्देश्य है।

मैंने लगभग 12-13 किलो वजन की कांवड़ कंधे पर उठाई और यात्रा आरंभ की। शुरुआती कुछ किमी उत्साह, जयघोष और ऊर्जा से भरे हुए थे, किंतु जैसे-जैसे रास्ता आगे बढ़ता गया, यात्रा का वास्तविक अर्थ उद्घाटित होने लगा। कांवड़ियों की श्रद्धा जितनी प्रभावित करने वाली थी, उतनी ही प्रभावित करने वाली वह सामाजिक शक्ति भी थी, जो पूरे मार्ग में यात्रा को संभाले हुए थी। यात्रा के दौरान अनेक लोग स्वयं यात्रा नहीं कर रहे थे, पर वे सेवा में लगे हुए थे। कोई पानी बांट रहा था, कोई भोजन परोस रहा था। यह शुद्ध सेवाभाव से उपजी सामाजिक शक्ति थी। हमारा समाज केवल व्यवस्था से अपेक्षा नहीं करता, बल्कि स्वयं भी व्यवस्था का सहभागी बनता है। कांवड़ यात्रा इसका जीवंत उदाहरण है। कांवड़ यात्रा के लिए जिस शारीरिक क्षमता, सहनशक्ति और अनुशासन की आवश्यकता होती है, उसकी चर्चा शायद ही कभी होती है। यही युवा यदि महंगी फीस देकर आयरनमैन या हाइरावस जैसी प्रतियोगिता में भाग लेते, तो उनकी दृढ़ता और अनुशासन की प्रशंसा होती, पर जब वही तरुणाई आस्था के रूप में दिखाई देती है और सामान्य परिवारों के युवा उसे दर्शाते हैं, तो उसे कमतर आंका जाता है।

श्रद्धा एवं समर्पण की अनुपम अभिव्यक्ति है कांवड़। फाइल

हममें से अधिकांश लोग मंदिर कुछ न कुछ मांगने जाते हैं, लेकिन उस क्षण, जब महादेव मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने खड़ा था, मेरे पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल मौन था और उसी मौन में पूर्णता थी। हमारी परंपरा में साधना का आरंभ शरीर से होता है। इसी भाव को बसवन्ना के वचन अत्यंत सुंदर रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं-धनवान लोग शिवालय बनवा सकते हैं, लेकिन साधारण जन अपने शरीर को ही मंदिर बना लेते हैं। उनके पैर स्तंभ बनते हैं, देह देवालय बनती है और मस्तक स्वर्ण कलश। पत्थर के मंदिर नष्ट हो सकते हैं, किंतु चलता-फिरता जीवंत मंदिर अमर होता है।

कांवड़िए प्रायः सामान्य परिवारों से आते हैं-किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी, दुकानदार और मेहनतकश युवा। उनके पास धन-संपदा भले न हो, लेकिन वे अपना शरीर, श्रम, कष्ट और भक्ति अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा भारतीय सभ्यता के तीन बड़े आयामों को जीवंत रूप में सामने लाती है। पहला आयाम है साधना। हर कदम आत्म-अनुशासन है, हर पीड़ा तपस्या है। शारीरिक कष्ट यहां बाधा नहीं, बल्कि यात्रा का अभिन्न अंग है। दूसरा आयाम है सेवा। कांवड़ यात्रा केवल कांवड़िए की यात्रा नहीं है। भंडारा लगाने, पानी पिलाने, चिकित्सा सहायता देने, थके हुए यात्री की देखभाल करने वाला-हर व्यक्ति इस यात्रा का सहभागी बन जाता है। तीसरा आयाम है समरसता। कांवड़ यात्रा में सामाजिक भेद पीछे छूट जाते हैं। सब साथ चलते हैं, सब कष्ट सहते हैं, सब समर्पित रहते हैं। सब एकसमान होते हैं। इस यात्रा में हमारा एक छोटा-सा प्रयास स्वच्छता को लेकर भी था। यात्रा मार्ग और वीरभद्र महादेव मंदिर परिसर में प्लास्टिक और कचरा साफ कर यह संदेश देने का प्रयास किया कि स्वच्छता भी साधना का ही एक रूप है। हम अक्सर कर्मकांड के पीछे छिपे मूल्यों को भूल जाते हैं। हम गंगा की आरती करते हैं, पर गंगा को स्वच्छ रखने के दायित्व को भूल जाते हैं। भारतीय परंपरा में प्रकृति सदैव पूजनीय रही है, इसलिए उसकी रक्षा भी हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। यात्रा पूर्ण होने पर मन में यह विचार बार-बार आया कि भारत को केवल पुस्तकों से नहीं समझा जा सकता। उसे समझना-जीना हो तो ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलना पड़ता है। कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालु केवल गंगाजल नहीं उठा रहे। वे हजारों वर्षों से जीवित भारतीय सभ्यता की एक महान परंपरा को अपने कंधों पर आगे बढ़ा रहे हैं।

(लेखक लोकसभा सदस्य एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

राम नाम की महिमा

तीनों लोकों में राम का नाम सबसे पवित्र है, सबसे कल्याणकारी है। राम के नाम से इहलोक और परलोक दोनों की सुधारा जा सकता है। जिस तरह परमात्मा का मूल सत्य है, उसी तरह से राम का नाम सत्य है। इससे सरल न कोई मंत्र है न तंत्र है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। जो असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति रखता है, वह राम नाम अमृत है। राम का नाम मोक्षदायी है। यह संसार के समस्त सुखों एवं आनंद का भंडार है। यह समस्त दुखों का निवाशक और सभी रोगों की महाऔषधि है। यह अनंत की छाया और अखंड की मर्यादा है। यह जीवन की राह और मृत्यु की हार है। राम की धुन, राम का जाप, राम का संकीर्तन, राम गीत, राम का संगीत, राम की कथा, राम का काव्य-जीवन का प्रवाह है। जीवन का लक्ष्य है, राम। राम का सब कुछ राम नाम में ही निहित है। भगवान शंकर ने कहा है, जो मनुष्य राम नाम का रसपान करेगा, वह मृत्यु के होने पर भी परम पद प्राप्त करेगा। शिव जी का यह कथन शाश्वत सत्य है।

'राम नाम सत्य है' इस तथ्य से लोग डरते हैं, क्योंकि मरते समय इसे लोगों द्वारा स्मरण किया जाता है। केवल मरते समय ही 'राम नाम सत्य' होता है, क्या शेष समय में राम नाम सत्य नहीं रह जाता? सब जानते हैं कि राम नाम अमोघ है, अमूल्य है, लेकिन मृत्यु के भय से केवल श्मशान घाट जाते समय इस सत्य को स्वीकार करते हैं, बाकी समय में इसे छिपाने में ही दक्षता सिद्ध है। इस झूठे संसार में सत्य का रूप इतना ऊर्जावान है कि लोग उससे आंख मिलाने की शक्ति नहीं रखते, ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य के तीव्र प्रकाश को कोई देख ही नहीं पाता। राम का नाम सत्य वैसे ही है, जैसे मृत्यु अटल है। इसलिए मृत्यु के रहस्य को समझना ही कल्याणकारी है। जो व्यक्ति मृत्यु का सच नहीं जान पाया, उसका जीना यथार्थ नहीं।

डा. राघवेंद्र शुक्ल

ऊर्जा नीति में जैव ईंधन का भविष्य

जैवेंद्रराज सुथार

जीवाश्म ईंधन के नुकसान को देखते हुए सभी देश स्वच्छ ऊर्जा स्रोत को प्रोत्साहित करने की ओर ध्यान दे रहे हैं

प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर-जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में आम जनता में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही, इस दिन के माध्यम से जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत प्रयासों और योजनाओं पर भी प्रकाश डाला जाता है।

वस्तुतः जैव ईंधन एक तरल ईंधन है, जो जैविक साधनों जैसे कृषि अपशिष्ट, पेड़ पौधों और वनस्पति पदार्थों के माध्यम से व्युत्पन्न किया जाता है। यह पारंपरिक पेट्रोलियम पदार्थों की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होता है। अलग-अलग देश अपनी भौगोलिक परिस्थितियों और कृषि उपज के अनुसार अलग अलग कच्चे माल का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में स्विचग्रास और सोयाबीन जैसे कृषि उत्पादों का उपयोग जैव ईंधन निकालने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत, भारत में मुख्य रूप से मकई, गन्ना और रतनजोत के बीज का उपयोग होता है, क्योंकि ये फसलें भारतीय जलवायु और मिट्टी के अनुकूल हैं और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी हैं।

ऊर्जा मानव जाति और उसके सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। आज ऊर्जा संकट हमारे सामने आने वाले प्रमुख वैश्विक मुद्दों में से एक बनता जा रहा है। ईंधन इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जलाकर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और रोजमर्रा की जिंदगी के अधिकांश पहलू इसी पर आधारित हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस आज भी मुख्य ऊर्जा संसाधन बने हुए हैं। जीवाश्म ईंधन दुनिया की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं में लगभग 80 प्रतिशत का योगदान देते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में यह निर्भरता जीवाश्म ईंधन की एक मजबूत स्थिति की ओर इशारा करती है। पूरी दुनिया में ऊर्जा की खपत तेजी से बढ़ रही है। इस स्थिति में कहीं यह अमूल्य खजाना समाप्त न हो जाए, उससे पहले हमें वैकल्पिक ईंधन की समुचित व्यवस्था करनी होगी, ताकि मानव जीवन सुचारु रूप से चलता रहे। इस दिशा में सबसे बेहतर उपाय जैव ईंधन की अधिक से अधिक आपूर्ति सुनिश्चित करना है। जैव ईंधन भविष्य में ऊर्जा का सबसे आशाजनक विकल्प माना जा रहा है और यह भारत की समग्र ऊर्जा नीति का एक प्रमुख अंग भी बन चुका है।

पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में जैव ईंधन कई मायनों में अधिक परिणामकारक भी साबित हो रहे हैं। इस दिशा में भारतीय बिजानी लगातार जैव ईंधन के उपयोग के नए और उन्नत माडल विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। खनिज तेल के विकल्प के रूप में भारत सरकार भी एथेनाल और जैव डीजल जैसे स्रोतों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दे रही है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

awanishg30@gmail.com

सुधारनी होगी निर्माण की गुणवत्ता

संजय गुप्त ने 'दोयम दर्जे के निर्माण का सिलसिला' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में सार्वजनिक निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सड़क, पुल और अन्य आधारभूत परियोजनाएं विकास की पहचान हैं, लेकिन निर्माण के कुछ समय बाद ही उनमें दरार, धंसाव अथवा जलभराव जैसी समस्याएं सामने आएं तो यह केवल तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि निगरानी और जवाबदेही की कमजोरी का ही संकेत है। हालांकि, हर खराब निर्माण को भ्रष्टाचार का परिणाम मानना उचित नहीं होगा। मिट्टी की प्रकृति, जल-निकासी, अत्यधिक वर्षा, यातायात भार, डिजाइन और रखरखाव जैसी परिस्थितियां भी किसी परियोजना की टिकाऊ क्षमता प्रभावित करती हैं। फिर भी, बार-बार सामने आने वाली खामियों को अलग-अलग घटनाओं के बजाय संस्थागत समस्या के रूप में देखना होगा। समस्या का एक पक्ष ठेकेदारी व्यवस्था भी है, जहां कई बार परियोजना शीघ्र पूरी करने को गुणवत्ता से अधिक महत्व मिल जाता है। न्यूनतम लागत को प्राथमिक कसौटी बनाने के बजाय निर्माण की सामग्री की गुणवत्ता और दीर्घकालिक रखरखाव को निर्णय का आधार बनाया जाना चाहिए। तीसरे पक्ष से अनिवार्य परीक्षण, निर्माणस्थल की निगरानी और दोषपूर्ण कार्य पर दंड प्रभावी उपाय हो सकते हैं। सार्वजनिक धन से बनी परियोजना जनता की संपत्ति है। इसलिए विकास का मूल्यांकन केवल कितने किलोमीटर सड़क बनी, इससे नहीं, बल्कि वह कितने वर्षों तक सुरक्षित और उपयोगी रहती है, इससे होना चाहिए।

मेलबाक्स

पेपर लीक की समस्या पर लगाम

पिछले कई वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों में पेपर लीक की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। आज देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा हो, जो पेपर लीक की गंभीर बीमारी से अछूता हो। पिछले सात-आठ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में 70 से अधिक बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं पेपर लीक या अन्य धांधलियों के कारण रद या विवादित हुई हैं। इन परीक्षाओं से दो करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा हो, राजस्थान की शिक्षक भर्ती हो या केंद्रीय स्तर पर नीट और नेट जैसी परीक्षाएं- हर बार कहानी कमोबेश एक जैसी ही सामने आती है। एक तरफ गरीब और मध्यमवर्गीय माता-पिता कर्ज लेकर अपने बच्चों को कोचिंग हबों में भेजते हैं, कमरों का किराया भरते हैं और उनकी तैयारी पर अपनी वर्षों की जमा-पूंजी लगा देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लालच और व्यवस्था में सेंध लगाने की प्रवृत्ति कुछ ही घंटों में उनकी वर्षों की मेहनत को मिट्टी में मिला देती है। परीक्षा रद होने और फिर से आयोजित होने के इस चक्रव्यूह में विद्यार्थियों का समय, धन और मानसिक ऊर्जा लगातार नष्ट होती है। कई प्रतिभाशाली युवा अवसरों की तलाश में देश से बाहर जाने को विवश होते हैं, तो कई निराशा और अवसाद के दौर में पहुंच जाते हैं। संसद में कड़े कानून पारित कर देना या बड़ी-बड़ी समितियों का गठन कर देना इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। वास्तविक चुनौती कानून बनने से अधिक उसके प्रभावी क्रियान्वयन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की है। एनटीए जैसे शीर्ष परीक्षा नियामक संस्थानों की जवाबदेही स्पष्ट होनी चाहिए और व्यवस्था के भीतर मिलीभगत करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर और समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। प्रश्न पत्रों की छपाई, सुरक्षित परिवहन और भंडारण से लेकर परीक्षा केंद्रों पर निगरानी, रफ वर्क के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले कागज, विशेषज्ञों और कर्मचारियों की आवश्यक जांच तथा डिजिटल सुरक्षा तक हर स्तर पर निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। तकनीक का इस्तेमाल केवल परीक्षा आयोजित करने में नहीं, बल्कि प्रश्नपत्र की सुरक्षा और पूरी प्रक्रिया की निगरानी में भी बढ़ाना होगा। संबंधित एजेंसियों को इस संबंध में जवाबदेही तय करनी होगी।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एजीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4616500. E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

11 अरब रुपये से अधिक भारत ईरान के वाहपर पोर्ट के विकास में अब तक निवेश कर चुका है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

आजकल

ईरान-ओमान वार्ता में भारत के लिए अवसर

ईरान-ओमान की हालिया वार्ता से स्पष्ट हो रहा है कि पश्चिम एशिया में जल्द ही एक नया और संवेदनशील शिपिंग-मार्ग से जुड़ा भू-राजनीतिक विमर्श आकार लेने वाला है। ठीक इसी बीच सऊदी अरब पर समन्वित हमलों की आशंका भी निरंतर गहराती जा रही है, जिससे यह संकट टलने के बजाय और उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अनिश्चितता के बीच भारत निर्णयों की मेज से लगातार दूर, तटस्थ खड़ा दिखाई देता है। आने वाला समय यही तय करेगा कि भारत की यह नीति असली ताकत साबित होती है या केवल एक सुविधाजनक मजबूरी बनकर रह जाती है

प्रो. एम. एल. मीणा
विभागाध्यक्ष, भूगोल, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

भारत की ऊर्जा सुरक्षा कायम रखने में होर्मुज समुद्री मार्ग की संवेदनशीलता अपेक्षाकृत बढ़ गई है। फाइल

वर्ष 1973 के तेल संकट के दौरान जब अरब देशों ने पश्चिम पर तेल-प्रतिबंध लगाया था, तब भारत ने न तो कोई सैन्य पक्ष चुना और न ही किसी गठबंधन में शामिल होने का रास्ता अपनाया था। फिर भी भारत को उस प्रतिबंध की पूरी आर्थिक मार झेलनी पड़ी थी, क्योंकि तटस्थता तेल की कीमतों से कोई रियायत नहीं दिलवाती है। यह घटना भारत की विदेश-नीति के लिए एक स्थायी सबक बन गई थी। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि भू-राजनीतिक तटस्थता और आर्थिक सुरक्षा दो अलग-अलग चीजें होती हैं, और पहली दूसरी की कोई गारंटी नहीं देती। आज 50 साल बाद, ठीक वैसा ही सबक फिर एक बार सामने खड़ा है, बस इस बार भूगोल थोड़ा अलग है और किरदार भी बदले हुए हैं।

इस बार भारत का भूगोल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी मजबूरी, दोनों एक साथ बना हुआ है। भारत तीन व्यवस्था विकल्पों में इतनी गहराई से बंधा हुआ है कि किसी एक दिशा में झुकना उसके लिए व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव हो जाता है। इसमें एक तरफ खाड़ी देशों से आने वाला तेल, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ लगातार बढ़ती सामरिक साझेदारी, और तीसरी तरफ ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह जैसी दीर्घकालिक परियोजनाओं की असफलता और निवेश संकट हैं। शुरूआती तौर पर इस युद्ध के संदर्भ में भारत ने अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों की निंदा तो की, पर इस निंदा में उसने ईरान का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया था। यह भूराजनीतिक भाषाई सूक्ष्मता भारत की उस पुरानी कूटनीतिक शैली का स्पष्ट नमूना है जिसमें किसी भी पक्ष को सीधे कठघरे में खड़ा किए बिना, सिद्धांतों की तटस्थ भाषा में अपनी बात रखी जाती है। इसके बाद मार्च में ईरान के विदेश मंत्री ने यह घोषणा की कि ईरान भारत, चीन और रूस जैसे मित्र देशों को होर्मुज जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दे रहा है।

यहाँ यह बात समझना बहुत जरूरी है कि भारत की तटस्थता को ईरान ने अपने एक कूटनीतिक अवसर के रूप में भी इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि भारत को गुजरने देना ईरान के लिए दुनिया को यह दिखाने का एक जरिया था कि वह अमेरिका के सहयोगियों और गैर-सहयोगियों में स्पष्ट फर्क कर सकता है। इस तरह भारत उस संकेत का लाभार्थी तो बना, पर इस रियायत को पूरी तरह भारत की अपनी कूटनीतिक जीत मान लेना भी अधूरा आयाम होगा। क्योंकि यह उतना ही ईरान के अपने व्यापक प्रचार-लक्ष्य से भी प्रेरित था, जितना भारत के अपने प्रयासों से था। यह दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं कि भारत के प्रयास प्रभावी थे, और साथ ही ईरान का अपना स्वार्थ भी उसी दिशा में काम कर रहा था।

इसी बीच ईरानी जहाज आइआरआइएस देना, जो भारतीय नौसेना के साथ हुई एक अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा से लौट रहा था, श्रीलंका के गाले तट के पास, भारत की अपनी समुद्री सीमा से निकट अमेरिकी सेना द्वारा डुबो दिया गया। और इसमें भारत की प्रतिक्रिया एक औपचारिक बयान से आगे नहीं बढ़ पाई थी।

अब स्थिति एक नए और महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। ईरान और ओमान के बीच होर्मुज में सुरक्षित शिपिंग मार्गों को लेकर बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है, और दोनों पक्ष मार्ग-निर्देशकों पर सहमत भी हो चुके हैं। हालांकि ईरान का लक्ष्य लगभग तीन महीने की एक अस्थायी व्यवस्था स्थापित करना है। यहीं वह तथ्य सामने आता है जिसे भारत की नीति के मूल्यांकन में जरूर शामिल करना चाहिए कि जिस असली और बाध्यकारी समझौते पर होर्मुज का निकट भविष्य टिका हुआ है, वह तो ईरान और ओमान के बीच हो रहा है। और भारत इस मेज पर मौजूद ही नहीं है। इसकी वजह भारत की किसी कमी में उतनी नहीं जितनी भूगोल में है, क्योंकि ओमान इस जलमार्ग का सह-मालिक है।

यह तथ्य भारत की विदेश नीति में एक निर्णायक भूराजनीतिक आयाम छोड़ता है। यह आयाम यह जरूर स्पष्ट कर देता है कि संवाद की क्षमता और परिणाम तय करने का सामर्थ्य दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। और भारत के पास फिलहाल पहली क्षमता प्रचुर मात्रा में है, जबकि दूसरी अभी सीमित ही बना हुआ है। यह ठीक वैसा ही फर्क है जो 1973 के तेल संकट में भी सामने आया था, जब भारत हर मंच पर अपनी आवाज तो उठा सकता था। लेकिन तेल की कीमत और आपूर्ति तय करने वाली असली सौदेबाजी की मेज पर उसकी कोई सीधी भूमिका नहीं थी। आज भी यह संरचनात्मक सच्चाई मूलतः वैसी ही बनी हुई है, भले ही भारत की कूटनीतिक कुशलता और उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा, दोनों उस दौर से कहीं आगे बढ़ चुकी हों। आगे की दिशा में देखा जाए, तो भारत की इस नीति का मूल्यांकन दो कसौटियों पर होना चाहिए। पहली कसौटी यह है कि क्या भारत ने अपने तात्कालिक और व्यावहारिक हितों की रक्षा की, और इस कसौटी पर भारत का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से संतोषजनक रहा है। क्योंकि टैंकरों की आंशिक सुरक्षित निकासी और ऊर्जा-आपूर्ति की निरंतरता इसका प्रमाण हैं। दूसरी कसौटी यह है कि क्या भारत ने इस संकट के दौरान अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता को भी मजबूत किया है, यानी क्या वह अगली बार ऐसा संकट आने पर केवल संवाद करने वाला देश बना रहेगा, या उस मेज पर बैठने की स्थिति में भी होगा जहां फैसले लिए जाते हैं।

अंततः भारत की सधी हुई संतुलन दिशा न तो पूर्ण विजय है और न ही पूर्ण असफलता है। यह उस बीच की वास्तविकता है जिसमें एक उभरती हुई शक्ति की वास्तविक सीमाएं और उसकी वास्तविक उपलब्धियां, दोनों एक साथ मौजूद हैं। भारत ने इस युद्ध के दौरान यह साबित किया कि संवाद, सही ढंग से इस्तेमाल किए जाने पर, ठोस व्यावहारिक परिणाम दे सकता था, परंतु उसने यह भी उजागर किया कि संवाद अकेले किसी देश को निर्णायक शक्ति की उस मेज तक नहीं पहुंचा सकता जहां असली फैसले लिए जाते हैं। भारत की आने वाली कूटनीति की असली परीक्षा यही तय करेगी कि क्या वह इस फर्क को समय रहते पहचानकर उसे पाटने की दिशा में आगे बढ़ता है, या फिर वह इसी सुविधाजनक संतुलन में संतुष्ट होकर रुक जाता है।

समुद्री खजाने से ऊर्जा सुरक्षा की राह आसान

रंजना मिश्रा

भारत सरकार द्वारा देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और इस मामले में विदेशी निर्भरता कम करने एवं समुद्र के भीतर छिपे बेशकीमती खजानों को बाहर निकालने के लिए लगभग 84,084 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'समुद्र-मंथन' नाम की एक बहुत बड़ी योजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। यह योजना साल 2030-31 तक चलेगी। जिस तरह पुरानी कहानियों में समुद्र मंथन से कई अमूल्य चीजें निकली थीं, ठीक उसी तरह हमारी इस आधुनिक योजना का मकसद भी समुद्र की अथाह गहराइयों में दबे तेल, गैस और खनिजों को ढूंढकर देश को मजबूत बनाना है। इस महत्वाकांक्षी योजना का एक प्रमुख और स्पष्ट लक्ष्य देश के हाइड्रोकार्बन (तेल और प्राकृतिक गैस) भंडार में वृद्धि करना है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी। भारत के पास लंबी तटरेखा और पानी का बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन अब तक हम इस प्राकृतिक ताकत का पूरा फायदा नहीं उठा पाए थे।

वस्तुतः भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक ऐसा देश है जिसके पास लंबी तटरेखा और पानी का बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन अब तक हम इस प्राकृतिक ताकत का पूरा फायदा नहीं उठा पाए थे। हम अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा और जरूरी ईंधन दूसरे देशों से खरीदते हैं, जिससे बाहर के देशों में होने वाले तनाव या दाम बढ़ने का सीधा असर हमारी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसी परेशानी से बचने और खुद को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने इस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका मुख्य काम समुद्र के गहरे पानी में छिपे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों का सही पता लगाना है।

इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों, आधुनिक जहाजों और विज्ञान की नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। विज्ञानी समुद्र की तलहटी का बारीक अध्ययन करेंगे और यह पता लगाएंगे कि कहां पर कौन सा ईंधन या खनिज मौजूद है। यह योजना सिर्फ तेल और गैस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की नीली अर्थव्यवस्था को भी तेजी से आगे बढ़ाएगी।

जब समुद्र के भीतर इन चीजों की खोज का काम तेज होगा तो हमारे देश के युवाओं, इंजीनियरों और विज्ञानियों के लिए नौकरी के ढेरों नए मौके बनेंगे। इसके साथ ही, समुद्र से जुड़े साजो-सामान, जहाजों और बंदरगाहों के आसपास के कामों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे तटीय इलाकों का विकास तेजी से होगा। हमारे देश के जो तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरे भाई हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी इस योजना में कई अच्छी बातें जोड़ी गई हैं। उन्हें मछली पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीक, मौसम की सही जानकारी देने वाले यंत्र और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वे गहरे समुद्र में सुरक्षित रहकर ज्यादा मछली पकड़ सकें और उनकी आमदनी बढ़ सके। इसके अलावा, समुद्र के किनारे घूमने-फिरने की जगहों को और सुंदर बनाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आ सकें और स्थानीय लोगों का व्यापार फले-फूले।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खरी-खरी

विज्ञापन का कमाल

सुदर्शन कुमार सोनी

अभी तक इस देश में सिटीजन, नेटिजन, मतदाता, करदाता और उपभोक्ता हुआ करते थे। अब विज्ञापनों ने एक नई जाति पैदा कर दी है- सिपिजन। टीवी पर एक सज्जन दूसरे से पूछते हैं- "आप सिपिजन हुए कि नहीं?" सामने वाला घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं सरकार ने नागरिकता का कोई नया पैमाना तो लागू नहीं कर दिया। वैसे भी आजकल पासपोर्ट से नागरिकता सिद्ध नहीं होती, तो कहीं सिप न करने से नागरिकता भी संदेह के घेरे में न आ जाए! यही तो आज के विज्ञापन का कमाल है। वह आपको कोई उत्पाद नहीं बेचता, पहले यह डर बेचता है कि कहीं आप उस भीड़ का हिस्सा बनने से चूक न जाएं, जिसमें बाकी सब शामिल हो चुके हैं। पहले हीनभावना पैदा करो, फिर उसका इलाज बेचो। विज्ञापन देखकर लगता है कि आज की सबसे बड़ी उपलब्धि आइएएस, आइपीएस, पद्मश्री या पद्मविभूषण नहीं, बल्कि सिपिजन बनना है। कल तक पूछा जाता था, "बेटा, क्या करते हो?" अब पूछा जाएगा, "बेटा, सिप करते हो?"

गंगाधर को डर है कि जल्दी ही एयरपोर्ट पर तीन कतारें होंगी- एक सामान्य यात्रियों की, दूसरी डिजीयात्रा वालों की और तीसरी सिपिजनों की। लाउंज में प्रवेश केवल नियमित सिप वालों को मिलेगा। अस्पताल में लिखा होगा- पहले सिपिजन मरीज, फिर बाकी मरीज।

फिर ज्ञान दिया जाता है- मार्केट गिर रहा है? बहुत बढ़िया, और खरीदिए। मार्केट चढ़ रहा है? तब भी खरीदिए। महंगा है? खरीदिए। सस्ता है? खरीदिए। अंत में महाबाक्य सुनाया जाता है- औसत हो जाएगा। यह "औसत" शब्द भारतीय निवेशक के लिए वैसा ही है, जैसा सरकारी प्रेस नोट में- "कड़ी जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" दोनों सुनकर आदमी श्वस्त हो जाता है।

सबसे सुंदर उपदेश यह है कि सिप कभी बंद मत करो। इसे आदत बना लो। जैसे हर महीने बिजली का बिल कटता है, वैसे ही बैंक खाते से सिप कटती रहे। धीरे-धीरे दर्द भी स्वचालित कटौती की तरह सामान्य लगने लगेगा। अब जो सिप नहीं करता, वह स्वयं को आर्थिक रूप से अशिक्षित समझने लगा है। विज्ञापनों की दुनिया भी कमाल की है।

पोस्ट

मोदी सरकार एफसीआरए को और सख्त बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि विदेशी फंड के दुरुपयोग पर रोक लग सके और भारत विरोधी गतिविधियों और तरकक्षी में बाधा डालने की कोशिश करने वालों पर शिकंजा कसा जाए। कांग्रेस इसे दमनकारी बता रही है, पर दिलचस्प बात यह है कि यह कानून कांग्रेस ही लेकर आई थी और उसने इसमें कई बदलाव भी किए।

हार्दिक भदसार@Bitt2DA

हर व्यक्ति या राष्ट्र की यात्रा में एक बिंदु आता है जब तर्क, नैतिकता या सही-गलत को लेकर किसी बहस के लिए स्थान नहीं रहता। भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में एफसीआरए में बदलाव का प्रस्ताव ऐसे ही एक बिंदु पर आया है।

शिव मिश्रा@shivkmishr

यूपीआइ पर चार्ज लगने की खबर लगभग हर साल उछली है। इसमें अलग-अलग चीजों- एमडीआर, जीएसटी और आम यूजर से लिए जाने वाले शुल्क को एक ही बात की तरह पेश किया जाता है और फिर भ्रम की स्थिति बनती है। इस भ्रम के लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो समय रहते संवाद न कर विवाद को हवा देते हैं।

नवनीत मिश्रा@navneetmishra99

जागरण जनमत

कल का परिणाम

पंजाब में भाजपा व अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ने से सत्ता वापसी संभव है?

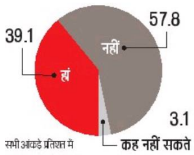

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या मानसून सत्र के बचे हिस्से में सरकार अपना विधायी एजेंडा आगे बढ़ाने में सफल होती दिख रही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

बरखा ऋतु में बरसता ज्यों 'हथिया' नक्षत्र,
बिल्कुल वैसा जायगा मानसून का सत्र।
मानसून का सत्र संभाला टोपी-अंचरा,
चमक-दमक के साथ खूब बरसेंगे बदरा!
परिसीमन बिल लाय घुमाएं मोदी चरखा,
होगी उसके बाद खूब सीटों की बरखा!!

-ओम प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश डायरी

पीडीए में 'पंडित', चुनावी बजट व दस्तक जेन-जी की

अजय जायसवाल
उप राजनीतिक संपादक, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव अभी कुछ माह दूर है, लेकिन सियासत का तापमान बढ़ चला है। पिछले दिनों प्रदेश की राजनीति में जो घटनाक्रम सामने आए, उनमें एक बात यह समान दिखी कि हर मुद्दे का सिरा वर्ष 2027 के विधान सभा चुनाव से सीधे जुड़ रहा है। दिल्ली के जंतर-मंतर से उठी जेन-जी की आवाज को लेकर दलों की सक्रियता हो, सपा मुखिया अखिलेश यादव का पीडीए में 'पीडी' को 'पंडित' का शार्ट फार्म बताना हो या फिर योगी आदित्यनाथ सरकार का 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट, सभी के पीछे सामाजिक समीकरण और हर तरह के मतदाता समूहों को साधने की कोशिश साफ दिखती है। इनको जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ है, सियासी दल अब केवल अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने की जगह नए सामाजिक और पीढ़ीगत समूहों तक पहुंच बनाने में जुट गए हैं। इनमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय-राजनीतिक संकेत जेन-जी आंदोलन रहा। लखनऊ और प्रयागराज तक पहुंचा युवाओं का आंदोलन किसी एक पार्टी के झंडे तले नहीं चला। आंदोलन से निकला सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि धर्म और जाति से पहले परीक्षा और रोजगार की बात। यही बात राज्य के अगले विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं का बड़ा वर्ग प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ और आगरा जैसे बड़े शहरों में है। इनका प्रभाव केवल छात्र तक सीमित नहीं रहता, उनके पीछे परिवार का आर्थिक और भावनात्मक निवेश भी है, इसलिए पेपर लीक, किसी छात्र से आगे बढ़कर पूरे परिवार का मुद्दा बना है।

अपनी मांगों के समर्थन में प्रयागराज में प्रदर्शन करते छात्र। फाइल

प्रदेश में जेन-जी की हिस्सेदारी कम नहीं है, इसलिए चुनाव में इनकी भूमिका कई सीटों पर निर्णायक हो सकती है। राजनीतिक दलों के लिए चुनौती इसलिए ज्यादा है, क्योंकि इसे पारंपरिक 'वोट बैंक' की तरह नहीं देखा जा सकता।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इस मुद्दे पर मुखरता और प्रयागराज में संपन्न छात्र संवाद, साफ संकेत है कि कांग्रेस वर्ष 2027 के लिए ऐसे मुद्दों की जमीन भी तैयार कर रही है। ऐसे में सत्ताधारी भाजपा के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे अपने विकास और रोजगार के दावों को युवाओं तक पहुंचाना है, दूसरी तरफ परीक्षा और भर्ती से जुड़े असंतोष को राजनीतिक आंदोलन में बदलने से रोकना है।

सरकार इस कोशिश में जुट भी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के युवा संवाद के साथ ही योगी सरकार युवाओं के लिए आयोग बनाने की तैयारी में है। बजट में भी युवाओं का ध्यान रखते हुए मंत्री से लेकर संगठन के पदाधिकारी और जिलों के अधिकारियों द्वारा खासतौर से युवाओं से संवाद किया जा रहा है। दूसरी तरफ, अखिलेश ने 'पीडीए' को पंडित से जोड़कर राजनीति को नया मोड़ दिया। लोक सभा चुनाव में पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के सामाजिक समीकरण से सफलता पाई, लेकिन विधानसभा की लड़ाई में पार्टी को एहसास है कि केवल पीडीए के सहारे सत्ता पाना आसान नहीं। लिहाजा अब पीडीए की छतरी के नीचे ब्राह्मण समेत दूसरे सामाजिक समूहों को जोड़ने की कोशिश है। भाजपा ने सपा के पुराने कार्यकाल और ब्राह्मणों से जुड़े सवाल उठाकर पलटवार किया, तो बसपा ने भी सपा पर निशाना साधा। यानी एक बयान भाजपा और बसपा को भी अपने-अपने सामाजिक आधार को सक्रिय करने का अवसर दे गया।

इस बीच चार अगस्त को मानसून सत्र में योगी सरकार ने अब तक के सबसे बड़े 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक के अनुपूरक बजट के जरिये ऐसे क्षेत्रों को छुआ, जिनका चुनावी असर संभव है। सत्र के दौरान सपा, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को उठाकर सरकार को घेरने में जुटी रही। योगी आदित्यनाथ ने सपा के विरोध को युवाओं, किसानों और गरीबों के मुद्दों पर चर्चा से बचने की कोशिश बताया।

तीनों घटनाक्रमों से वर्ष 2027 की चुनावी कहानी के तीन अध्याय अभी से दिख रहे हैं- सामाजिक समीकरण, सरकारी डिलीवरी और युवा असंतोष। सपा पीडीए की छतरी बड़ी करना चाहती है, तो बसपा दो दशक पुरानी सोशल इंजीनियरिंग। भाजपा, सरकार के काम और अपने व्यापक सामाजिक गठबंधन की चुनावी पूंजी में बदलने की तैयारी में है। कांग्रेस के सामने इन दोनों ध्रुवों के बीच अपना स्थान बनाने की चुनौती है और इन सबके बीच जेन-जी का सवाल सबसे अलग है। यह पीढ़ी पूछ रही है, हमारे भविष्य की गारंटी कौन देगा? साफ है कि अगला चुनाव जातियों के साथ पीढ़ियों को जोड़ने वाला भी होगा।

छत्तीसगढ़ डायरी

सावन में शिवलिंग पर विवाद

सतीश चंद्र श्रीवास्तव
संपादकीय प्रभारी, रायपुर

सावन के महीने में देवाधिदेव महादेव भोले शिवशंकर नाथ का नाम भक्तों के सिर चढ़कर बोल रहा है। प्रदेश के सभी शिवालयों में विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। श्रद्धालु सामर्थ्य के अनुसार रुद्राभिषेक और प्रसाद वितरण में जुटे हैं। ट्रेनें देवघर जाने वालों से खचाखच भरी हुई हैं। इसी बीच आभासी दुनिया में 'शिवलिंग' पर टिप्पणी से हलचल मची हुई है। डिजिटल प्लेटफार्म पर भगवान शिव के विरुद्ध टिप्पणी करने के आरोप में छत्तीसगढ़ क्रिश्चन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल गिरफ्तार किए गए हैं और 21 अगस्त तक के लिए फिलहाज जेल भेजे जा चुके हैं। राजनेताओं के इसमें कूदने से प्रकरण और पेचीदा हो गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार की रात प्रदर्शन किया तो कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों पर अराजकता फैलाने से लेकर जातीय आधार पर समाज को बांटने तक के आरोप जड़ दिए हैं।

कांग्रेसियों और ईसाई संगठनों ने पन्नालाल के प्रति सहानुभूति जताते हुए उनके 75 वर्ष की उम्र की विशेष चर्चा की है। प्रदेश की भाजपा सरकार पर आग में घी डालने तथा वातावरण खराब करने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और असम के सह प्रभारी हैं।

इन सबके बीच 43 हजार फालोअरों (अनुसरणकर्ताओं) वाला वह व्यक्ति गायब है जिसके फेसबुक पोस्ट पर हंगामा चल रहा है। हंसराज गोयल नाम से व्यक्ति ने पोस्ट किया, 'शिव का लिंग ही क्यों पूजते हैं।' साथ ही उक्त व्यक्ति ने आपत्तिजनक सवाल खड़ा किया, अन्य देवताओं, राम, कृष्ण, हनुमान, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और गणेश के .... में क्या खराबी है? डा. भीमराव आंबेडकर और वेंकटप्पा रामास्वामी पेरियार की तस्वीरों वाले फेसबुक पेज के संचालक हंसराज तक अभी तक पुलिस पहुंच सकी है, न बजरंगी। उक्त पेज पर भड़काऊ पोस्ट जारी लगातार हैं। इस प्रकरण में एफआइआर दर्ज कराने वाले भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने संदेह जताया है कि माहौल खराब करने के लिए छद्म नाम का प्रयोग हो रहा है। फेसबुक की भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। चिंता का विषय है कि डिजिटल प्लेटफार्म के यह 'टूल किट' कभी भी लोगों की भावना भड़का सकते हैं। जांच में स्पष्ट होगा कि क्या भावनाओं की परीक्षा का अंतरराष्ट्रीय संबंध भी है। ठोस व्यवस्था के बिना सत्ता के लिए इस चुनौती से निपटना आसान नहीं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं शिव के भक्त हैं। जशपुर के मधेश्वर महादेव को विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की मान्यता दिलाने के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। पन्नालाल की गिरफ्तारी के बाद उनका दोटूक बयान रहा कि भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। वैसे प्रदेश में हजारों वर्ष पुराने शिवालयों में अनवरत अभिषेक हो रहा है। गरियाबंद का भूतेश्वरनाथ महादेव लगातार आकार बढ़ने के कारण आकर्षण का केंद्र है तो कबीरधाम में नागवंशी राजाओं द्वारा सातवीं से 11वीं शताब्दी में निर्मित सात पहाड़ों से घिरा भोरमदेव मंदिर श्रद्धा का केंद्र है। छठी शताब्दी के दौरान स्थापित बस्तर के कोंडागांव का गोबरहीन शिव मंदिर, बारसूर का बत्तीसा और चंद्रादित्य मंदिर और जांजगीर चांपा का लक्ष्मणेश्वर मंदिर उन इतिहासकारों को भी झुठला रहे हैं जो क्षेत्र की अलग परंपरा की बात करते हुए समाज को बांटते रहे हैं।

इसी मंथन में संत कबीर दास की वाणी को भी याद किया जा सकता है, 'निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय।' समय के अनुसार इसमें बदलाव की अनुमति हो तो दूसरे हिस्सा कुछ ऐसा भी कहा जा सकता है :

कवर्धा के भोरमदेव मंदिर में श्रद्धालु। फाइल

'निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, सोए पड़े समाज को, पल में दियो जगाय।''

उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले सप्ताह में उस अदृश्य हंसराज गोयल की तलाश कर ली जाएगी जो भावनाएं भड़काने की साजिश रच रहा है। वैसे शिवलिंग के साथ 'खतना' शब्द का प्रयोग करने वाला अरुण पन्नालाल पहले भी मतांतरण के मामलों विवाद में रहा है। उसकी फाइल खुली तो पूरे प्रदेश में फैला मतांतरण जाल सार्वजनिक होगा। बस्तर और जशपुर में पहले ही बड़े बड़े बोर्ड लग चुके हैं 'पादरी और पास्टर गांव में नहीं आ सकते'।

चार कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.43 लाख करोड़ रुपये बढ़ा

नई दिल्ली: बीते सप्ताह बीएसई में सूचीबद्ध शीर्ष-10 में से चार कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 1.43 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी रही है। इस दौरान एसबीआइ के पूंजीकरण में सबसे ज्यादा 63,922.03 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और लार्सन एंड टूब्रो का पूंजीकरण भी बढ़ा है। दूसरी ओर, एलआइसी, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, भारती एयरटेल और हिंदुस्तान यूनीलिवर के पूंजीकरण में गिरावट आई है। (प्रेट्र)

केंद्र और राज्य सरकारों से सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने और व्यापार को आसान बनाने के प्रयासों में वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- आरसी भार्गव, चेयरमैन, मारुति सुजुकी इंडिया

केवल वेतन के आधार पर ही लोन नहीं देते हैं बैंक

अधिकांश नौकरीपेशा लोगों को अपने जीवन में लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे लोग मानते हैं कि उन्हें बैंक से उनके वेतन के आधार पर आसानी से कम ब्याज दर पर लोन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बैंक केवल किसी भी नौकरीपेशा व्यक्ति को उसके वेतन के आधार पर ही लोन नहीं देते हैं, बल्कि वे कई अन्य कारकों की जांच भी करते हैं। इन सभी कारकों की जांच के बाद ही बैंक की ओर से लोन दिया जाता है। **मनोज कुमार** बता रहे हैं बैंक की ओर से लोन के लिए जांचे जाने वाले अन्य कारकों के बारे में...

क्रेडिट स्कोर

लोन देने के लिए बैंक आवेदक के वेतन के अलावा जो सबसे जरूरी चीज देखते हैं, वो है लोन चुकाने का रिकार्ड। यदि किसी व्यक्ति ने प्रत्येक मासिक किस्त और क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर चुकाया है तो उसे आमतौर पर कम जोखिम वाला माना जाता है। इससे उस व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है और उसके बेहतर लोन आफर, ज्यादा लोन राशि या कम ब्याज दर पर लोन मिलने की संभावना ज्यादा होती है। बैंक और लोन देने वाली दूसरी संस्थाएं ग्राहकों के लोन, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट हिस्ट्री, बकाया राशि और डिफाल्ट की जानकारी सिबिल, इक्वाफिक्स और सीआरआइएफ हाई मार्क जैसे क्रेडिट ब्यूरो को देती हैं। इन रिकार्ड्स

का इस्तेमाल आपके क्रेडिट स्कोर की गणना के लिए किया जाता है जो 300 से 900 के बीच होता है। कोई भी व्यक्ति सिबिल की आधिकारिक वेबसाइट और ऐसे ही दूसरे प्लेटफार्म के जरिये अपना सिबिल या क्रेडिट स्कोर जांच सकता है। इसलिए, लोन के लिए आवेदन करने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर जरूर देखें ताकि पता चल सके कि आपकी वित्तीय प्रोफाइल कैसी है।

मौजूदा ईएमआइ

यदि आप किसी मौजूदा लोन के लिए मासिक किस्त यानी ईएमआइ चुका रहे हैं तो इसका नए लोन आवेदन पर काफी असर पड़ सकता है, भले ही कागजों पर आपका वेतन अच्छा-खासा दिख रहा है। बैंक आमतौर पर सिर्फ यह नहीं देखते कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह भी देखते हैं कि उस कमाई का कितना हिस्सा पहले से दूसरे लोन चुकाने में जा रहा है। मान लीजिए- अगर किसी व्यक्ति का वेतन 60 हजार रुपये महीना है और वह पहले से ही मौजूदा लोन की किस्त के रूप में 20 हजार रुपये चुका रहा है, तो बैंक यह मान सकता है कि उस व्यक्ति के पास एक और ईएमआइ को आसानी से संभालने की गुंजाइश कम है।

नौकरी में स्थिरता

व्यक्तिगत लोन के मामले में बैंक नौकरी में स्थिरता को भी एक अहम बात मानते हैं। बैंक देखते हैं कि लोन के लिए आवेदन करने वाले का इतिहास कैसा है। इससे पता चलता है कि आवेदक की आय कितनी स्थिर और अनुमानित है। बार-बार नौकरी बदलने वाली की तुलना में कई वर्षों से एक ही कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को आर्थिक रूप से ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। इसी प्रकार, सरकारी कर्मचारियों को उनकी सुरक्षित नौकरी के कारण बहुत स्थिर माना जाता है। मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वालों को उनके व्यवस्थित पेमेंट साइकिल के कारण प्राथमिकता दी जाती है।

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल

क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का अनुपात भी लोन को मंजूरी देने के लिए एक जरूरी पैमाना है। बैंक और वित्तीय संस्थान लोन के आवेदन की जांच करते समय आवेदक के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल पर भी ध्यान देते हैं। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का अनुपात ज्यादा होने पर लोन मंजूर होने की संभावना कम हो जाती है। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का अनुमाप आपके पास मौजूद कुल क्रेडिट के मुकाबले देखा जाता है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल का अनुपात कम बनाए रखने से न सिर्फ क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है, बल्कि यह जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार का भी संकेत देता है। इससे व्यक्तिगत लोन और नए क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी योग्यता बढ़ती है। साथ ही बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज दर पर लोन पाने में भी मदद मिलती है। **जागरण इन्फो**

₹7,400 करोड़ जुटाने के लिए इस सप्ताह खुलेंगे पांच आइपीओ

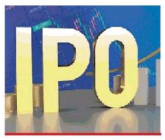

- पांचों कंपनियों ने 10 से 14 अगस्त तक मांगे आवेदन
- कारोबार विस्तार, कर्ज निपटान पर खर्च का जाएगी यह राशि

नई दिल्ली, प्रेट्र: इस सप्ताह पांच आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) सब्सक्रिप्शन खुलेंगे। इसमें आठो उपकरण निर्माता धूत ट्रांसमिशन, शिपराकेट, मिल्की मिस्ट डेयरी फूड, मोलबायो डायग्नोस्टिक्स और बिहारी लाल इंजीनियरिंग के आइपीओ शामिल हैं। यह पांचों कंपनियां आइपीओ के जरिये संयुक्त रूप से 7,400 करोड़ रुपये जुटाएंगी।

प्वाइंट-आफ-केयर डायग्नोस्टिक्स फर्म मोलबायो डायग्नोस्टिक्स और धूत ट्रांसमिशन के आइपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 10-12 अगस्त तक खुलेंगे। इसके बाद मिल्की मिस्ट डेयरी फूड का आइपीओ 11-13 अगस्त तक खुलेगा। इसी तरह, शिपराकेट और इंजीनियरिंग कास्टिंग व अलाय स्टील उत्पाद निर्माता बिहारी लाल इंजीनियरिंग का आइपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 12-14 अगस्त तक खुलेगा। ऐसे में प्राथमिक बाजार के लिए यह एक व्यस्त सप्ताह रहेगा। आइपीओ से मिलने वाली राशि का अधिकांश हिस्सा कारोबार विस्तार, पूंजीगत खर्च, कर्ज निपटान और अन्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए होगा।

धूत ट्रांसमिशन ने अपने 3,067 करोड़ रुपये के आइपीओ का शेयर मूल्य 829-871 रुपये प्रति इकाई तय किया है। इस आइपीओ में 1,400 करोड़ रुपये तक के नए शेयर 1.91 करोड़ प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। इसी तरह, मोलबायो डायग्नोस्टिक्स के 940 करोड़ रुपये के आइपीओ का शेयर मूल्य 768-807 रुपये है। इसमें 200 करोड़ रुपये तक के नए शेयर और 91.66 लाख प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। मिल्की मिस्ट 1,553 करोड़ रुपये के आइपीओ के 133-140 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर लांच करेगी। इसमें 1,428 करोड़ रुपये तक के नए शेयर और 125 करोड़ रुपये के प्रमोटर शेयर शामिल हैं।

शिपराकेट ने अपने 1,617.5 करोड़ रुपये के आइपीओ के लिए शेयर मूल्य 92-97 रुपये प्रति इकाई तय किया है। इसमें 885.50 करोड़ रुपये तक के नए शेयर और 732 करोड़ रुपये के मौजूदा शेयरधारकों के शेयर शामिल हैं। बिहारी लाल इंजीनियरिंग के आइपीओ का आकार 302 करोड़ रुपये और शेयर मूल्य 271-285 रुपये प्रति इकाई है।

आइपीओ का आकार

धूत ट्रांसमिशन	3,067
मोलबायो डायग्नो.	940
मिल्की मिस्ट	1,553
शिपराकेट	1,617.5
बिहारी लाल इंजी.	302

(नोट: राशि करोड़ रुपये में)

नौ कंपनियों को आइपीओ लाने की मिली मंजूरी

कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी से नौ कंपनियों को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) लाने की मंजूरी मिल गई है। इसमें प्लेसिपल गेम्स्, ज़ेन स्टार्टअप गरुड़ा एयरोस्पेस, रेक्लिफ़ डाट काम इंडिया प्रमुख हैं। सेबी के ताजा अपडेट के अनुसार, आइपीओ लाने की मंजूरी पाने वाली अन्य कंपनियों में जैकसन ग्रीन, एज़ायट इंडस्ट्रीज, एक्सप्रेसन 360 सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, एसएनवीए ट्रेवलटेक, नैनी पेपर्स लिमिटेड, रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लैवसो शामिल हैं।

एफपीआइ ने पहले सप्ताह में 12,921 करोड़ के शेयर खरीदे

नई दिल्ली, प्रेट्र: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने भारतीय शेयरों में अपनी खरीदारी जारी रखी है और अगस्त के पहले सप्ताह में 12,921 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह बेहतर व्यापक आर्थिक स्थितियों, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और स्थिर रुपये के कारण संभव हुआ है।

इससे पहले जुलाई 2026 में एफपीआइ ने 20,200 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था, जो चार महीनों की भारी बिक्री के बाद एक सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है। हालांकि, हालिया खरीदारी के बावजूद विदेशी निवेशक कैलेंडर वर्ष 2026 में भारतीय शेयरों में शुद्ध विक्रेता बने हुए हैं और अब तक 2.41 लाख करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं।

यह 2025 में की 1.66 लाख करोड़ रुपये की निकासी से अधिक है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया प्रवाह निवेशक भावना में सुधार को दर्शाता है।

डाटा से खिलवाड़ नहीं कर सकेंगी बीमा कंपनियां

इरडा ने बीमा उत्पादों की तुलना के दौरान कंपनियों के ग्राहकों से विस्तृत डाटा लेने पर रोक लगाई

- डीपीडीपी कानून पूर्ण रूप से लागू होने पर लेनी होगी ग्राहकों की अनुमति
- मिस-सेलिंग रोकने के लिए बिक्री एजेंटों की जानकारी को जरूरी बनाया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: डिजिटल प्लेटफार्म पर बीमा उत्पादों की तुलना के दौरान कंपनियां तभी कोई भी जानकारी मुहैया कराती हैं जब आप उन्हें अपना विस्तृत ब्योरा देते हैं। पहले कंपनियां आपकी उम्र, फोन नंबर, ई-मेल आइडी जैसी कई महत्वपूर्ण जानकारी कंपनियां ले लेती है। इसके बाद बताती है कि कौन से बीमा उत्पाद को खरीदने के लिए कितना प्रीमियम देना होगा या कितने का इंश्योरेंस होगा। लेकिन अब इन कंपनियों को इस प्रकार से ग्राहकों का डाटा लेना बंद करने के लिए कहा गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) की तरफ से इन कंपनियों को साफ तौर पर कहा गया है कि वे ग्राहकों को जानकारी देने के बदले इस प्रकार से उनका डाटा लेना बंद करें।

बीमा उत्पादों की डिजिटल रूप से तुलना करने के लिए ग्राहक अपनी सारी जानकारी दे देता है और फिर उन्हें कंपनियों की तरफ से अनचाहे काल का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि अन्य संस्थानों को उन डाटा को बेच दिया जाता है। इरडा ने कंपनियों से कहा है कि वे इस प्रकार का डाटा लिए बगैर ही ग्राहकों की जानकारी मुहैया कराएं। हालांकि, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कानून के पूर्ण रूप से लागू होने पर कंपनियां ग्राहकों के डाटा का बिना उनकी इजाजत के इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। डीपीडीपी एक्ट को पिछले साल नवंबर में आंशिक रूप से लागू किया गया और अगले साल मध्य तक यह कानून पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। इस साल नवंबर से कंपनियों को किसी व्यक्ति का डाटा लेने व उसके इस्तेमाल के लिए कंसेंट (सहमति) मैनेजर रखना होगा। जानकारों का कहना है कि इस प्रकार से डाटा लेने का काम शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के दौरान भी किया जाता है।

इरडा ग्राहकों को बीमा उत्पादों की मिस-सेलिंग (गलत दावों के साथ बिक्री) को भी लेकर गंभीर है। इरडा के नए नियम के मुताबिक, बीमा उत्पाद के प्रति जिम्मेदारी तय करने के लिए अब कंपनियों को हरेक उत्पाद के साथ उस पालिसी का प्रस्ताव देने वाले व बिक्री करने वाले वाले बिक्री एजेंट की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसका फायदा यह होगा कि ग्राहक अगर बाद में उस उत्पाद को मिस-सेलिंग करार देता है तो यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि किस एजेंट ने ग्राहक को गुमराह किया। हालांकि, बीमा जानकारों का कहना है कि सिर्फ यह जान लेने से काम नहीं चलेगा कि मिस-सेलिंग के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, बल्कि मिस-सेलिंग करने वाले पर पेनाल्टी लगाने या फिर उनके इंसेंटिव को वापस लेने जैसी कार्रवाई से ही असली जिम्मेदारी तय होगी।

म्यूचुअल फंड में बिना दावे वाला लाभांश 15.7% बढ़ा

नई दिल्ली, एएनआइ: कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने ताजा वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि बीते वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में म्यूचुअल फंड में बिना दावे वाली लाभांश राशि 15.7 प्रतिशत बढ़कर 2,689 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में यह राशि 2,324 करोड़ रुपये थी। यानी बीते वित्त वर्ष के दौरान म्यूचुअल फंड में बिना दावे वाली राशि में 365 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। सेबी ने बिना दावे वाली संपत्तियों की मात्रा कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें डिजिलाकर के साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड्स का एकीकरण शामिल है। इससे निवेशक एक ही स्थान पर डीमैट और म्यूचुअल फंड की जानकारी कर सकते हैं। इसके अलावा, सेबी और निवेशक शिक्षा व संरक्षण कोष प्राधिकरण ने निवेशक शिविर पहल शुरू की है।

राष्ट्रीय फलक

अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों और पूर्व अधिकारियों पर ईडी का शिकंजा

- मनी लांड्रिंग के दो मामलों में विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल
- द्वारका और राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट, रिलायंस इन्फ्रा और आरकाम से जुड़ा है मामला
- मुंबई पुलिस और सीबीआइ की एफआइआर के आधार पर कार्रवाई

अदालती कार्यवाही में आगे बढ़ी ईडी।

नई दिल्ली, प्रेट्र : ईडी ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों और उनके पूर्व अधिकारियों से जुड़े मनी लांड्रिंग के दो अलग-अलग मामलों में विशेष अदालतों में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इन मामलों में सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पहला मामला रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़ा है। ईडी ने शनिवार को द्वारका स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस ग्रुप के पूर्व कार्यकारी अधिकारी सतीश सेठ (70) और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज कराई। सतीश सेठ को ईडी ने जून में गिरफ्तार किया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। उन्होंने वर्ष 2025 में रिलायंस ग्रुप छोड़ दिया था।

जांच में यह सामने आया कि एनएचएआइ की चार टोल-रोड परियोजनाओं (त्रिची-करूर, त्रिची-डिंडीगुल, सलेम-उलुंदुरपेट और जयपुर-रींगस) के सार्वजनिक फंड को डायवर्ट करने की एक 'संगठित साजिश' की गई थी। सितंबर-अक्टूबर 2010 के दौरान फर्जी सब-कान्ट्रैक्टिंग और शेल कंपनियों के जरिये लगभग 187 करोड़ रुपये का गबन किया गया।

दूसरा मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकाम) से संबंधित है, जिसमें राऊज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में एक पूरक चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले की मुख्य चार्जशीट मार्च में दाखिल की गई थी। इसमें आरकाम, रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड (आरटीएल) और पूर्व अधिकारियों - सतीश सेठ, गौतम दोशी, अमिताभ झुनझुनवाला आदि को आरोपित बनाया गया है।

यह पूरक चार्जशीट सीबीआइ की उन एफआइआर पर आधारित है, जिनमें आरकाम, आरटीएल और रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड द्वारा क्रेडिट सुविधाओं के डायवर्जन का आरोप है। इस मामले में अपराध से अर्जित आय की राशि 40,185 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर अनिल अंबानी ग्रुप की ओर से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है और ना ही नामजद पूर्व अधिकारियों की तत्काल प्रतिक्रिया मिल सकी है।

31 जुलाई तक अपील न करने वाले करदाताओं को मिल सकती राहत

जासं, लखनऊ : जीएसटी के 2017 से लेकर अब तक के प्रकरणों की जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने की समय सीमा भले ही बीत चुकी है, लेकिन करदाताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। राज्यों के न्यायाधिकरणों से सुझाव मांगे गए हैं। संभव है कि अपील करने की अवधि बढ़ जाए।

इंस्टीट्यूट आफ कास्ट अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आइसीएआइ) लखनऊ चैप्टर की ओर से रविवार को होटल डैमसन प्लम में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें जीएसटी वाद-विवाद व जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण विषय पर जानकारी दी गई। न्यायाधिकरण लखनऊ पीठ के न्यायिक सदस्य संतोष श्रीवास्तव ने कहा कि जीएसटी अपील पोर्टल पर कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, जिन्हें बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा। जिन लोगों ने निर्धारित समय सीमा में अपील दाखिल नहीं की है, उन करदाताओं को राहत मिल सकती है।

वेदांता ने हासिल की कार्लापाट-पोलिंगपाड़र बाक्साइट ब्लाक, बाल्को होगी मजबूत

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा

- कच्चे माल का बड़ा स्रोत, 24.8 करोड़ टन अनुमानित भंडार
- अडाणी, रिलायंस, हिंडाल्को और पावरसेम भी दौड़ में रहे शामिल

भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड संयंत्र। फाइल फोटो

वेदांता समूह की इकाई भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) ने ओडिशा के कालाहांडी जिले के कार्लापाट-पोलिंगपाड़र बाक्साइट ब्लाक की नीलामी जीत ली है। अडाणी समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और पावरसेम जैसी कंपनियों से मुकाबले में बाल्को ने 175 प्रतिशत प्रीमियम की सबसे ऊंची बोली लगाकर ब्लाक हासिल किया। करीब 24.8 करोड़ टन अनुमानित भंडार वाला यह ब्लाक वेदांता समूह के लिए कच्चे माल के बड़े स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है।

कार्लापाट ब्लाक ऐसे समय में मिला है, जब बाल्को कोरबा में एल्युमिनियम उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी के मौजूदा उत्पादन आधार के विस्तार के साथ आने वाले वर्षों में बाक्साइट और एल्युमिना की जरूरत भी बढ़ेगी। ऐसे में बड़े बाक्साइट भंडार वाला ब्लाक हासिल करना उत्पादन के लिए कच्चे माल की दीर्घकालीन उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण है। बाक्साइट से एल्युमिना और फिर एल्युमिनियम तैयार होता है। वेदांता समूह की इस उत्पादन श्रृंखला में ओडिशा का लांजीगढ़, झारसुगुड़ा और छत्तीसगढ़ का कोरबा महत्वपूर्ण केंद्र है।

इस वर्ष हुआ होगा पांच लाख टन विस्तार का काम : बाल्को की कोरबा स्थित वर्तमान एल्युमिनियम उत्पादन क्षमता करीब पांच लाख टन प्रतिवर्ष है। पांच लाख टन अतिरिक्त क्षमता वाले विस्तार संयंत्र का निर्माण अंतिम चरण में है, जिसके 2026 में पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद कोरबा संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता करीब 10 लाख टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। इस विस्तार के बाद वेदांता समूह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक समूह बन जाएगा।

झारसुगुड़ा में 18.5 लाख टन उत्पादन: ओडिशा के झारसुगुड़ा में वेदांता समूह का करीब 18.5 लाख टन वार्षिक क्षमता वाला एल्युमिनियम संयंत्र संचालित है। कोरबा में विस्तार पूरा होने के बाद दोनों संयंत्रों की संयुक्त क्षमता करीब 28.5 लाख टन प्रतिवर्ष हो जाएगी।

इस बढ़ते उत्पादन आधार के लिए पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता आवश्यक होगी। कार्लापाट का बड़ा बाक्साइट भंडार इसी जरूरत को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण संसाधन बन सकता है।

25 शादियां करने के आरोपित समधी पर विधायक ने लिखाया मुकदमा

जागरण संवाददाता, सीवान

- रेउसा थाने में दर्ज कराया मुकदमा, छह अगस्त को बेटी के साथ विधायक आए थे फेसबुक लाइव

सीतापुर: बेटी के साथ फेसबुक पर लाइव जानकारी देते विधायक ज्ञान तिवारी। स्क्रीनशाट

भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने समधी अनुज त्रिवेदी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। यह मामला रेउसा थाने में दर्ज किया गया है। विधायक ने आरोप लगाया है कि अनुज ने झांसा देकर 25 महिलाओं से शादी की। अनुज पहले ही महाराष्ट्र पुलिस द्वारा ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार होकर जेल भेजा जा चुका है।

सेउता से विधायक ज्ञान तिवारी ने दो वर्ष पहले अपनी बेटी की शादी अनुज के बेटे प्रखर से की थी। प्रकरण के तूल पकड़ने के बाद छह अगस्त को विधायक अपनी बेटी डा. प्रज्ञा के साथ फेसबुक लाइव भी आए थे। आरोप है कि अनुज ने शादी के समय झूठ बोला था कि वह महाराष्ट्र में रियल एस्टेट का काम करता है। लेकिन, शादी के करीब ढाई वर्ष बाद विधायक को पता चला कि अनुज ने अलग-अलग नामों से वैवाहिक विज्ञापन देकर महिलाओं को ठगा और नकदी और उपहार लेकर फरार हो गया। उसने करोड़ों की संपत्ति भी बनाई है।

गिरफ्तारी के समय विधायक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन हाल ही में चार महिलाओं ने अनुज की संपत्ति कुर्क करने की मांग की थी। विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि उनकी बेटी प्रज्ञा तिवारी मांगलिक है, इसलिए उन्होंने मांगलिक वर की तलाश की थी।

एसी डक्ट में छिपा शराब बिहार भेज रहे कोच अटेंडेंट, रेलवे बोर्ड ने मांगा ब्योरा

जागरण संवाददाता, लखनऊ

- आरपीएफ से तस्करी वाली ट्रेन और कोच अटेंडेंट का रिकार्ड मांगा
- पांच महीने से वेतन नहीं, लेकिन शराब तस्करी से कमा रहे एक लाख महीना

पिछले साल 14 अगस्त को लखनऊ से बरौनी जा रही लखनऊ जंक्शन-बरौनी एक्सप्रेस की एसी सेकेंड बोगी ए-2 के यात्रियों ने गर्मी की शिकायत की तो बस्ती में बिजली कर्मचारियों ने पहले एसी प्लांट चेक किया। फाल्ट तलाशने के लिए छत का डक्ट खोला तो उसमें शराब की 316 बोतलें देखकर सभी चौंक पड़े। पता चला कि कोच अटेंडेंट ने ही इसे छिपाया था। एसी की फाल्ट तो नहीं मिली, लेकिन नशाबंदी वाले बिहार में ट्रेन के जरिये शराब की तस्करी का नया ट्रेंड सामने आ गया। तब से इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब रेलवे बोर्ड ऐसे कोच अटेंडेंट का ब्योरा तैयार करने में जुटा है, जो शराब तस्करी में लिप्त हैं।

बरौनी एक्सप्रेस में शराब तस्करी मामले की जांच करने वाली उच्च स्तरीय टीम को पता चला कि कोच अटेंडेंट को आठ हजार मानदेय कई महीने से मिला ही नहीं था। हर महीने शराब तस्करी से ही वह एक लाख तक की कमाई कर लेता था। ऐसे अटेंडेंट शराब तस्करी से लेकर पुष्पक एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की एसी बोगियों की सीटें बेचने में भी शामिल हैं। टीटीई से साठगांठ भी रहती है। पिछले एक साल से लखनऊ से बिहार जाने वाली ट्रेनों में शराब की तस्करी बढ़ी है। कोच अटेंडेंट की ड्यूटी तो एसी बोगियों के यात्रियों को लिनेन उपलब्ध कराने की होती है, लेकिन वह यांत्रिक विभाग के कर्मचारियों की मदद से एसी डक्ट, पैनल और शौचालय के बोल्ट खोलकर उसके भीतर शराब छिपाकर ले जा रहे हैं।

रेलवे बोर्ड करेगा समीक्षा

आउटसोर्स पर तैनात होने वाले कोच अटेंडेंट के आपराधिक इतिहास का ब्योरा किसी के पास नहीं है। ठेकेदार सत्यापन भी नहीं कराते हैं। रेलवे बोर्ड ने आरपीएफ से उन ट्रेनों और कोच अटेंडेंट का रिकार्ड मांगा है, जिनको पिछले छह महीने के दौरान शराब तस्करी या अन्य अपराध में पकड़ा गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड चिन्हित ट्रेनों की निगरानी बढ़ाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक छह माह में आठ कोच अटेंडेंट तो सीधे तौर पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में शराब तस्करी करते हुए धरे गए हैं। इसके अलावा आठ बार केवल तस्कर पकड़े गए हैं, उनके मोबाइल फोन में कोच अटेंडेंट से हुई बातचीत का ब्योरा मिला है।

झारखंड के रामगढ़ में पावर प्लांट में ब्लास्ट, एक दर्जन कर्मी झुलसे

- स्पंजन ने लगाया लापरवाही का आरोप
- फर्नेस से स्पंज आयरन गलाने का कार्य चल रहा था

अस्पताल में इलाज कराते कर्मचारी। जागरण

संवाद सूत्र, जागरण • कुजू (रामगढ़)

झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित श्रीराम पावर एंड स्टील प्लांट, मुरगा में रविवार शाम फर्नेस में जोरदार विस्फोट हो गया। हादसे में नौ कर्मी घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए रांची स्थित द होप अस्पताल ले जाया गया। होप अस्पताल के डा. सौरभ कुमार ने बताया कि फैक्ट्री के नौ कर्मियों को अस्पताल लाया गया था। इनमें दो की हालत गंभीर थी, जिन्हें रिम्स रांची रेफर किया गया। प्रबंधन ने घटना पर कोई जानकारी देने से परहेज किया।

जानकारी के अनुसार, प्लांट में फर्नेस के जरिए स्पंज आयरन गलाने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक फर्नेस में विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद पिघला हुआ गर्म लोहा और आग की लपटें आसपास फैल गईं, जिससे वहां काम कर रहे कई कर्मी इसकी चपेट में आकर झुलस गए। सूत्रों के अनुसार, हादसा फर्नेस से जुड़े मैन्मेट संचालन और मेंटेनेंस कार्य के दौरान हुआ। स्वजन ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है।

संपादकीय

शेत खाऊन फुगणारे कुंपण

कुंपणानेच शेत खाल्ले तर... अर्थात, रक्षण करणाऱ्यानेच किंबहुना ज्यांच्यावर आपण विश्वास ठेवला त्यांनीच घात केला तर जशी पायाखालची जमीन सरकते तसे 'नीट' देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पायाखालची जमीनही सरकली अन् डोक्यावरचे आभाळही फाटले. आता तिथे कोणाचा आधार शोधावा आणि किती ठिगळे लावावीत? सीबीआयने तत्पर दोषारोपपत्र दाखल करून सुरुंग लागलेल्या व्यवस्थेला सुरळीत करण्यासाठी पहिले पाऊल उचलले आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी ज्या नोंदी घेतल्या, जे पुरावे गोळा केले आणि प्रथमदर्शनी मास्टरमाइंड बहाद्दरांचे जे कारनामे कागदावर उतरले ते पाहून कुंपणानेच शेत खाल्ल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्या तिघांचे उज्ज्वल शिक्षणाचे तीनतेरा वाजवणारे आहेत. ज्यांनी एका विषयाला वाहून घेतले होते, त्यापैकी कोणी भाषांतरकार बनले, कोणी प्रश्नसंचिका तयार करण्यासाठी एनटीएमध्ये दाखल झाले. मोठ्या विश्वासाने त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवली असणार. गोपनीय विभागात भाषांतर आणि पुनर्भाषांतरासाठी दिलेल्या कोऱ्या कागदांचा वापर करून प्राध्यापक राहिलेल्या महाशयांनी चिठ्ठ्या लिहिण्याचे काम केले. कायम कॉपीमुक्तीची मोहीम राबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते त्यांनी गोपनीय विभागात राहून जणू कॉप्याच केल्या. छोट्या चिठ्ठ्या लिहिल्या. त्या लपविल्या. सर्वार्थाने त्यांनी चोरी केली, असाच अर्थ सीबीआयच्या दोषारोपपत्रातून निघतो. आपली हुशारी आणि बुद्धिचातुर्य हे गैरव्यवहार, भानगडींसाठी वापरणारे नमुने कमी नाहीत. समाजव्यवस्थेत सज्जन निष्क्रिय आणि दुर्जन सक्रिय झाले हे आपण नेहमी वाचतो, लिहितो, बोलतो; त्याची प्रचिती नीट पेपरफुटीमध्येही आली. व्यवस्था शाबूत ठेवणारे जणू निष्क्रिय झाले. कुंपणाच्या तारा त्यांना नीट बांधता आल्या नाहीत, की त्यांनी जाणीवपूर्वक त्या नीट बांधल्या नाहीत? पुरवलेले कागद कुठे वापरले गेले हे तपासणारे कोणी नव्हते का? याचाही शोध पुढच्या काळात एनटीएने आणि तपास यंत्रणेने घेतला पाहिजे. भाषांतरकार महाशयांनी आपली विद्वत्ता उपयोगात आणत सोप्या प्रश्नांचे पाठांतर केले. हे डोके विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी, त्यांच्या शंका निरसनासाठी वापरले असते तर दोन-चार जणांचे भले झाले असते; परंतु दक्षिणेचा लोभ इतका उच्चपराकोटीला गेला की, वेतन, निवृत्तिवेतन पुरले नाही. नामांकित संस्थांमध्ये अध्यापन करणाऱ्या महिला प्राध्यापकही काही कमी नव्हत्या. दिलेली जबाबदारी नीट पार पाडायचीच नाही, असे ठरवूनच त्याही यंत्रणेत शिरल्या असाव्यात. जिथे कोणालाही सहज प्रवेश मिळत नाही तिथे भाषांतरकार म्हणून पोहोचलेल्या आरोपींनी आपल्या अनुभवाचा उपयोग पेपर फोडण्यासाठी केला. प्रश्नांची आणि पाठ्यपुस्तकाची सांगड घातली अन् चोरीचा मार्ग सुकर केला. इथून तिथून तिन्ही भाषांतरकार एकाच माळेचे मणी निघाले. कोणी चिठ्ठ्या लिहिल्या, कोणी आठवून पुस्तकातील उतारे घरी येऊन चिन्हांकित केले, तर कोणी संक्षिप्त नोंदी ठेवल्या. मेंदूला ताण देऊन आठवून-आठवून केलेले उद्योग त्यांना आता कोठडीत आठवत असतील का? हा प्रश्न पडतो. गलेलठ्ठ वेतन आणि सर्व सुखसुविधांमध्ये नांदणाऱ्यांना झालेला लोभ विद्यार्थ्यांचे आयुष्य टांगणीला लावणारा ठरला. सेवानिवृत्त आणि कार्यरत असलेले मिळून तीन प्राध्यापक मास्टरमाइंड निघावेत? त्यांची ज्ञानाची भूक किती मोठी होती, माहिती नाही; परंतु लोभ आणि मायेत अडकलेला हव्यास साऱ्या देशाने पाहिला आहे. कुंपणाच्या भूमिकेतील महाभाग एनटीएत घुसले होते तेव्हा ज्यांच्या हाती संरक्षणाची लाठी होती ते कुठे होते? राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या सुरक्षेतील गंभीर त्रुटींचे पुढे काय होणार, हा खरा सवाल आहे. गोपनीय विभागाचे निरीक्षण करणारी व्यवस्था नव्हती की, मुद्दामहून ठेवली नव्हती? सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटीमुळे चिठ्ठ्या घेऊन जाणारे भाषांतरकार दृष्टिपथात आले नाहीत. प्रश्नपत्रिका अंतिम करणाऱ्यांमध्ये त्याच त्या व्यक्तींचा समावेश कसा होत गेला, याचा उलगडा झाला पाहिजे. प्रश्नांची चोरी करणारे, त्यांना चोरी करता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करणारे हे प्रथम दोषी आहेत. त्यानंतर हाती आलेला प्रश्नसंच विकत घेणारे आणि पुढे अनेक ग्राहक शोधणारे, तशी साखळी तयार करणारे तितकेच दोषी ठरतात; परंतु ज्यांच्यावर उज्ज्वल भविष्याची जबाबदारी दिली, ज्ञानी आहे म्हणून विश्वास ठेवला त्यांनीच पैशाचे 'दिवे' लावले. त्याचा इतका उजेड पडला, अन् गाजावाजा असा झाला की, ते 'अंधार' कोठडीत गेले.

सरसंघचालक बोलले, योग्य तेच बोलले!

पुढची पिढी आधीच्या पिढीपेक्षा जास्त तीक्ष्ण बुद्धीची असते, हे सत्य आपण स्वीकारले तरच 'जेन-झी'च्या मुला-मुलींचे म्हणणे आपण समजून घेऊ शकू.

विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

'हम लाये हैं तुफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभालके
- कवी आणि गीतकार प्रदीप यांनी लिहिलेले हे गाणे तुम्ही ऐकले असेल. पुढच्या पिढीचा दृष्टिकोन आणि विचार हाच आपल्या भवितव्याचा आधार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत मुंबईत झालेल्या त्यांच्या मुलाखतीत म्हणाले, 'जेन-झीने केलेले विरोध प्रदर्शन देशविरोधी नाही, ते आपले आहेत!' - मी भागवतजींच्या या मताशी पूर्ण सहमत आहे. ही मुलेच आपली पुढची पिढी आहेत. त्यांच्याशी संवादाबरोबरच त्यांना आपलेपणा वाटेल असे संवादी वातावरण आपणच तयार केले पाहिजे.

आजच्या तरुणांना राजकारण नव्हे, तर पारदर्शक आणि विश्वासार्ह शिक्षण व्यवस्था हवी आहे असे मी याच सदरात गेल्या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात लिहिले होते. या देशातल्या व्यवस्थेने तरुणांचा विश्वास गमावला तर देशाची सर्वात मोठी संपत्ती हरवून जाईल; आणि तरुणांचा विश्वास कायम राहावा यासाठी आपल्याला त्यांची भाषा समजली पाहिजे, आपण त्यांचे मन समजले पाहिजे. एखादी आई आपल्या छोट्या मुलाची भाषा समजून घेते, तसेच या पिढीशी मोठ्यांचे वर्तन असले पाहिजे. त्याचे मन आणि भाषा आपल्याला समजणे गरजेचे आहे. नेतृत्व करणाऱ्यांना नव्या पिढीच्या भाषेत त्यांच्याशी संवाद करावा लागेल आणि आजचे तरुण कुठल्याही 'ब्रँड'शी बांधून राहू इच्छित नाहीत हे समजून घ्यावे लागेल.

मुंबईत नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटरमध्ये 'इंडिया इंटरनॅशनल मूव्हमेंट टू युनायटेड नेशन्स'च्या पंधराव्या वर्धापनदिनानिमित्त मोहन भागवत यांनी नेतृत्व करणाऱ्यांना दिशा दिली, हे उत्तम झाले. लोकशाहीत विरोध प्रदर्शन हे व्यापक सहमती तयार करण्याचे एक माध्यम असते. भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत खूप काही दुरुस्त करण्याची गरज असून, ते होत नाही असे दिसते म्हणून ही मुले रस्त्यावर उतरली आहेत. त्यांच्याशी संवाद नक्कीच झाला पाहिजे आणि समाजामध्ये फूट पाडणे नव्हे, तर सहमती होणे हा त्यामागचा उद्देश असला पाहिजे. विरोध करताना वेगवेगळे विचार समोर येतात आणि चर्चेनंतर एक सहमती तयार होते.

भागवत यांचे हे म्हणणे शंभर टक्के खरे आहे; कारण कोणत्याही प्रश्नावर उपाय शोधण्यासाठी संवाद अत्यंत आवश्यक असतो. भारत आणि चीन यांच्यात सीमेवरून असलेला वाद नेहमीच तणावाच्या टोकाला पोहोचलेला असतो. परंतु, दोन्ही देश तरीही वाटाघाटी करत राहतात. पाकिस्तानशी आपला छत्तीसचा आकडा आहे. तरीही दोन्ही देशांत वाटाघाटी व्हाव्यात अशी मागणी सतत होत असते. 'ऑपरेशन सिंदूर' झाले तेव्हा दोन्ही देशांदरम्यान

बोलणी झाल्यानंतरच संघर्ष थांबला. संवाद महत्त्वाचा तो या अर्थाने.

स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपर फुटण्याचे प्रकरण सातत्याने गंभीर होत गेले. पेपर फुटण्याची सव्वाशेपेक्षा जास्त प्रकरणे समोर आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत 'झिरो टॉलरन्स' अपेक्षितात हे आपल्याला माहिती आहे. परंतु, शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनेक व्यक्तींबाबत प्रश्न उपस्थित होत राहतात. 'नीट-यूजी' पेपर फुटीचे प्रकरण समोर येताच कडक पावले टाकली गेली असती तर हे प्रकरण इतके चिघळले नसते. राहुल गांधी यांच्या संदर्भात काही लिहिले, तर या विवेचनाला राजकीय रंग येईल. परंतु, तेही विद्यार्थ्यांच्या योग्य मागण्यांविषयीच बोलत आहेत आणि त्यांच्याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.

आपल्याकडे शास्त्रार्थाची परंपरा चालत आली. दोन्ही बाजूंचे विचार समजून घेऊन योग्य तो निर्णय घेता यावा असे मोहन भागवत यांनी म्हटले ते बरोबरच आहे. शास्त्रार्थाचे निष्कर्ष निघतात, त्यांच्याकडे कोणा एकाचा पराभव किंवा दुसऱ्याचा विजय अशा स्वरूपात मुळीच पाहता कामा नये.

उत्क्रांतीचा सिद्धांत सांगतो, पुढची पिढी मागच्या पिढीपेक्षा अधिक तीक्ष्ण बुद्धीची असते. हे वास्तव आपण स्वीकारायलाच हवे.

आजच्या जेन-झीसमोर संपूर्ण जग खुले आहे. त्यांचा दृष्टिकोन व्यापक आहे. मात्र मी एक जरूर सांगेन - भारतीय सांस्कृतिक परंपरेचे मूल्यमापन जरूर करा, तिला कसोट्यांवर जरूर तपासा; पण एका झटक्यात ती नाकारू नका, हे शिकवण्याची जबाबदारीही आपलीच आहे. आणि हेही खरे, की ज्या देशातील नेतृत्व तरुणांच्या भावनांची दखल घेत नाही, त्यांच्यासाठी परिस्थिती पुढे अधिकाधिक कठीण होत जाते.

कॉंबडीची मान नव्हे, हत्तीची सोंड!

भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडणाऱ्या सिलीगुडी कॉरिडॉरला स्वातंत्र्यानंतरपासून 'चिकन नेक' म्हणजेच कॉंबडीची मान म्हटले जाते. या भागाची कमाल रुंदी अवघी २२ किलोमीटर आहे.

चीन आणि पाकिस्तान यांना वाटते, ही 'कॉंबडीची मान' तोडली की काम तमाम! पण अलीकडच्या काळात भारताने डावच पलटला आहे. आता या भागाला 'चिकन नेक' नव्हे, तर 'हत्तीची सोंड' म्हटले जात आहे. सोंड दिसायला बारीक असते, पण तिच्यात एवढी ताकद असते की भल्याभल्यांना धूळ चारू शकतो. गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्याच महिन्यात या 'हत्तीच्या सोंडेची' पाहणी केली आहे.

शत्रूंसाठी संदेश अगदी स्पष्ट आहे- उगाच अंगावर येण्याची आगळीक न करा, तरच बरे!

vijaydarda@lokmat.com
डॉ. विजय दर्डा यांचे समग्र लेखन वाचण्यासाठी स्कॅन करा :

अन्वयार्थ

क्वांटम कॉम्प्युटिंग : २१व्या शतकाचे नवे तंत्रज्ञान युग!

जे प्रश्न आजच्या महासंगणकांना सोडवायला वर्षानुवर्षे लागतील, ते क्वांटम संगणक काही तासांत किंवा मिनिटांत सोडवू शकेल, असा शास्त्रज्ञांचा दावा आहे.

डॉ. संजय गांधी
कौशल्य विकास तज्ज्ञ

मानवी इतिहासाने तंत्रज्ञानाचा विकास आणि त्यामुळे झालेले बदल अनुभवले आहेत. काही तंत्रज्ञानाने तर नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. एकोणिसावे शतक हे यंत्रयुग (मशीन एज) होते. वाफेचे इंजिन, कारखाने आणि यांत्रिकीकरणाने जगाची अर्थव्यवस्था बदलली. विसावे शतक हे माहिती युग ठरले. संगणक, इंटरनेट आणि डिजिटल क्रांतीने माणसाच्या जगण्याची, शिकण्याची आणि व्यवसाय करण्याची पद्धतच बदलून टाकली. आता आपण उभे आहोत एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर, जे आहे क्वांटम युग.

सर्वसामान्य भाषेत सांगायचे झाले, तर आजचा संगणक माहिती साठवण्यासाठी आणि प्रक्रिया करण्यासाठी बिट (० किंवा १) वापरतो. म्हणजे एका वेळी एकच शक्यता. याउलट क्वांटम कॉम्प्युटर हे क्युबिट (Qubit) वापरतात, जे एकाच वेळी ० आणि १ या दोन्ही अवस्थांमध्ये असू शकतात. याला सुपरपोझिशन म्हणतात. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, सामान्य संगणक एका वेळी एकच रस्ता चोखाळतो, तर क्वांटम संगणक हजारो रस्ते एकाच वेळी तपासू शकतो आणि योग्य उत्तर वेगाने शोधू शकतो. त्यामुळे जे प्रश्न आजच्या महासंगणकांनाही सोडवायला वर्षानुवर्षे लागतील, ते क्वांटम संगणक काही तासांत किंवा मिनिटांत सोडवू शकेल, असा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे.

क्वांटम तंत्रज्ञानाचे काय परिणाम होतील?

क्वांटम तंत्रज्ञान हे केवळ प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर ते सामान्य माणसाच्या आयुष्यावर थेट परिणाम करणार आहे.

आरोग्य क्षेत्र : नवीन औषधे आणि लस शोधण्याची प्रक्रिया जी आज अनेक वर्षे घेते, ती क्वांटम सिम्युलेशनमुळे अतिशय जलद होऊ शकते.

हवामान व शेती : हवामान बदलाचे अचूक अंदाज, पीक व्यवस्थापन आणि नैसर्गिक आपत्ती पूर्वसूचना यासाठी क्वांटम मॉडेलिंग उपयुक्त ठरेल.

आर्थिक व्यवहार : बँकिंग, गुंतवणूक जोखीम विश्लेषण आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन अधिक अचूक व वेगवान होईल.

ऊर्जा क्षेत्र : बॅटरी तंत्रज्ञान, सौरऊर्जा आणि नवीन पदार्थांच्या (मटेरियल्स) संशोधनाला गती मिळेल.

सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्व

क्वांटम तंत्रज्ञानाचा सर्वात संवेदनशील पैलू म्हणजे सायबर सुरक्षा. आज इंटरनेटवरील बँक व्यवहार, सरकारी माहिती आणि वैयक्तिक डेटा यांचे संरक्षण करणाऱ्या एन्क्रिप्शन पद्धती पारंपरिक संगणकांसाठी अभेद्य आहेत. मात्र पुरेसे सक्षम क्वांटम संगणक भविष्यात याच पद्धती काही वेळात भेदू शकतील, अशी शक्यता बहुतांश तज्ज्ञ व्यक्त करतात. त्यामुळे जगभरातील देश आणि उद्योग आतापासूनच क्वांटम-प्रतिरोधक सुरक्षा प्रणाली विकसित करण्यावर मोठ्या प्रमाणावर भर देत आहेत. भारतासाठीही ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.

शिक्षण क्षेत्र आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंग

क्वांटम कॉम्प्युटिंग हा विषय पारंपरिक पद्धतीने, केवळ पुस्तकी भौतिकशास्त्र आणि गणिती सिद्धांत शिकवून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे पुरेसे नाही. आजच्या विद्यार्थ्यांना गरज आहे ती प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित शिक्षणाची; जिथे ते स्वतः क्यूबिट्सवर कोडिंग करू शकतील, क्वांटम अल्गोरिदम प्रत्यक्ष राबवू शकतील आणि उद्योगातील खऱ्या समस्यांवर काम करू शकतील.

केवळ सिद्धांत शिकून विद्यार्थी नोकरीसाठी सज्ज होत नाहीत; त्यांना प्रोग्रामिंग, सिम्युलेशन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा अनुभव मिळणे आवश्यक आहे. याच दृष्टिकोनातून शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्य गरजेचे ठरते. जसे अ‍ॅस्पायर नॉलेज अँड स्किल्स इंडिया आणि आयआयटी (बीएचयू) यांच्यातील भागीदारी तरुणांसाठी नवे क्षितिज निर्माण करणारी आहे. भविष्यातील कुशल मनुष्यबळ घडवण्यासाठी असे सहकार्य निर्णायक ठरते.

येत्या दशकात क्वांटम तंत्रज्ञान हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेइतकेच किंबहुना काही क्षेत्रांत त्याहूनही अधिक परिवर्तनकारी ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्याचे संकेत दिसू लागले आहेत. त्यामुळे आजचे विद्यार्थी, संशोधक आणि उद्योग यांनी या तंत्रज्ञानाची मूलभूत समज आणि प्रत्यक्ष कौशल्य आत्मसात करणे, ही काळाची गरज आहे.

जगभर

राहण्यायोग्य शहरांमध्ये जगात जपान वरचढ !

जगातील राहण्यायोग्य शहरांची (लिव्हेबल सिटीज) एक यादी नुकतीच इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिटने प्रसिद्ध केली. जपानमधील ओसाका हे शहर या यादीत सातव्या क्रमांकावर आहे. पूर्वी १३ व्या क्रमांकावर असलेले तोक्यो यंदा दहाव्या क्रमांकावर आले आहे. जगातील पहिल्या दहा राहण्यायोग्य शहरांमध्ये दोन शहरे असलेला जपान हा एकमेव आशियाई देश ठरला आहे. त्यामुळेच जपानमधील ही दोन शहरे राहण्यायोग्य करण्यासाठी कोणत्या निर्णयांचा उपयोग झाला, हे जाणून घेणे रंजक आहे. एखादे शहर राहण्यायोग्य असण्यासाठी तिथे मोठमोठी, जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळे असणे आवश्यक नाही. उलट तिथे राहणाऱ्या नागरिकांना खासगी वाहनाशिवाय कामावर जाता येते का, पायी चालत ते शहरात फिरू शकतात का, अपंग व्यक्ती व्हिलचेअरवरून किंवा छोट्या बाळाला त्याचे आई-बाबा बाबागाडीतून फिरवू शकतात का, वृद्ध व्यक्ती फुटपाथवरून चालू शकतात का, सहज रस्ता ओलांडू शकतात का याबाबी ते शहर राहण्यायोग्य आहे की नाही हे ठरवतात. पायाभूत सेवा, आरोग्य, शिक्षण अशा निकषांवर जपानमधील ओसाका आणि तोक्यो या शहरांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाले आहेत.

जपानमध्ये शहरांतील नागरिकांचे वास्तव्य सुखाचे करण्यासाठी चार प्रमुख नियम आहेत. आपल्या शहराची रचना सर्वांना उपयोगी पडेल अशी करण्याकडे जपानचा कल आहे. जपानी नागरिक रोजच्या कामांसाठी वैयक्तिक वाहनावर अवलंबून न राहता जगू शकतात. दैनंदिन जगण्यातील अडथळे कमी करण्यावर जपानचा विशेष भर आहे. जपानमध्ये शोतेंगाई म्हणजे छत असलेले सपाट बाजार-रस्ते आहेत. भाजीवाले, कॅफे, दवाखाने, रेस्टॉरंट्स असे सर्व काही या रस्त्यांवर असल्यामुळे नागरिकांना रोजच्या

गरजांसाठी फार लांब जावे लागत नाही.

जपानमध्ये वाहनांच्या सोयीचे रस्ते तयार केले जात नाहीत तर रस्त्यांच्या आकारांनुसार वाहने बनवली जातात. अरुंद रस्त्यांवरही छोटे मालवाहू ट्रक सहज फिरताना दिसतात. पायी चालणारे लोक, सायकलस्वार आणि वाहन चालक या सर्वांना तिथल्या रस्त्यांवर समान न्याय मिळतो. त्यामुळे वाहतूक कोंडी, गोंधळ, अपघात यांचे प्रमाणही कमी असते. जपानमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही अत्यंत भरवशाची आणि उत्कृष्ट असल्यामुळे वैयक्तिक वाहन, वाहन चालवण्याचा परवाना या गोष्टी अनावश्यक वाटतात, असे जपानी लोक सांगतात. २००६ मध्ये जपानने आपली शहरे 'बॅरिअर फ्री' करणारा कायदा आणला. त्यामुळे देशभरातील हजारो रेल्वेस्थानकांवरचे जिने काढून लिफ्ट्स बसवण्यात आल्या. साहजिकच सर्व वयाच्या नागरिकांचा रेल्वे वापर सुकर झाला आहे.

जपानमध्ये नवीन गोष्टींसाठी जुन्या वस्तू नष्ट करण्याचा प्रकार दिसत नाही. जपानने बुलेट ट्रेनसारख्या वेगवान आणि अत्याधुनिक पर्यायांचा स्वीकार केला असला तरी त्यासाठी आपली ओळख असलेल्या गोष्टी पुसून टाकायला जपानी माणूस तयार नाही. त्यामुळेच शेकडो वर्षे जुनी झाडे जपानमध्ये आजही जतन केली जातात. ओसाका या शहराजवळ असलेल्या कयाशिमा स्थानकाच्या छतामधून आत येणारे ७०० वर्ष जुने कापुराचे झाड हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. जपानमधील आणखी एक महत्त्वाची पद्धत म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी अत्यंत कटाक्षाने शिष्टाचाराचे पालन केले जाते.

करनीती

आयटीआर भरताना मान्य होणारे खर्च

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, व्यवसायात वर्षभरात झालेला प्रत्येक खर्च ITR मध्ये व्यावसायिक खर्च म्हणून दाखवता येतो का?

कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, माही. खर्च झाला म्हणजे तो आयकरात मान्य होतोच असे नाही. एखादा खर्च एक जरी अट पूर्ण करत नसेल, तर तो अमान्य होतो आणि नफा वाढल्यामुळे करासोबत व्याज व दंडही भरावा लागू शकतो. खर्च पूर्णपणे व्यवसायासाठी असावा, वैयक्तिक नसावा; तो महसूली स्वरूपाचा व संबंधित वर्षातील असावा; योग्य बिल, व्हाउचर व लेखा नोंदी असाव्यात; तसेच पेमेंट आणि टीडीएसचे नियम पाळलेले असावेत.

अर्जुन : कोणते खर्च व्यवसायासाठी सामान्यतः मान्य होतात?

कृष्ण : योग्य कागदपत्रांसह आणि नियमांनुसार केलेले खर्च जसे कच्चा माल व खरेदी, वाहतूक, पगार व कर्मचारी खर्च, व्यवसायाचे भाडे, वीज-पाणी, फोन, मोबाइल आणि इंटरनेट खर्च, दुरुस्ती, विमा, व्यावसायिक कर्जावरील व्याज, बँक चार्जेस, घसारा, जाहिरात व मार्केटिंग, व्यावसायिक फी, व्यावसायिक प्रवास आणि ऑफिस खर्च इत्यादी खर्च सामान्यतः मान्य होतात.

अर्जुन : आता कोणते खर्च आयकरात मान्य होत नाहीत?

कृष्ण : वैयक्तिक व घरगुती खर्च, आयकर व त्यावरील दंड/व्याज, कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दलचे दंड, भांडवली खर्चाची पूर्ण रक्कम, नियमबाह्य रोख देयके, टीडीएस न पाळल्यामुळे होणारी नामंजुरी, मुदतीनंतर जमा केलेला कर्मचाऱ्याचा पीएफ/ईएसआयसी आणि बनावट खरेदीचे खर्च अमान्य होऊ शकतात.

- उमेश शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटंट

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : janman@lokmat.com

जेन झी

आवाज उठवणाऱ्या मुली आणि डॉक्सिंग डाकूंच्या टोळ्या!

मुलींना बोलण्याचं स्वातंत्र्य हवं आणि बोलण्यासाठी भयमुक्त अवकाश हवा. त्यासाठी डॉक्सिंग करणाऱ्या टोळ्यांना जाब विचारायला हवा.

राही श्रु. ग.
सिनिअर रिसर्च फेलो जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ

देशभरातल्या विद्यार्थी आंदोलनांमधल्या जेन झींच्या भाषेमुळे दुखावलेल्या सत्ताधीशांच्या आणि 'व्हॉट्सॲप अंकल/ आंटी'च्या मनातली सर्वात खोलवरची जखम आहे, मुलींच्या वागण्यामुळे झालेली. पुरुष, मुलगे ठीक आहेत, ते असंच वागणार, बोलणार, पण या देशाच्या मुली, ज्यांनी इथली संस्कृती त्यांच्या खांद्यांवर वाहणं अपेक्षित आहे, त्या खुलेआम शिव्या देतात, सत्तेच्या उच्चस्थानी आणि अनेकांच्या श्रद्धास्थानी असणाऱ्या नेतेमंडळींची टवाळी करतात, याचा खरा खोलवर धक्का बसला आहे, दुःख झालं आहे.

शिव्या कोण देतो आहे, टिंगलटवाळी कोण, कोणाची करतो आहे, हा संदर्भ अतिशय महत्वाचा असतो. ज्याच्याकडे सत्ता आहे, ज्याला राज्यसंस्थेची सुरक्षा आहे, माध्यमांचं कवच आहे, त्याने कोणाला दहशतवादी, देशद्रोही, झुरळं म्हणणं आणि ज्यांच्या हाती कसलीही सत्ता नाही अशा सामान्य लोकांनी सत्ताधीशांविषयी विनोद करणं, यात मोठं अंतर असतं. बहुतेक शिव्या आपल्याकडे स्त्रियांच्या बाबतीत, त्यांना हीन लेखणाऱ्या असतात. मात्र तरूण मुली जेव्हा शिव्याच काय, साधी टिंगल टवाळीही करतात, तेव्हा त्यांच्या चारित्र्याकडे कधी 'काचेचं भांडं' तर कधी हत्यार म्हणून पाहणारा समाज प्रचंड अस्वस्थ होतो.

सत्ताधीशांच्या जवळच्या अनेक पत्रकारांनी आणि सोशल मीडियावरच्या कार्यकर्त्यांनी या मुलींना एकेक करून निशाण्यावर घेतलं. मुंबईच्या आंदोलनांमध्ये नाच करणाऱ्या उर्वशीचा व्हिडिओ भाजपच्या छत्तीसगडच्या सोशल मीडिया खात्यांवर

चक्क 'बाबर की विरासत पर ठुमके लगाती जेन झी' या नावाखाली प्रसिद्ध केला गेला. मूळ नाचाचा व्हिडिओ तयार करणाऱ्या उर्वशी पलंदुरकरने हसत हसत या 'बाबर की विरासत'ला प्रश्न विचारणाऱ्या पीपीटीचं दुसरं रील केलं. मात्र प्रत्येकासाठी हे सोपं नव्हतं. सोशल मीडियावर ज्या व्यक्त झाल्या होत्या अशा कितीतरी मुलींच्या अकाउंट्सवर पुरुषांनी त्यांना छळायला सुरूवात केली. कोणी त्यांना आणि त्यांच्या घरच्यांना धमक्या द्यायला सुरूवात केली, तर कोणी त्यांचे फोटो वापरून त्यापासून अश्लील लैंगिक व्हिडिओ, फोटो तयार करून सगळीकडे पसरवायला लागले.

या छळाची पुढची पायरी म्हणजे 'डॉक्सिंग' (doxxing). 'ड्रॉपिंग डॉक्युमेंट्स' (dropping docs) या शब्दप्रयोगावरून तयार झालेला 'डॉक्सिंग' हा शब्द सोशल मीडियाच्या युगातला हिंसेच्या एका विशिष्ट प्रकाराचं नाव आहे. एखाद्याची खाजगी किंवा संवेदनशील माहिती अचानक जगासमोर जाहीर करणं, याला डॉक्सिंग म्हणतात. एखाद्याचा पत्ता, फोन नंबर, बँक खात्याची माहिती प्रसंगी त्या व्यक्तीची मीडिया अकाउंट्स हॅक करून सार्वजनिक करणं, या डॉक्सिंगच्या प्रकाराला कितीतरी मुलींना तोंड द्यावं लागलं. 'तिच्यावर बलात्कार करा, तिला, तिच्या कुटुंबियांना मारून टाका', अशा घोषणांसह या मुलींचे पत्ते जाहीर केले गेले. तरूणांच्या आंदोलनांबद्दल व्हिडिओ करणारी एक मुलगी आईबरोबर बाजारात गेलेली असताना दोन पुरुषांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. यापैकी कितीतरी मुली आणि त्यांचे कुटुंबीय अनेक दिवस घराबाहेर पडू शकलेले नाहीत.

टीका आणि व्यंगाची इतकी भयंकर किंमत चुकवायला लावून, माफी मागायला भाग पाडून त्यांना माफ करण्याचा देखावा करणं हा निव्वळ मानभावीपणा आहे. जेन झी मुलींना जगायचं असेल, तर त्यांना बोलण्याचं स्वातंत्र्य हवं; आणि बोलण्यासाठी भयमुक्त अवकाश हवा. त्यासाठी डॉक्सिंग करणाऱ्या टोळ्यांना जाब विचारायला हवा.

raheeshrutiganesh@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८५ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२-२४७४८०४६
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२-२४९०८८४३-४८ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न बुझ, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४९९०५, २५३८५७७४
● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : २७७५६८८८ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

चिंतन

सीमा सुरक्षा के साथ सतर्कता भी जरूरी

भारत-पाकिस्तान सीमा पर अमृतसर के दाउके गांव में बुधवैठिए को बीएसएफ द्वारा मार गिराए जाने की घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि सीमा सुरक्षा में छोटी-सी चूक भी बड़ी चुनौती का रूप ले सकती है। कंटीली तार के पास संदिग्ध गतिविधि, जवानों की सतर्कता, चेतावनी और उसके बाद हुई फायरिंग पूरी घटना बताती है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों को हर समय सतर्कता बरतनी पड़ती है। सीमा पर यह घटना ऐसे समय हुई है, जब पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से आधुनिक बनाने में जुटा है। रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान ने भारत से लगे इलाकों में चीन निर्मित एसएच-15 व्हील्ड सेल्फ-प्रोपेल्ड होवित्ज़र तैनात किए हैं। इनकी संख्या करीब 250 बताई जा रही है, हालांकि इस तैनाती की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन यदि यह आकलन सही है तो इसे केवल हथियारों की खरीद का मामला मानना उचित नहीं होगा। यह चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे होते सैन्य एवं रणनीतिक सहयोग का एक और गंभीर संकेत है। एसएच-15 स्वचालित तोप ट्रक चेसिस पर आधारित है और शूट एंड स्कूट क्षमता के कारण गोलीबारी के बाद तेजी से स्थान बदल सकती है। इससे जवाबी गोलाबारी का जोखिम कम होता है। लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी प्रणालियां सीमा के पास तैनात होने पर किसी भी सैन्य संकट में दोनों पक्षों के लिए प्रतिक्रिया का समय घटा सकती हैं। यही वह पहलू है, जिसे भारत को गंभीरता से देखना चाहिए। चीन-पाकिस्तान सैन्य सहयोग की कहानी नई नहीं है। चीन के लिए पाकिस्तान एक रणनीतिक साझेदार होने के साथ-साथ उसके रक्षा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बाजार भी है, जबकि पाकिस्तान को अपेक्षाकृत कम लागत पर सैन्य आधुनिकीकरण और पश्चिमी देशों पर निर्भरता घटाने का अवसर मिलता है। भारत के लिए चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसे एक साथ दो सीमाओं पर रणनीतिक परिस्थितियों पर नजर रखनी पड़ती है। पाकिस्तान की बढ़ती आर्टिलरी क्षमता, रॉकेट सिस्टम और अन्य सटीक मारक हथियारों के साथ चीनी तकनीक का मेल भविष्य के किसी संकट में सैन्य गणित को प्रभावित कर सकता है। अमृतसर की घटना इस बड़े परिदृश्य का जमीनी पहलू सामने रखती है। सीमा पर केवल भारी हथियारों की चुनौती नहीं है, बल्कि घुसपैठ, तस्करी, ड्रोन और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए सीमा सुरक्षा को केवल जवानों की संख्या या हथियारों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आधुनिक सेंसर, ड्रोन निगरानी, कैमरा नेटवर्क, बेहतर खुफिया तंत्र और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच तेज सूचना-साझाकरण को और मजबूत करना होगा। भारत को पाकिस्तान की हर गतिविधि पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी निवारक क्षमता को इतना मजबूत करना होगा कि किसी भी संभावित दुस्साहस की कीमत स्पष्ट हो। साथ ही, संदिग्ध घुसपैठ की घटनाओं में सख्त कार्रवाई के साथ निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच भी जरूरी है। चीन-पाकिस्तान का बढ़ता सैन्य तालमेल भारत के लिए निश्चित रूप से सतर्क रहने का संकेत है, लेकिन इसे अनावश्यक भय का कारण बनाना भी उचित नहीं। भारत की वास्तविक ताकत उसकी तकनीकी क्षमता, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, खुफिया तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया में है। सरहद पर चौकसी जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी दूरदर्शी रणनीति भी है। सीमा की सुरक्षा केवल कंटीली तार से नहीं, बल्कि मजबूत निगरानी, आधुनिक तकनीक और हर संभावित खतरे के लिए तैयार रणनीति से सुनिश्चित होगी।

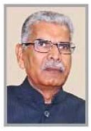

शिक्षा के पंचतत्त्व
प्रो. रमेश चंद्र कुहाड़

शिक्षा संस्थानों की अभिरक्षा का पुनर्निर्माण

प्रश्नपत्र लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं तथा प्रवेश प्रक्रियाओं को लेकर उत्पन्न विवादों ने करोड़ों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के मन में गहरी चिंता उत्पन्न की है। वर्षों की कठोर साधना, अथक परिश्रम और असंख्य सपनों का भविष्य जब कुछ क्षणों में संदेह के घेरे में आ जाता है, तब सबसे अधिक आहत विद्यार्थी नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता होती है। यह स्थिति केवल प्रशासनिक त्रुटि या तकनीकी विफलता का परिणाम नही, शिक्षा व्यवस्था की संरचना, उत्तरदायित्व और संस्थागत स्वायत्तता पर गंभीर पुनर्विचार का आह्वान भी है। इन चुनौतियों का समाधान केवल कठोर कानूनों, दंडात्मक प्रावधानों अथवा आधुनिक तकनीकी निगरानी में नहीं खोजा जा सकता।

किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक संपन्नता अथवा तकनीकी प्रगति में नहीं, बल्कि उसकी शिक्षित, जागरूक, नैतिक और उत्तरदायी युवा पीढ़ी में निहित होती है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, समाज की संस्कृति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करने वाली सबसे प्रभावशाली शक्ति है। इसलिए जब शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं, तब संकट केवल किसी परीक्षा, विश्वविद्यालय अथवा संस्था का नहीं होता; वह राष्ट्र के भविष्य, सामाजिक विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों की विश्वसनीयता का संकट बन जाता है।

हाल के वर्षों में प्रश्नपत्र लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं तथा प्रवेश प्रक्रियाओं को लेकर उत्पन्न विवादों ने करोड़ों विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के मन में गहरी चिंता उत्पन्न की है। वर्षों की कठोर साधना, अथक परिश्रम और असंख्य सपनों का भविष्य जब कुछ क्षणों में संदेह के घेरे में आ जाता है, तब सबसे अधिक आहत विद्यार्थी नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता होती है। यह स्थिति केवल प्रशासनिक त्रुटि या तकनीकी विफलता का परिणाम नहीं है; यह शिक्षा व्यवस्था की संरचना, उत्तरदायित्व और संस्थागत स्वायत्तता पर गंभीर पुनर्विचार का आह्वान भी है। इन चुनौतियों का समाधान केवल कठोर कानूनों, दंडात्मक प्रावधानों अथवा आधुनिक तकनीकी निगरानी में नहीं खोजा जा सकता। स्थायी समाधान तभी संभव है, जब शिक्षा की मूल आत्मा, उसकी संस्थागत संरचना और शैक्षणिक उत्तरदायित्व को पुनः सुदृढ़ किया जाए। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था पांच आधारभूत तत्त्व-प्रवेश, पाठ्यक्रम, पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम पर आधारित है। यदि इनमें से कोई भी तत्व शिक्षा संस्थानों के नैतिक और शैक्षणिक नेतृत्व से बाहर चला जाता है, तो उत्तरदायित्व का स्वाभाविक क्षरण प्रारम्भ हो जाता है। उत्तरदायित्व का यह विखंडन अंततः पारदर्शिता को कमजोर करता है और वही परिस्थितियां प्रश्नपत्र लीक, अनियमितताओं तथा जनविश्वास के ह्रास जैसी समस्याओं को जन्म देती हैं। वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न बाहरी एजेंसियों के बीच विभाजित होते जा रहे हैं। प्रवेश प्रक्रिया कोई संस्था संचालित करती है, प्रश्नपत्र किसी अन्य एजेंसी द्वारा तैयार किए जाते हैं, परीक्षा किसी तीसरे तंत्र के माध्यम से आयोजित होती है और परिणाम भी कई स्तरों की बाहरी व्यवस्थाओं पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण कठिन हो जाता है। जब उत्तरदायित्व बिखरता है, तब पारदर्शिता और जवाबदेही भी स्वतः कमजोर पड़ जाती है। परिणामस्वरूप किसी त्रुटि अथवा विफलता की स्थिति में दोष तो दिखाई देता है, परंतु उत्तरदायी व्यक्ति या संस्था स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती। शिक्षा केवल परीक्षा आयोजित करने की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। यह शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, शोध, संवाद, मूल्यांकन और सतत बौद्धिक विकास के बीच निरंतर चलने वाली एक जीवंत प्रक्रिया है।

शिक्षक केवल विषय-विशेषज्ञ नहीं होता; वह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, चरित्र, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्माता होता है। यदि प्रवेश से लेकर परिणाम तक की संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षा

संस्थानों की भूमिका सीमित कर दी जाएगी, तो धीरे-धीरे उनका शैक्षणिक महत्व भी कम होने लगेगा। तब विद्यालय और विश्वविद्यालय केवल भवन बनकर रह जाएंगे, जबकि शिक्षा का वास्तविक केंद्र उनका बौद्धिक वातावरण, नैतिक संस्कृति और अकादमिक परंपरा होती है। निस्संदेह विद्यार्थियों की सुविधा, समान अवसर और राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनेक प्रवेश प्रक्रियाओं का केंद्रीकरण किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जैसी व्यवस्थाओं ने विद्यार्थियों का समय, श्रम और आर्थिक व्यय कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किंतु अनुभव यह भी दर्शाते हैं कि अनेक विश्वविद्यालयों में अपेक्षित संख्या में विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं।

परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह जाती हैं और बार-बार ओपन काउंसलिंग आयोजित करनी पड़ती है। यह केवल प्रवेश प्रक्रिया का प्रश्न नहीं, बल्कि संस्थागत उत्तरदायित्व, स्थानीय शैक्षणिक आवश्यकताओं और विश्वविद्यालयों की सक्रिय भूमिका से भी जुड़ा विषय है। अतः आवश्यकता किसी एक छोर पर खड़े होकर केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण का समर्थन करने की नहीं, बल्कि संतुलित और उत्तरदायी व्यवस्था विकसित करने की है। यदि राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं आवश्यक समझी जाती हैं, तो भी प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरणों, विषय चयन, शैक्षणिक परामर्श और प्रवेश प्रबंधन में विश्वविद्यालयों की भूमिका अधिक सशक्त होनी चाहिए। इससे शिक्षा के प्रथम पंचतत्व, प्रवेश का स्वाभाविक संबंध पुनः शिक्षा संस्थानों से स्थापित होगा। इसी प्रकार यदि सरकार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, सिविल सेवाओं अथवा अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रवेश परीक्षाओं की व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक समझती है तो उनकी शैक्षणिक विश्वसनीयता, गोपनीयता, निष्पक्षता और शुचिता का नेतृत्व शिक्षा संस्थानों तथा अनुभवी शिक्षकों के हाथों में होना चाहिए। आधुनिक तकनीक, सूचना-प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां इस प्रक्रिया के आवश्यक सहयोगी अवश्य हों, किंतु परीक्षा की शैक्षणिक आत्मा का केंद्र शिक्षक ही रहना चाहिए। एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली केवल तकनीकी दक्षता से निर्मित नहीं होती। उसके लिए शिक्षकों, प्रशासकों, सूचना-प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों तथा सहयोगी कर्मचारियों के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। फिर भी उसकी शैक्षणिक विश्वसनीयता का मूल आधार शिक्षक ही होता है। शिक्षक के लिए शिक्षण केवल आजीविका नहीं, बल्कि ज्ञान, चरित्र और समाज के प्रति आजीवन नैतिक उत्तरदायित्व है। यदि हमें प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं पर स्थायी नियंत्रण स्थापित करना है, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पुनः स्थापित करनी है और समाज का विश्वास सुदृढ़ करना है, तो शिक्षा के पंचतत्व -प्रवेश, पाठ्यक्रम, पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम को पुनः शिक्षा संस्थानों की अभिरक्षा, उत्तरदायित्व और नैतिक नेतृत्व में प्रतिष्ठित करना होगा।

यही शिक्षा की गरिमा, शिक्षक की प्रतिष्ठा और विद्यार्थी के उज्ज्वल भविष्य की सबसे सुदृढ़ आधारशिला है। भारत यदि ज्ञान-आधारित, नवाचारी और विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प रखता है, तो उसे शिक्षा को केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की सर्वोच्च संस्था के रूप में देखना होगा। प्रवेश, पाठ्यक्रम, पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम- ये पांचों पंचतत्त्व तभी अपनी पूर्ण सार्थकता प्राप्त करेंगे, जब उनका संचालन उत्तरदायी, स्वायत्त और नैतिक शैक्षणिक नेतृत्व के अंतर्गत होगा। यही शिक्षा की विश्वसनीयता, शिक्षक की गरिमा, विद्यार्थी के भविष्य और राष्ट्र के ज्ञान-आधारित विकास की सबसे सुदृढ़ आधारशिला है।

(लेखक हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं व उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

मेटा पर सख्ती

डॉ. मोनिका शर्मा

सुरक्षा-सम्मान से जुड़ी जवाबदेही लेनी होगी

मौजूदा दौर में हर मोर्चे पर डिजिटल होते जीवन में भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स नियमों से परे नहीं हो सकते। विशेषकर नागरिकों और देश की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हाल ही में भारत सरकार ने मेटा के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यही बात स्पष्ट रूप कही है कि देश में काम करने वाले सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। ध्यातव्य है कि सरकार द्वारा मेटा कंपनी से एआई, डीपफेक, बाल यौन शोषण सामग्री और कंटेंट मॉडरेशन पर भी जवाब मांगा गया है। आईटी नियमों को और सख्त करने का प्रस्ताव रखने के साथ ही कई अहम मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा के बाद मेटा ने यह भी स्वीकार किया कि बहुत सारा गैरकानूनी कंटेंट प्रमोट किया गया और खास ऑडियंस के लिए पेड प्रमोशन किए गए। ज्ञात हो कि इन्हीं दिनों फेसबुक और इंस्टाग्राम की मनमानियों पर अमेरिकी अदालत ने भी एक अहम निर्णय दिया है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ और सुरक्षा में गंभीर चूक के बाद मेटा को अरबों रुपये का हर्जाना भरने का आदेश दिया गया है। यह सख्त निर्णय इस कंपनी द्वारा अपने फायदे के लिए बच्चों की सुरक्षा, गोपनीयता और मानसिक सेहत को पूरी तरह दरकिनार करने के गंभीर आरोपों के बाद आया है गौरतलब है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एवं फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट को भी कुछ समय के लिए हटाने के साथ-साथ बच्चों के यौन शोषण वाले कंटेंट, डीपफेक और बहुत सारा पैसा लेकर कुछ खास सामग्री को बढ़ावा देने जैसी खामियों के लिए माफी मांगी है। ज्ञात हो कि जेन जी आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं से की गई अपील वाले वीडियो संदेश मेटा ने हटा दिया था। मोदी की पोस्ट को तकनीकी समस्या (ऑटोमेटेड फ़िल्टर की त्रुटि) से इसका कारण बताकर कुछ देर बाद बहाल कर दिया था। वहीं न्यू मैक्सिको की एक शीर्ष अदालत के बाद अमेरिका में भी मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने सार्वजनिक रूप से गलती मानते हुए प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से जुड़ी सामग्री को रोकने में व्यवस्थागत असफलता की बात स्वीकार की है। साथ ही इस लापरवाही के लिए सुरक्षा प्रणालियों को बेहतर बनाने का आश्वासन भी दिया है। दरअसल, बात माफी मांगने से कहीं ज्यादा जवाबदेही लेने की है। इसके लिए कड़े नियम भी जरूरी हैं और मेटा कंपनी में दायित्वबोध का भाव भी। हालिया वर्षों में देश में होने वाली राजनीतिक घटनाएं हों या चर्चित चेहरों जुड़ा कंटेन्ट। बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री हो या कंटेंट मॉडरेशन अपने फायदे के अनुसार नकारात्मक सामग्री को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखती है। यही वजह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सोशल मीडिया कंपनी मेटा को कथित पोर्नोग्राफ़ी और अनुचित आयुवर्ग से संबन्धित सामग्री अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाने के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। इसका सीधा सार अर्थ है कि इन प्लेटफॉर्म पर पॉक्सो कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। ज्ञात हो कि यह नोटिस इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल की श्रेणी के तहत आ सकते हैं। ज्ञात हो कि 2025 में भी सोशल मीडिया पर बच्चों के अश्लील वीडियो परोसे जाने को लेकर सरकार ने आपत्ति जताई गई थी। बावजूद इसके ऐसी सामग्री को लेकर लापरवाही जारी है। समझना मुश्किल नहीं कि हमारे देश में ही नहीं, दुनियाभर में एल्गोरिदम का खेल खेलने वाली टेक कंपनी मेटा के सभी मंचों पर मुनाफे की सोच हावी है। विचारणीय है कि हमारे देश में सोशल मीडिया पर परोसी या प्रमोट की जाने वाली सामग्री से कई चिंताएं और चुनौतियां जुड़ी हैं। भारत में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप पर करीब 56 करोड़, यू-ट्यूब पर करीब 50 करोड़, इंस्टाग्राम पर 48 करोड़, फेसबुक पर 40 करोड़, स्नैपचैट पर 21 करोड़ और एक्स पर 2 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं। इनमें यूजर्स में युवाओं की संख्या ज्यादा है। अकेले इंस्टाग्राम पर 18 से 24 आयु वर्ग के 64 प्रतिशत युवा हैं। ऐसे में यहां साझा की जा रही सामग्री न केवल देश की बड़ी आबादी को प्रभावित करती है बल्कि सामाजिक-पारिवारिक और राजनीतिक स्वीकार की दिशा से जुड़ी है। यही वजह है कि इनके नैतिक दायित्वों को याद दिलाने के साथ ही सख्त नियम बनाने और उनका पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हो चला है। मेटा कंपनी के मनमानी रवैए पर केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में उसके जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, उन्हें भारतीय कानून का पालन करना ही होगा। साथ ही इस पहलू से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए हर कदम उठाना होगा।

(लेखिका स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जब मन अशांत हो, इष्टदेव के मंत्रों का करें जप

संकलित
दर्शन

शुकदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय राजा ने पूछा कि आजकल लोग इतने बेचैन क्यों हैं? लोगों का मन अशांत क्यों है? शुकदेव ने राजा को एक कथा सुनाई कि एक दिन पृथ्वी ने भी भगवान से यही बात पूछी थी। पृथ्वी ने भगवान से कहा था कि ये लोग जो खुद मौत के खिलौने हैं। ये सभी मुझे यानी धरती, राज्य जीतना चाहते हैं। अभी तक मुझे यानी धरती को कोई भी मृत्यु के बाद अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सका है। लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? शुकदेव ने राजा से कहा कि पृथ्वी ने ये सभी बातें भगवान से इसलिए कहीं थीं, कि धरती पर जो धन-संपत्ति है, वही सारे झगड़ों की जड़ है। सभी चाहते हैं कि मेरे पास दूसरों से ज्यादा वैभव हो, सभी इसी में लगे हुए हैं। जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। परीक्षित ने शुकदेव की बातें ध्यान से सुनीं और कहा कि आजकल इतनी अशांति है तो शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुकदेव ने कहा कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए, ध्यान, पूजा-पाठ करना चाहिए। अपने इष्टदेव के नामों का जप करने से नकारात्मकता दूर होती है, मन शांत होता है। मंत्र जप से शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उनसे मन शांत होता है।

कपड़े की उपयोगिता दिखावे के लिए नहीं

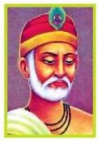

संकलित
प्रेरणा

संत कबीर रोज अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश दिया करते थे। कबीर जी के उपदेश सुनने एक धनी व्यक्ति भी आता था। धनी व्यक्ति कबीर दास जी से बहुत प्रभावित था। एक दिन उस धनी व्यक्ति ने देखा कि कबीर दास जी जो कुर्ता पहनते हैं, वह बहुत पुराना हो गया और कुर्ता बहुत ही सामान्य कपड़े से बना था। अगले दिन धनी व्यक्ति एक मूल्यवान कुर्ता लेकर पहुंचा और कबीर दास को उपहार में दे दिया। कुर्ता मखमल से बना था। बाहर की ओर से कुर्ता मखमली था और अंदर की ओर उसमें सामान्य कपड़ा लगा था। धनी व्यक्ति ने सोचा था कि अब कबीर दास जी उसका दिया हुआ कुर्ता पहनेंगे। अगले दिन जब वह व्यक्ति फिर से कबीर दास जी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कबीर जी ने उल्टा कुर्ता पहना है। दरअसल, कबीर दास जी के कुर्ते का मलमल वाला हिस्सा अंदर की ओर था और बाहर सामान्य कपड़ा दिख रहा था। उस धनी व्यक्ति ने कबीर जी से पूछा कि ये आपने क्या किया? आपने तो कुर्ता उल्टा पहना है? सभी लोगों ने भी कबीर दास जी से पूछा कि कुर्ता मूल्यवान है तो आपने इसे उल्टा क्यों पहना है? कबीर जी ने कहा कि ये कुर्ता देखकर मैंने सोचा कि मखमल शरीर को स्पर्श होगा तो शरीर को ज्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि ये कपड़ा तो शरीर के लिए ही है। दिखाने के लिए तो साधारण हिस्सा ही काफी है। दूसरों को हमारे कपड़ों से क्या लेना-देना?

अंतर्मन

आज की पाती

गांव की हर चीज चाहिए लेकिन गांव नहीं चाहिए

यह एक साधारण-सा वाक्य नहीं, बल्कि आधुनिक भारतीय समाज की बदलती मानसिकता का सटीक चित्रण है। हम गांव के शुद्ध दूध की बात करते हैं, देसी घी की प्रशंसा करती है, जैविक अनाज खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, गांव के फलों और सब्जियों को स्वास्थ्य का आधार मानते हैं, गांव की संस्कृति, लोकगीत, लोकनृत्य और पारंपरिक जीवन को अपनी पहचान बताते हैं, लेकिन जब स्वयं गांव में रहने की बात आती है तो अधिकांश लोग उससे दूरी बनाना चाहते हैं। यह विरोधाभास केवल जीवन-शैली का नहीं, बल्कि विकास की हमारी अवधारणा का भी प्रश्न है। भारत को सदियों से गांवों का देश कहा जाता रहा है। आज भी देश की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव कृषि पर टिकी है और कृषि गांवों के बिना संभव नहीं है। – *प्रमोद साहू, रायपुर*

करंट अफेयर

चीन में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका घटी

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को लंबे समय से अपनी उपलब्धियों में से एक बताती रही है। हालांकि, विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि चीन में हाल के वर्षों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका घटी है, खासकर राजनीतिक और नीतिगत नेतृत्व में शीर्ष स्तरों पर। चीन में सत्तारूढ़ सीपीसी ने लैंगिक समानता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर दशकों से माओ जेदोंग के इस प्रसिद्ध नारे को बढ़ावा दिया है कि महिलाएं आधा आसमान थामे हुए हैं। हालांकि, सीपीसी के मुखपत्र 'पीपुल्स डेली' में प्रकाशित विभिन्न लेखों के विश्लेषण पर आधारित एक नये अध्ययन की माने तो हाल के वर्षों में चीन के सरकारी मीडिया के विमर्श में बदलाव देखने को मिला है और इसमें मुख्य रूप से महिलाओं की घरेलू और पारिवारिक भूमिकाओं पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सीपीसी दशकों से दावा करती आ रही है कि महिलाओं ने समाजवादी आधुनिकीकरण, सुधार और खुलापन लाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। हालांकि, हांगकांग स्थित दो शोधकर्ताओं के मुताबिक, चीन के सरकारी मीडिया में 1990 के दशक के अंत में महिलाओं के चित्रण में व्यापक बदलाव दिखना शुरू हो गया।

ऑफ बीट

स्मार्ट चश्मे जिंदगी का हिस्सा बन रहे, खत्म होगी निजता

ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर ऐसे चश्मा पहने लोग अच्छी खासी संख्या में दिख जाएंगे जिससे वे आसपास की तस्वीरें और वीडियो बेहद सहजता से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी बड़ी वजह 'कैमार्ट' है, जिसने हाल में सस्ते /"कैमरा वाले चश्मे/ बाजार में उतारे हैं और ये देखते ही देखते बिक गए हैं। ये चश्मे 'कैमार्ट' के अपने ब्रांड 'आंको' के हैं जिनकी कीमत महज 89 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, जबकि 'मेटा' और 'रे-बैन' के इसी तरह के उत्पादों की कीमत 337 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से शुरू होती है। 'कैमरा वाले चश्मे' को बड़े उपभोक्ता चलन में बदलने की इस कोशिश की एक कीमत है और वह कीमत चश्मा पहनने वाले की ही नहीं, बल्कि उसके आसपास मौजूद हर व्यक्ति की निजता को चुकानी पड़ सकती है। या इनसे रिकॉर्ड की गई तस्वीरें आखिर कौन देख सकता है। यही वजह है कि शुक्रवार को संघीय अटॉर्नी-जनरल मिशेल रोलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के निजता आयुक्त से इस तकनीक की तत्काल समीक्षा करने को कहा। तो क्या मौजूदा निजता कानून तकनीक की इस नयी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत है? स्मार्ट चश्मे कोई नयी चीज नहीं हैं। गूगल ने 2013 में 'गूगल ग्लास' पेश किया था। उस समय मीडिया में इसकी खूब चर्चा हुई और कई मशहूर हस्तियों ने भी इसका समर्थन किया।

ट्रेंड

गर्व का पल

भारतीय खेलों के लिए गर्व का पल, जब हमारे युवा एथलीटों ने वैश्विक मंच पर शानदार प्रदर्शन किया ! बस्ता का हाई जंप ने भारत का पहला गोल्ड और शाहनवाज का ब्रोंज मेडल, हमारे रक्षा बलों के समर्पण, अनुशासन की मिसाल है।
- **राजनाथ सिंह**, रक्षामंत्री

रोशनी की मशाल

सिस्टम की फैलाई नई अंधेरी पिच्छा के बीच, देश के छात्रों ने अपने डर का सामना किया और रोशनी की मशाल जलाई है। अब समय आ गया है कि बीजेपी-आरएसएस और अडानी के सिस्टम को 'टाटा-बाय-बाय' कहकर खत्म कर दिया जाए।
- **राहुल गांधी**, सांसद, कांग्रेस

'हर घर तिरंगा' अभियान

'हर घर तिरंगा' अभियान हर व्यक्ति तक देशभक्ति की भावना पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। आइए, हम सब उत्साह के साथ इस अभियान से जुड़ें और 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
- **नितिन नवीन**, अध्यक्ष, भाजपा

कानून-व्यवस्था कमजोर

पश्चिम बंगाल ने विपक्षी नेताओं को डराने और उन पर हमला करने के लिए तानाशाही भारतीय जनता पार्टी ने जान-बूझकर कानून-व्यवस्था को कमजोर किया है। जैसे-जैसे मोदी सरकार की लोकप्रियता घट रही है, बीजेपी की हताशा बढ़ती जा रही है।
-**अरविंद केजरीवाल**, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

कल्पमेधा

जितना हम अध्ययन करते हैं, उतना ही हमें अपने अज्ञान का आभास होता जाता है।

- स्वामी विवेकानंद

दावों पर पानी

राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते यह उम्मीद की जाती है कि दिल्ली में अन्य शहरों के मुकाबले हर मोर्चे पर व्यवस्था बेहतर होगी। मगर इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि यहां बरसात से जुड़ी समस्याएं वर्षों से जस की तस बनी हुई हैं। गर्मी के मौसम में यहां कई इलाकों में लोग पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस जाते हैं, तो बरसात में पानी घरों और सड़कों को ही डुबो देता है। दिल्ली में सत्ता भले ही बदलती रहती है, लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव या सुधार नजर नहीं आता है। यहां नई सरकार के कमान संभालने के बाद दावे किए जा रहे थे कि शहर को जल-भराव मुक्त बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन बीते दो-तीन दिनों में दिल्ली में बारिश ने सरकार के इन दावों पर ही पानी फेर दिया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, वर्ष 2011 के बाद अगस्त के पहले सप्ताह में शुक्रवार को यहां सबसे अधिक 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जाहिर है कि जब एक घंटे की तेज बारिश में ही दिल्ली पानी-पानी हो जाती है, तो दिन भर की बरसात में क्या हाल होगा, इसके दृश्य इन दिनों कई जगह देखने को मिल रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश से एक बार फिर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कई प्रमुख सड़कें तालाब बन गईं, जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई। महरौली-बदरपुर रोड से लेकर महिपालपुर, आइटीओ, शकरपुर और छतरपुर तक की सड़कें पानी में डूब गईं। खानपुर से ओखला मोड़ के बीच कई किलोमीटर तक गाड़ियां रेंगती नजर आईं। इस दौरान यात्री घंटों जाम में फंसे रहे। इसके अलावा कई इलाकों में घरों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ीं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे थे, उनका आधार क्या था? अगर जल-भराव की समस्या को खत्म करने के लिए प्रयास किए गए, तो उनका नतीजा जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? आखिर क्या वजह है कि बारिश के पानी की निकासी से जुड़ी योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है!

गौरतलब है कि सरकार की ओर से हर साल बरसात शुरू होने से पहले सीवेज की नालियों और बड़े नालों की सफाई का जोर-शोर से अभियान शुरू किया जाता है। सवाल है कि क्या यह अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है? इसे कारगर तरीके से धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? शहर में बारिश के पानी की निकासी के माकूल बंदोबस्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका एक कारण यह भी है कि दिल्ली में जल-भराव की समस्या से निपटने के मुद्दे पर काम कम और सियासत ज्यादा होती है। हमेशा की तरह इस दफा भी यही देखने-सुनने को मिल रहा है। सरकार का दावा है कि जिन स्थानों पर पहले बहुत ज्यादा जल-भराव होता था, वहां इस बार समस्या काफी कम रही। वहीं, विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार दिक्कतों का स्थायी समाधान करने के बजाय लीपा-पोती की कोशिश कर रही है। बहरहाल, सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि अगर दिल्ली को वास्तव में जल-भराव मुक्त बनाना है, तो दावों के समांतर जमीन पर भी काम करना होगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हर स्तर पर जवाबदेही तय करनी होगी।

जोखिम का भोजन

आमतौर पर लंबी दूरी की ट्रेनों में खानपान को लेकर जिस तरह की शिकायतें आती रही हैं, वे बताती हैं कि ट्रेन से सफर या उसमें खाने-पीने को लेकर पूरी तरह सुरक्षित और निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि किसी ट्रेन में परोसे जाने वाला खाना बेहद खराब गुणवत्ता वाला था। जब कोई मामला तूल पकड़ लेता है, तब रेल महकमे की ओर से कार्रवाई होती दिखती है, लेकिन कुछ दिनों बाद स्थिति फिर पहले की तरह हो जाती है। आम ट्रेनों से लेकर राजधानी जैसी घोषित तौर पर उच्च स्तर की ट्रेनों में भी अक्सर खराब गुणवत्ता का खाना परोसे जाने की शिकायतें आती रहती हैं। वहीं रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर खाने-पीने के जो सामान बेचे जाते हैं, उनकी गुणवत्ता की हकीकत भी जगजाहिर रही है। लापरवाही से लेकर भ्रष्टाचार तक इसके कारणों की पहचान करके उस पर काबू पाने को लेकर शायद ही कभी सक्रियता दिखती है।

गौरतलब है कि केंद्रीय रेल मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि भारतीय रेलवे में हर वर्ष औसतन लगभग अट्ठावन करोड़ लोगों को खाना परोसा जाता है। इसमें गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतें सिर्फ 0.0008 फीसद ही मिलती हैं। औपचारिक शिकायतों के आधार पर पिछले तीन वर्षों में आइआरसीटीसी ने दोषी पाए गए वेंडरों पर पांच करोड़ तेरह लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। चौवन वेंडरों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और छह के अनुबंध को खत्म कर दिया गया। सरकार की ओर से अक्सर ऐसे दावे किए जाते हैं कि अब देश के लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेल यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मगर इस तरह के दावों और घोषणाओं की हकीकत क्या है, इसका अंदाजा ट्रेनों में सफर करने के बाद लग पाता है। खासतौर पर लंबी दूरी के सफर के लिए एक यात्री को किस तरह की दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, यह छिपा नहीं है। सवाल है कि अगर किसी खामी को दुरुस्त करने के लिए कोई सख्ती की जाती है, तो उसके बाद भी उस तरह की गड़बड़ी के कायम रहने की जिम्मेदारी किस पर है और इसका खमियाजा आम यात्री क्यों उठाते रहें!

बेटियों के प्रति बदलता नजरिया

भारतीय समाज में पुत्र मोह एक कड़वी सच्चाई बन कर हमारे साथ रहा है। मगर आज हवा का रुख बदल रहा है। माता-पिता का अब बेटियों के प्रति झुकाव बढ़ रहा है। यह सुखद बदलाव है।

रचना सिद्धा

कुछ समय पहले राजस्थान के नागौर जिले के सुरियास गांव में पहली बार एक बेटी का 'पाग दस्तूर' किया गया। राजस्थान की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में पिता के निधन के बाद परिवार के बड़े बेटे को परिवार का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। इसी को 'पाग दस्तूर' कहते हैं। अगर परिवार में पुत्र नहीं होता, तो कई परिवार दत्तक पुत्र लेकर यह रस्म निभाते हैं। पंद्रह जुलाई को सुरियास गांव के कान सिंह राठौड़ का बीमारी से निधन हो गया। उनके परिवार में एकमात्र संतान उनकी दस वर्षीय बेटी है। बारहवें की रस्म के बाद किसी निकट संबंधी को दत्तक लेकर 'पाग दस्तूर' कराने की चर्चा चल रही थी। मगर कान सिंह की माता और पत्नी ने साफ शब्दों में कहा कि क्योंकि उनकी एकमात्र संतान पुत्री है, इसलिए उसका ही 'पाग दस्तूर' किया जाएगा। इस बदलाव से परिवार ने पुरानी परंपरा को नया स्वरूप देते हुए मजबूत संदेश दिया है कि परिवार की पहचान और सम्मान केवल बेटे से नहीं, बल्कि बेटी से भी आगे बढ़ सकता है। गांव के लोगों का भी कहना है कि इस निर्णय ने वर्षों की सामाजिक सोच में बदलाव ला दिया है जो बेटियों को बराबरी का अधिकार और सम्मान देने का संदेश देता है।

पिछले कुछ वर्षों में लड़कियों को गोद लेने का चलन बढ़ा है। इस बात की पुष्टि करती हाल ही में जारी 'सेंट्रल अडाप्शन रिसोर्स अथारिटी' की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष के मुकाबले वर्ष 2025-26 में लड़कियों को गोद लेने वालों की संख्या में आठ फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वह समय बीत गया, जब बेटियों को बोझ माना जाता था और बेटों को परिवार का सम्मान। तब बेटियां पराया धन मानी जाती थी और बेटे को वंश को आगे बढ़ाने वाला और बुढ़ापे का सहारा बनने वाला कहा जाता था। यहां तक कि अंतिम संस्कार बेटों के हाथों से होने पर मुक्ति मिलने की सोच हमारी मानसिकता पर हावी थी। इसी मानसिकता के प्रभाव में हमने सदियों तक लड़कियों को दोयम दर्जे का नागरिक बना कर रखा।

सदियों से भारतीय समाज में पुत्र मोह एक कड़वी सच्चाई बन कर हमारे साथ रहा है। मगर आज हवा का रुख बदल रहा है। आधुनिक भारत में यह एक नया और सुखद बदलाव दिखाई दे रहा है। न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में समाज की सोच में तेजी से बदलाव आ रहा है। पहले जहां बेटों को प्राथमिकता दी जाती थी वहीं अब बेटियों के प्रति झुकाव बढ़ रहा है। एक विश्लेषण के मुताबिक 1980 से अब तक करीब पांच करोड़ बेटियां जन्म से पहले ही खत्म कर दी गईं। यह आंकड़ा अब तेजी से घट रहा है। विश्लेषण के मुताबिक 2001 से अब तक 70 लाख बेटियां बचाई गई हैं। चीन, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में लिंगानुपात तेजी से सामान्य होता जा रहा है। माता पिता अब बेटियों को ज्यादा समझदार, संवेदनशील और कम चुनौतीपूर्ण मानने लगे हैं।

कई देशों में अब यह धारणा भी जोर पकड़ती जा रही है कि बेटियां बुजुर्ग माता-पिता की बेहतर देखभाल करती हैं। यह सोच भारत में भी तेजी से बढ़ रही है और शायद यही कारण है कि अब एक संतान बेटी हो जाने के बाद भी दंपति लड़के के लिए दूसरी संतान के बारे में नहीं सोचते। यह समाज की सोच में आया एक सकारात्मक बदलाव नहीं, बल्कि सोच की उस संकीर्णता पर भी करारी चोट है जिसने लंबे समय तक बेटियों को 'पराया धन' मान कर हाशिये पर रखा। इस सकारात्मक बदलाव के पीछे कई अहम कारण हैं, जिसने लोगों की मानसिकता को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है।

> **न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेटियों को लेकर जो स्वीकार्यता और ललक बढ़ी है, वह उम्मीद जगाने वाली है। हालांकि देश के दूरदराज इलाकों में आज भी कुछ कुरीतियां और भेदभाव के अंश बाकी हैं। कुछ क्षेत्रों में अब भी लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह और शिक्षा से वंचित कर दिए जाने जैसी समस्याएं मौजूद हैं। बदलाव के लिए जो हमारी गति है, उससे मंजिल बहुत दूर नहीं लगती। जब समाज बेटियों को बोझ नहीं, बल्कि एक वरदान के रूप में देखने लगता है, तब केवल एक परिवार और समाज का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का उत्थान होता है। इसलिए बेटियों को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करना हम सभी की जिम्मेदारी है।**

आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष तक, कारपोरेट के बोर्डरूम से लेकर सीमा की सुरक्षा तक हर जगह बेटियों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। ओलंपिक पदकों से लेकर सिविल सेवाओं तक, जब माता-पिता हर जगह बेटियों का परचम लहराते देखते हैं, तो उनका गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिले, तो बेटियां आसमान छू सकती हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि अवसर मिलने पर वे किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। उनकी सफलता ने समाज की पुरानी धारणाओं को तोड़ते हुए बेटियों के प्रति सम्मान और भरोसे को मजबूत किया है।

अक्सर देखा जाता है कि बेटियां शादी के बाद भी अपने माता-पिता के प्रति उतनी ही संवेदनशील और जिम्मेदार रहती हैं, जितना कि शादी से पहले थीं। बुढ़ापे में माता-पिता की देखभाल करने और उनका भावनात्मक सहारा बनने में बेटियां किसी से कम साबित नहीं हो रही हैं। समाज में अब यह बात गहराई से महसूस की जाने लगी है कि बेटा केवल एक कुल का नाम आगे बढ़ाता है, लेकिन बेटी दो-दो परिवारों को रोशन करती है।

साक्षरता दर में वृद्धि और कानून के प्रति बढ़ती जागरूकता ने भी इस बदलाव की नींव रखी है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे सरकारी अभियानों, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ सख्त कानून और संपत्ति में बेटियों के समान अधिकार जैसे विधायी कदमों ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं ने भी इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने का कार्य किया है। कई राज्यों में कन्या जन्म पर आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, निशुल्क शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रोत्साहन जैसी योजनाओं ने परिवारों को बेटियों के भविष्य के प्रति आश्वस्त किया है।

आजकल के छोटे या एकल परिवारों में माता-पिता लिंग भेद से परे जाकर केवल एक या दो बच्चों की परवरिश पर ध्यान दे रहे हैं। अब लोग इस बात से पूरी तरह बेफिक्र हैं कि उनका इकलौता बच्चा बेटा है या बेटी। वे बेटी की परवरिश भी उसी लाड़-प्यार, शिक्षा और संसाधनों के साथ कर रहे हैं जो कभी सिर्फ बेटों का हक समझा जाता था।

इस यात्रा को पूरा होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेटियों को लेकर जो स्वीकार्यता और ललक बढ़ी है, वह उम्मीद जगाने वाली है। हालांकि देश के दूरदराज इलाकों में आज भी कुछ कुरीतियां और भेदभाव के अंश बाकी हैं। कुछ क्षेत्रों में अब भी लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह और शिक्षा से वंचित कर दिए जाने जैसी समस्याएं मौजूद हैं। बदलाव के लिए जो हमारी गति है, उससे मंजिल बहुत दूर नहीं लगती। जब समाज बेटियों को बोझ नहीं, बल्कि एक वरदान के रूप में देखने लगता है, तब केवल एक परिवार और समाज का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का उत्थान होता है। इसलिए बेटियों को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। बेटियों की बढ़ती चाह एक समृद्ध, समतावादी और संवेदनशील भारत के निर्माण का सबसे सशक्त प्रतीक है।

न्याय की संवेदना

आलोक यात्री

आधी सदी पहले दुष्यंत कुमार ने एक शेर कहा था- 'भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेर-ए-बहस ये मुद्दआ।' एक अदालती फैसला सामने आने के बाद यह बात शिद्दत से महसूस हो रही है कि आधी सदी बाद भी यह शेर और परिस्थितियां अपनी जगह जस की तस खड़ी हैं। गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में साहित्यकारों और विचारकों को भी उद्धृत किया। मामला दो साल की एक बच्ची की हत्या से जुड़ा है। रोटी मांगने पर मां ने बच्ची की कथित रूप से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। चार महीने बाद आरोपी मां को अदालत ने जमानत दे दी। इस मामले में एक हत्यारोपी को जमानत मिलना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी अहम है गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणी।

अपने फैसले में किसी न्यायाधीश को पहली बार विश्व विख्यात लेखकों को उद्धृत करते हुए देखना समाज की ओर एक नई खिड़की खुलने जैसा सुखद अहसास है। उच्च न्यायालय की पीठ ने इस प्रकरण को दिल दहला देने वाली घटना बताते हुए कहा कि भूख केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा, न्याय और जमीर का मामला है। अदालत ने इसे समाज और व्यवस्था की सामूहिक विफलता करार देते हुए कहा कि भूख जब एक मां को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करे, तो यह केवल अपराध नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय का गंभीर विषय है।

अत्यधिक गरीबी के प्रभाव को समझने के लिए अदालत ने अपने फैसले में विश्व विख्यात लेखकों पन्नालाल पटेल, चार्ल्स डिकेंस, विक्टर ह्यूगो और महात्मा गांधी के विचारों तथा तर्कों का हवाला दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी मां ने मार्च 2026 में बेटी द्वारा बार-बार खाना मांगने पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी थी। बचाव पक्ष का कहना था कि तीन बच्चों की मां, जिसे उसका पति छोड़ चुका था, अत्यधिक गरीबी, भुखमरी और सात महीने की गर्भावस्था से जूझ रही थी। आरोपी मां की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए अपने फैसले में अदालत में दो विश्वविख्यात उपन्यासों, पन्नालाल पटेल के गुजराती उपन्यास 'मानवीनी भवाई' और विक्टर ह्यूगो के उपन्यास 'लेस मिजरेबल्स' का हवाला दिया गया। न्यायमूर्ति हसमुख डी सुथार की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि भुखमरी जब किसी मां को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर देती है, तो यह विफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की होती है। इस दुखद घटना को करुणा और इस बात के पुख्ता संकल्प के तौर पर देखा जाना चाहिए कि कोई भी मां या बच्चा भुखमरी की पीड़ा सहने को मजबूर न हो।

फैसले में उद्धृत उपन्यासों में से एक में पन्नालाल पटेल ने भीषण भूख और सामाजिक व्यवस्था के ढहने से पैदा होने वाले मनोवैज्ञानिक डर को रेखांकित किया है। जबकि विक्टर ह्यूगो ने उन्नीसवीं सदी के फ्रांस में गरीब, दबे-कुचले और समाज के हाशिये पर धकेल दिए गए लोगों की जिंदगी और संघर्ष को दर्शाया है। चार्ल्स डिकेंस ने भी उन्नीसवीं सदी के औद्योगिक ब्रिटेन में भूख, गरीबी और सामाजिक न्याय को बहुत करीब से देखा और अपनी रचनाओं में उसे गहराई से उभारा है। उनका यह कथन खास ध्यान देने योग्य है 'चमचमाते और खुशहाल लंदन के नीचे एक अंधेरा, भूखा और रोता हुआ लंदन भी बसता है।' एक जगह वे लिखते हैं- 'भूख उन दीवारों को भी तोड़ देती है, जिन्हें कानून नहीं लांघ सकता।' अपने फैसले में अदालत ने महात्मा गांधी और ब्रितानी लेखक चार्ल्स डिकेंस के कथनों के अलावा हिंदू, मुसलिम और ईसाई धर्म ग्रंथों का भी उल्लेख किया, जिसमें भूखे को खाना खिलाने को एक पवित्र कर्तव्य बताया गया है। इस क्रम में महात्मा गांधी के इस उदाहरण को इंगित किया गया कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, जो इतने भूखे हैं कि उन्हें भगवान रोटी के रूप में ही दिखाई दे सकते हैं।

सभी धर्म यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति को भूख से मरने देना न केवल एक सामाजिक विफलता है, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक विफलता भी है। यह घटना दिल दहला देने वाली होने के साथ-साथ यह भी याद दिलाती है कि भूख महज आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा, न्याय और अंतरात्मा का मामला है। साथ ही यह घटना केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है, बल्कि समाज पर एक गंभीर आरोप है और यह सामाजिक न्याय एवं नैतिकता से जुड़े बुनियादी सवाल खड़े करती है। फैसले में पीठ ने टिप्पणी की कि 'इस अदालत का मानना है कि सामाजिक न्याय इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर इंसान को भोजन, रहने की जगह, स्वास्थ्य सेवा और सम्मान जैसी बुनियादी जरूरतें मिलनी चाहिए। भुखमरी के कारण जब कोई मां इतना कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है, तो यह किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की विफलता होती है।' अदालत ने यह भी कहा कि यह घटना सामाजिक कल्याण व्यवस्था की विफलता को भी दर्शाती है और कमजोर परिवारों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य और समाज की नैतिक जिम्मेदारी को उजागर करती है। भारतीय संविधान के तहत बच्चों को छह साल की आयु पूरी होने तक शुरुआती बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना राज्य सरकार का कर्तव्य है।

शायद यह पहला अवसर है जब अदालत ने लेखकों को उद्धृत किया है। अब देखना यह है कि नैतिकता और जुर्म के दो पलड़ों पर टिके इस प्रकरण का परिणाम संविधान की किताब से निर्धारित होगा या शासकीय विफलता भी इस हत्या की दोषी मानी जाएगी।

दुनिया मेरे आगे

> **स भी धर्म यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति को भूख से मरने देना न केवल एक सामाजिक विफलता है, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक विफलता भी है। यह घटना दिल दहला देने वाली होने के साथ-साथ यह भी याद दिलाती है कि भूख महज आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा, न्याय और अंतरात्मा का मामला है।**

नतीजों का संदेश

विधानसभा उपचुनावों के परिणामों को केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। गुजरात में मिली जीत के पीछे प्रभावशाली पटेल समुदाय का समर्थन और स्थानीय सामाजिक समीकरण हावी रहे। मध्य प्रदेश की दतिया सीट का परिणाम भी क्षेत्रीय कारकों से प्रभावित रहा, लेकिन सबसे अधिक राजनीतिक महत्त्व बिहार की बांकीपुर सीट के परिणाम का है। पिछले तीन दशकों से अधिक समय से यह सीट भाजपा के कब्जे में रही। साथ ही यह बिहार की सबसे अधिक शिक्षित विधानसभा सीटों में भी गिनी जाती है। जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसे अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया था। उनका मानना था कि बांकीपुर का जनादेश उस हांडी के चावल की तरह होगा, जिससे पूरे बिहार की राजनीतिक दिशा का अनुमान लगाया जा सके। चुनाव परिणाम ने इस धारणा को काफी हद तक पुष्ट किया है। यह नतीजा भाजपा के लिए आत्ममंथन का अवसर भी है। यदि जनता को यह महसूस होने लगे कि उसकी अपेक्षाओं को महत्त्व नहीं दिया जा रहा और युवाओं की बेचैनी को अनदेखा किया जा रहा है, तो उसका असर चुनावी परिणामों में दिखाई देना स्वाभाविक है।

- खुमानसिंह चुंडावत, मंदसौर

खतरे में कल्पवृक्ष

'कल्पवृक्ष खेजड़ी के संरक्षण की दरकार' (आलेख, 5 अगस्त) पढ़ा। खेजड़ी थार के रेगिस्तान का जीवन-तंत्र, जैव विविधता का संवाहक और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अमर प्रतीक है। रेगिस्तान के प्राकृतिक संतुलन में खेजड़ी की भूमिका अनुपम है। यह मिट्टी के कटाव को रोकने, भूजल की आर्द्रता बनाए रखने और भूमि की उर्वरता बढ़ाने का काम करता है। भीषण ग्रीष्मकाल में जब वनस्पति सूखने लगती है, तब खेजड़ी के पत्ते पशुओं के लिए आहार बनते हैं और इसकी पौष्टिक फलियां ('सांगरी') मनुष्य के पोषण का सहारा बनती हैं। मगर यह चिंताजनक है कि बीते सात दशकों में इसका क्षेत्रफल 19 लाख हेक्टेयर से घट कर मात्र 3.20 लाख हेक्टेयर रह गया है। अंधाधुंध कटाई, घटता भूजल और अनियोजित शहरीकरण इस जीवनदायी कल्पवृक्ष के अस्तित्व को लील रहे हैं। यदि आज यह वृक्ष संकट में है, तो यह हमारी सामूहिक चेतना पर बड़ा प्रश्नचिह्न है।

- मनोज वशिष्ठ, रेवाड़ी

नई पीढ़ी की फिक्र

'शिक्षा में बुनियादी सुधार की जरूरत' (आलेख, 6 अगस्त) पढ़ा। आजादी के 79 वर्ष बाद भी शिक्षा में बुनियादी सुधार की बात ही हो रही है, यह जानते हुए भी कि भारत कभी विश्व गुरु रहा है। दुनिया के कई देशों से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आते थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वस्तरीय शिक्षा केंद्र हमारे यहां मौजूद थे। मगर मैकाले की शिक्षा व्यवस्था ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम न तो अपनी शैक्षणिक धरोहर को सुरक्षित रख पाए और न ही डिजिटल होती दुनिया के साथ चल सके। परिणाम यह हुआ कि आज की शिक्षा व्यवस्था बच्चों से उनका बचपन छीन रही है। अंक आधारित शिक्षा नई पीढ़ी को तनाव और कुंठा के गर्त में धकेल रही है। मोटे रैकेज की लालसा में देश की प्रतिभाएं विदेश जाकर बस रही हैं। जबकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि बच्चों को व्यावहारिक रूप से सक्षम बनाया जाए। हमें व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण जैसी शिक्षा व्यवस्था की ओर लौटना ही उचित होगा ।

- श्रीकांत द्विवेदी, धार

सुरक्षा का सवाल

'जोखिम का सफर' (संपादकीय, 6 अगस्त) पढ़ा। हवाई यात्रा आज केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन, पर्यटन, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संपर्क का अत्यंत विश्वसनीय माध्यम बन चुकी है। प्रतिदिन लाखों यात्री इस विश्वास के साथ विमान में यात्रा करते हैं कि उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसलिए विमानन क्षेत्र से जुड़ी प्रत्येक घटना केवल एक समाचार नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था के लिए आत्ममंथन का विषय बन जाती है। हाल ही में फुकेत से भारत आ रहे एअर इंडिया के एक विमान से संबंधित घटना याद दिलाती है कि विमानन क्षेत्र में सतर्कता का कोई विकल्प नहीं हो सकता। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, विमानन कंपनियों तथा संबंधित सभी संस्थाओं का यह दायित्व है कि वे सुरक्षा व्यवस्था को निरंतर अद्यतन और सुदृढ़ बनाए रखें।

- अशोक, पटना, बिहार

हिन्दुस्तान 1936

एयर टैक्सी की ओर

भारतीय आकाश में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा का सपना साकार होने की ओर बढ़ चला है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने विश्वास जताया है कि भारत में 2028 तक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू हो जाएगी। इस उभरती तकनीक के जमीनी परीक्षण में अगले साल तेजी आ जाएगी। बेंगलुरु में एक आधुनिक उपक्रम सरला एविएशन के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर नायडू ने पूरे उत्साह से सूचित किया कि ये एयर टैक्सी वास्तव में इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (ईवीटीओएल) यान होगी। ऐसे यान या एयर टैक्सी का इस्तेमाल भारत के भीड़ भरे महानगरों के ज्यादा मुफीद होगा। इन शहरों की सड़कों पर अक्सर जाम की स्थिति रहती है। जब किसी को जल्दी होगी, तब एयर टैक्सी काम आएगी। कबड्डी खेलने बराबर जगह पर यह टैक्सी आसमान से जमीन पर सीधे उतर सकेगी और सीधे ऊपर उठकर मंजिल की ओर उड़ सकेगी।

गौर करने की बात है, सरला एविएशन ने एयर टैक्सी के मॉडल तैयार किए हैं और अगले साल कंपनी परीक्षण का काम शुरू कर देगी। टैक्सी के विकास और परीक्षण पर सरकार की पूरी नजर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय व विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) परीक्षण, सुरक्षा और नियमों पर उद्योग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एयर टैक्सी के आकार-प्रकार को मंजूरी मिल गई है। कोई आश्चर्य नहीं, इसमें ड्रोन, हेलीकॉप्टर और पारंपरिक विमान की तकनीक का समायोजन होगा। 'पावर्ड लिफ्ट' के रूप में वर्गीकृत इस टैक्सी में पायलट सहित छह लोग सवार हो सकेंगे। इसमें सात इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होगा। छह मोटर इसे ऊपर उठाने या उठाए रखने के साथ ही नीचे लाने का काम करेंगे, जबकि एक मोटर इसे आगे बढ़ाने या पीछे करने के लिए समर्पित रहेगा। यह टैक्सी किसी प्रकार के तरल या गैस ईंधन से नहीं, सुरक्षित ऊर्जा- इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलेगी। इसके अलावा इसमें एक ऐसे जनरेटर को जोड़ने की सुविधा शामिल की जा सकती है, जिससे चलते-उड़ते इसकी बैटरी को चार्ज करना संभव हो जाएगा।

इसमें ड्रोन, हेलीकॉप्टर और पारंपरिक विमान की तकनीकों का समायोजन होगा। 'पावर्ड लिफ्ट' के रूप में वर्गीकृत इस टैक्सी में पायलट सहित छह लोग सवार हो सकेंगे।

यह एक बेहतरीन नवाचार है, जिसकी मदद भारत के अनेक निवेशक व उद्यमी कर रहे हैं। यह तकनीक पूरी तरह से भारत में विकसित हो रही है। इसकी कामयाबी भारतीय उद्योग जगत ही नहीं, भारतीय विज्ञान को भी बल प्रदान करेगी। सबसे बड़ी बात, यह एयर टैक्सी दुनिया में सबसे किफायती होगी। इसकी ओर बहुत महत्वाकांक्षा से देखा जा रहा है। विशेष रूप से चिकित्सा और एंबुलेंस सेवा को इससे बहुत ताकत मिलेगी। बहुमूल्य समय बचेगा और दो घंटे का सफर आधे घंटे में तय हो जाएगा। एयर टैक्सी बना रही कंपनी से अनेक अस्पतालों ने अभी से अनुबंध करना शुरू कर दिया है। यह तरक्की अचानक नहीं हुई है। आईआईटी मद्रास की प्रयोगशाला में इस पर करीब सात साल पहले काम शुरू हुआ था और अब अनेक कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं। चेन्नई स्थित ई-प्लेन कंपनी ने 2,000 किलोग्राम के एक ऐसे विमान का अनावरण किया है, जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरता है। यह एक पायलट और दो यात्रियों को ले जा सकता है और एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक उड़ सकता है। उम्मीद कीजिए, 2028 में परिचालन शुरू होने पर इस सेवा की कीमत ओला-उबर के किराए से ढाई गुना से अधिक नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ, तो भारतीय परिवहन पूरी तरह से बदल जाएगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 10 अगस्त, 1951

भारत और भूटान

जब पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के लिए उसके विरुद्ध अनर्गल प्रचार कर रहा है, तब भारतीय संसद ने प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत एक विधेयक स्वीकार किया है, जिसके अनुसार लगभग 13 वर्गमील भूमि जो इस समय भारतीय संघ की सीमा के अन्तर्गत है, भारत के पड़ोसी भूटान राज्य को सौंप दी जायेगी। पड़ोसी राज्यों के प्रति यह भारत की उदार नीति का द्योतक है। भूटान राज्य के साथ भारत ने सन् 1949 में एक संधि पर हस्ताक्षर किये थे। उसमें भारत ने वह भूमि भूटान को सौंपना स्वीकार किया था। कतिपय वैधानिक कठिनाइयों के कारण यह कार्य अभी तक सम्पन्न नहीं हो पाया।...

भूटान को इस प्रकार जो प्रदेश सौंपा जायेगा, वह इस समय आसाम राज्य की सीमा में शामिल था। भारत सरकार के सुझाव पर आसाम की राज्य सरकार ने अपनी विधानसभा की सहमति से यह प्रदेश भूटान राज्य को सौंपने के लिए अपनी स्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी थी। आसाम के लोगों ने इस बारे में संकीर्ण प्रान्तीयता की भावना से अपने को प्रभावित नहीं होने दिया और राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया, इसके लिए वे सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं। यों देखा जाये तो यह प्रदेश मूलतः भूटान राज्य का ही था और अंग्रेजों ने उससे लड़ाई करके छीन लिया था। भारत ने इस प्रदेश को लौटाने का निश्चय करके एक पुराने अन्याय का परिमार्जन कर दिया है। भूटान के लोग इस प्रदेश को धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समझते हैं; अतः उनकी धार्मिक भावनाओं को भी सन्तोष मिलेगा। इस प्रदेश में अधिकतर जंगल ही जंगल हैं और कहा जाता है, उसमें भारतीय नागरिक बिल्कुल ही नहीं हैं अथवा हैं भी, तो अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। इस छोटे से प्रदेश के अलग हो जाने से भारतीय संघ की विशालता अथवा साधन-सम्पन्नता पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसके विपरीत उसके इस त्याग का भूटान पर अच्छा असर होगा और वह भारत के अधिक निकट आ जायेगा।

भूटान कहने को पर-राज्य है, किन्तु जैसा कि नेहरूजी ने संसद में कहा, वह भारत के उतना ही निकट है, जितना भारत का और राज्य हो सकता है। सन् 1949 की संधि द्वारा एक प्रकार से भूटान ने अपना भाग्य भारत के साथ जोड़ दिया है। उसकी रक्षा का दायित्व भारत ने अपने कंधों पर ले लिया है।

साइबर अपराध रोकने की सर्वोच्च पहल

यहां स्कैन करें

प्रांजल शर्मा | डिजिटल नीति विशेषज्ञ

देश की शीर्ष अदालत ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी पर सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को चार सप्ताह के भीतर व्यापक मानक प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

मुंबई में एक व्यक्ति ने आतंक-निरोधी एजेंसी का कथित अधिकारी बनकर एक रिटायर डॉक्टर को फोन किया और आतंकियों को धन देने का आरोप लगाते हुए उन्हें 'डिजिटल अरेस्ट' कर लिया। पीड़ित डॉक्टर ने डरकर उस 'अधिकारी' को 1.3 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। दूसरी घटना में चेन्नई निवासी एक व्यक्ति से विदेशी पार्सल से जुड़े कस्टम नियमों के उल्लंघन का डर दिखाकर भारी भरकम रकम ऐंठ ली गई, जबकि उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर किया ही नहीं था।

इसी तरह, एक व्यक्ति ने खुद को साइबर क्राइम विभाग का अधिकारी बताकर एक इन्फ्लुएंसर से इंस्टाग्राम पर संपर्क किया और उन पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाकर 'जुर्माना' भरने को कहा। ये चंद उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि कैसे साइबर अपराधी लोगों को धोखा देने के लिए डर और अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे माहौल में, साइबर क्राइम में इस्तेमाल होने वाले 'म्यूल अकाउंट्स' (धोखाधड़ी से पैसे ऐंठने के लिए इस्तेमाल होने वाले खाते) पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया दिशा-निर्देश अहम हैं।

शीर्ष अदालत ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी पर सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को चार सप्ताह के भीतर 'म्यूल अकाउंट्स' से निपटने के लिए व्यापक मानक प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आरबीआई म्यूल खातों की पहचान करने, उन्हें तुरंत फ्रीज करने और उनके दुरुपयोग रोकने के लिए स्पष्ट नियम और तकनीक (जैसे एआई और मशीन लर्निंग) का उपयोग करे। सीबीआई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों की जांच करे। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश साइबर फ्रॉड को रोकें, धन वापसी मॉड्यूल का तत्काल उपयोग शुरू करें और पीड़ितों को राहत व मुआवजा दिलाएं।

इस आदेश में जांच एजेंसियों, बैंकों और राज्यों को आपसी तालमेल बढ़ाने और लोगों में जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया है। यह आदेश विशेष रूप से उन खातों के मामले में अहम है, जो अक्सर गलत केवाईसी प्रक्रिया या बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए खोले जाते हैं। न्यायालय ने इसकी खामियां दूर करने को कहा है। कुल मिलाकर, शीर्ष न्यायालय का यह आदेश एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ केंद्रीकृत, समयबद्ध और त्वरित कार्रवाई वाली प्रणाली बनाने को प्रेरित करता है।

म्यूल खाते कई तरह के होते हैं। कई मामलों में लोगों को फीस, कमीशन या आसान नौकरी का लालच देकर उनके खातों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। उन्हें यौन-अपराधों में फंसाकर, नकली पुलिस-ईडी की कॉल दिखाकर या बहला-फुसलाकर खाते का विवरण देने को मजबूर किया जाता है। कुछ ऐसे भी खाते होते हैं, जिन्हें चोरी के दस्तावेज या हैक किए गए केवाईसी डाटा का इस्तेमाल करके खोल लिए जाते हैं। साइबर अपराध में आमतौर पर डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग या नकली कॉल करके, पीड़ित को झांसा देकर किसी खाते में पैसे भिजवाए जाते हैं। इसके बाद पैसे को तत्काल 20 से 50 दूसरे खातों में भेजा जाता है या कैश, क्रिप्टो में बदला जाता है। ऐसे में, जांच एजेंसियों के लिए असली चोर का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

देश का कानून म्यूल गतिविधि को गंभीर मानता है। इसमें शामिल लोगों पर धनशोधन निरोधक कानून, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता और अगर डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल हुआ हो, तो 'सूचना-तकनीक कानून' के तहत मुकदमे चल सकते हैं। ऐसे अपराधों में लिप्त व्यक्ति का खाता फ्रीज किया जा सकता है व काली सूची में डाला जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को नए खाते खोलने या कर्ज और क्रेडिट कार्ड लेने में मुश्किलें आ सकती हैं।

बैंक और नियामक संस्थाएं कुछ खास संकेतों पर नजर रखती हैं, जैसे कोई खाता, जो पहले निष्क्रिय रही हो या जिसमें कम जमा-निकासी हो रही हो, उसमें अचानक बड़ी रकम आने लगे। इसी तरह, किसी खाते में राशि आते ही कई खातों में उसका अंतरण हो और खाताधारक इस धन का स्रोत या मकसद न बता सके, तो उसे संदिग्ध माना जाता है। अगर आपको कभी अपने खाते का इस्तेमाल करने के लिए पैसे का लालच दिया जाए या किसी ऐसे व्यक्ति के खाते से धन लेने और आगे भेजने के लिए कहा जाए, जिसे आप नहीं जानते हैं, तो वह म्यूल अकाउंट हो सकता है।

तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में साइबर अपराध बेहद चालाकी से किए जा रहे हैं। इनमें सबसे खतरनाक है 'डिजिटल अरेस्ट'। आम साइबर धोखाधड़ी से अलग डिजिटल अरेस्ट में अपराधी जांच अधिकारी के वेश में पीड़ितों को डराते-धमकाते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। अगर आपको कभी किसी सरकारी अधिकारी के नाम से कोई संदिग्ध कॉल या मैसेज आए, तो सतर्क हो जाइए। उसका मकसद आपसे पैसे लेना या आपकी संवेदनशील निजी जानकारी हासिल करना हो सकता है। माहौल बनाने के लिए पीड़ितों को अक्सर वाट्सएप या स्काइपे जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉल करने के लिए मजबूर किया जाता है। उनका भरोसा जीतने के लिए इन कॉल में थाने का बैकग्राउंड रखा जाता है।

गौरतलब है, भारतीय अपराध कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी जालसाजी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सतर्क और जागरूक रहना। यदि कोई व्यक्ति खुद को अधिकारी बताता है, तो उसका नाम, संगठन और संपर्क नंबर लेकर तुरंत छानबीन करें। वह व्यक्ति यदि तुरंत पैसे की मांग करता है, तो सवाल करें, क्योंकि वैध अधिकारी कभी भी फोन पर या ऑनलाइन पैसे की मांग नहीं करेंगे। फोन पर या ऑनलाइन आधार नंबर, बैंक विवरण या ओटीपी जैसी संवेदनशील जानकारियां न दें और कॉल, एसएमएस, वाट्सएप के माध्यम से प्राप्त संदिग्ध संदेशों और कॉल की रिपोर्ट दर्ज कराएं।

भले ही सर्वोच्च न्यायालय, आरबीआई और सरकारी एजेंसियां साइबर अपराध के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन इसके बारे में आम लोगों का जागरूक होना महत्वपूर्ण है। उन्हें फर्जी दावों और कॉल के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। साइबर धोखाधड़ी से मुकाबला करने के लिए कानूनी कार्रवाई और उपभोक्ताओं की सतर्कता, दोनों जरूरी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

शिक्षा व्यवस्था अब सुधरेगी या नए संकट में डूब जाएगी

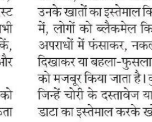

यहां स्कैन करें

पूरन डावर | चिंतक एवं विश्लेषक

देश में परीक्षा-प्रणाली में सुधार की मांग व्यापक छात्र आंदोलन के बाद तेज हुई है। छात्र पेपर लीक से कहीं अधिक नीट-यूजी परीक्षा रद्द होने से आक्रोशित थे। दरअसल, उपलब्ध तथ्यों और जांच के आधार पर सरकार और एनटीए ने स्ववंय पूरे देश की नीट-यूजी परीक्षा रद्द कर फिर से इसे कराने का फैसला लिया था। राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार इस परीक्षा को पूरी तरह निरस्त करना छात्रों को ज्यादा नागवार गुजरा।

हालांकि, हमें भावना से अधिक तथ्यों को समझना चाहिए। नीट के माध्यम से विभिन्न मेडिकल, आयुष सहित सभी पाठ्यक्रमों के लिए लगभग दो लाख सीटें उपलब्ध होती हैं, जबकि परीक्षा में करीब 23 लाख परीक्षार्थी बैठते हैं। इसका मतलब है कि लगभग 21 लाख अभ्यर्थियों को हर वर्ष निराशा हाथ लगती ही है। यह विशाल वर्ग अनेक बार शिक्षा माफिया, राजनीतिक स्वार्थों और देश-विरोधी तत्वों के लिए भावनात्मक रूप से सबसे आसान लक्ष्य बन जाता है। अभिभावकों को यह सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि अधिकतम सात-आठ प्रतिशत परीक्षार्थियों को ही सफलता मिल सकती है। शेष की असफलता उनकी प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि सीमित अवसरों का परिणाम है। दुर्भाग्य से, अत्यधिक सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण कुछ परीक्षार्थी खुदकुशी जैसा दुखद कदम तक उठा लेते हैं।

केवल पेपर लीक रोकने की नहीं, उस पूरे इको-सिस्टम को तोड़ने की जरूरत है, जो युवाओं की आकांक्षाओं को कारोबार बना देता है।

पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों को भी यही असंतुलन जन्म देता है। जब दांव बहुत बड़ा हो और सीटें सीमित हों, तब कुछ लोग अपने बच्चों को किसी भी तरह प्रवेश दिलाने का प्रयास करते हैं। यहां कोचिंग उद्योग के एक वर्ग की भूमिका की भी गंभीर जांच होनी चाहिए। आंदोलन की शुरुआती धार बड़े पैमाने पर कोचिंग संस्थानों के डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कक्षाओं और सोशल मीडिया अभियानों से आती दिखी थी। यदि इनकी गतिविधियों, इनके वित्तीय स्रोतों और आपसी समन्वय की निष्पक्ष जांच की जाए, तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे काम कर रही वास्तविक शक्तियों का पता चल सकता है। ऐसी गतिविधि में यदि कोई व्यक्ति, संस्था या संगठित नेटवर्क शामिल पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए।

सरकार ने 2024 में भी पेपर लीक को गंभीर माना था। तब सीबीआई जांच हुई थी, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई और न्यायिक प्रक्रिया भी चली। ऐसी स्थिति में 2026 में उसी मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन करना, अराजकता का वातावरण बनाना, असामाजिक तत्वों का सक्रिय होना और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक की नौबत कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि पेपर लीक को अनदेखा कर दिया गया होता, तो शायद यह विवाद इतना बड़ा नहीं बनता; पर सरकार ने कार्रवाई का रास्ता चुना।

एक और महत्वपूर्ण पक्ष पर विचार होना चाहिए। हर वर्ष सरकार नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है और निजी क्षेत्र भी लगातार क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन केवल अभ्यर्थियों की संख्या देखकर सीटें बढ़ा देना समस्या का समाधान नहीं है। प्रत्येक नई मेडिकल सीट के लिए योग्य शिक्षक, शिक्षण अस्पताल, क्लीनिकल एक्सपोजर, इंटर्नशिप, पीजी सीटें और भविष्य में रोजगार की भी आवश्यकता होती है। यदि गुणवत्ता और राष्ट्रीय जरूरत की उपेक्षा कर केवल सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो भविष्य में बेरोजगार डॉक्टरों और कमजोर चिकित्सा शिक्षा का नया संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए समाधान संतुलित, गुणवत्तापूर्ण और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तार में है।

हालिया आंदोलन युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा छल भी हो सकता है। यदि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा संगठित दबाव समूहों की सफलता के रूप में देखा जाए, तो भविष्य में ऐसे तत्वों का मनोबल और बढ़ेगा। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, पर लोकतंत्र को संगठित अपराध, आर्थिक हितों या अराजकता का बंधक नहीं बनने दिया जा सकता। सरकार को केवल पेपर लीक रोकने की नहीं, बल्कि उस पूरे इको-सिस्टम को तोड़ने की आवश्यकता है, जो युवाओं की आकांक्षाओं को अवसर नहीं, बल्कि कारोबार बना देता है। शिक्षा का उद्देश्य प्रतिभा को आगे बढ़ाना होना चाहिए, न कि निराशा का बाजार खड़ा करना।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

दान ही असली धर्म

जैसे शिवजी के गले के आसपास नाग डोलते हैं, वैसे धन के आसपास गलतफहमियां घिरी रहती हैं। धन बड़ा पेचीदा मामला बना हुआ है। एक तरफ लोग धन के लालच में डूबे जा रहे हैं, लेकिन साथ ही अपराध-बोध से भरे रहते हैं, क्योंकि धर्म सिखाते हैं कि लालच बुरा है। धन आध्यात्मिकता के खिलाफ है, क्योंकि त्याग और दान ही असली धर्म है।

इस दोहरे मापदंड से लोग न तो धन का आनंद ले पाते हैं, न उसे छोड़ पाते हैं। ओशो पहले बुद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने खुलकर धन का सम्मान किया और वे एक अमीर जीवन शैली जिए। उन्होंने आध्यात्मिकता की परिभाषा ही बदल दी, साफ कहा कि मैं धन का सम्मान करता हूं। धन मनुष्य के सबसे महान आविष्कारों में से एक है, लेकिन यह कभी मत भूलना कि यह केवल एक माध्यम है। सिर्फ नासमझों ने ही इसकी निंदा की है; शायद वे इस बात से ईर्ष्यालु थे कि दूसरों के पास पैसा है और उनके पास नहीं है। उनकी ईर्ष्या ही उनकी निंदा बन गई।

धन एक अद्भुत आविष्कार है। धन के बारे में थोपे गए सभी विचारों को छोड़ दें, इसके प्रति सम्मानजनक रहें। धन का सृजन करें, क्योंकि इसके बाद ही आपके कई अन्य आयाम खुलते हैं। गरीब आदमी के लिए सभी दरवाजे बंद हैं। धन ने मानवता की बहुत बड़ी सेवा की, क्योंकि लोग खरीदने और बेचने में सक्षम हो गए, वे अधिक से अधिक समृद्ध होते गए। इसे समझना होगा।

पैसा जितना अधिक गति करता है, चलता रहता है, आपके पास उतना ही अधिक पैसा होता है। इसीलिए पैसे को 'करेंसी' कहा जाता है। इसे 'करंट', यानी, एक धारा की तरह बहते रहना चाहिए। भारत में कहते हैं लक्ष्मी चंचला है; इसका मतलब यही है; वह एक जगह नहीं रह सकती, इसे रोककर नहीं रखना चाहिए। जैसे ही आपको यह मिले, इसे खर्च कर दें।

धन बदनाम इसलिए हुआ, क्योंकि उसके साथ आदमी की असुरक्षा का भय और लोभ जुड़ गया। इसलिए, वे उसे छिपाकर रखने लगे, ताकि बुरे वक्त में काम आए। यह धन के साथ हुआ हादसा ही है कि धन साध्य बन गया, साधन नहीं। धन तो खूब कमा लिया, लेकिन उसके बाद क्या? वह तो एक मुर्दा चीज है, उसे खर्च करने के बाद ही वह जिंदा होता है। दूसरा हादसा, वे तमाम चीजें जो धन से नहीं खरीदी जा सकतीं उनसे मनुष्य वंचित रह गया। प्रेम, शांति, आनंद, संतोष, करुणा, मैत्री, आशीर्वाद, स्वास्थ्य, इनमें से कुछ भी तो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। यही बातें आदमी को धनवान बनाती हैं, मानवीय बनाती हैं। धन तो बहुत आ गया, लेकिन आदमी गरीब हो गया। ईशावास्य में कहा गया है कि स्वर्ण के पात्र ने सत्य का मुंह ढक दिया है। वह शब्दशः सच हो रहा है।

धन एक अद्भुत आविष्कार है। धन के बारे में थोपे गए सभी विचारों को छोड़ दें, इसके प्रति सम्मानजनक रहें। धन का सृजन करें, क्योंकि इसके बाद ही आपके कई अन्य आयाम खुलते हैं।

अमृत साधना

आशुतोष राणा | अभिनेता

श्रवण मात्र सुनना नहीं है; जो सुना है, उसे समझना भी है। भ्रमण केवल घूमना नहीं है, बल्कि ऐसे घूमना है, जो हमारे भ्रम का निवारण कर सके। महादेव चराचर जगत में विचरण करते हैं, वह श्रद्धालुओं को सुनते हैं, समझते हैं और उनके भ्रम का निवारण भी करते हैं।

आभासी दुनिया में टूट रहे आधुनिक परिवार

सभ्यता को सबसे गहरा घाव किसी युद्ध, महामारी या आर्थिक संकट ने नहीं, उस चमकती स्क्रीन ने दिया है, जिसे हमने सुविधा समझकर जीवन का केंद्र बना लिया। इतिहास में पहली बार संवाद के साधन सबसे अधिक हैं, पर संवाद सबसे कम है। आवाजें हैं, पर अभिमत नहीं। हर चेहरा ऑनलाइन है, हर मन ऑफलाइन हो रहा है। यही हमारे समय का सबसे मौन, व्यापक और सबसे कम समझा गया सामाजिक पतन है। परिवारों का विघटन अब खामोशी से हो रहा है। घर दीवारों से नहीं, स्क्रीन से संचालित हैं। एक ही छत के नीचे लोग अलग-अलग डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। भारत में एक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन सात घंटे से अधिक वक्त स्क्रीन पर बिताता है। माता-पिता पांच घंटे से अधिक और बच्चे चार घंटे से ज्यादा यमय स्मार्टफोन को देते हैं। अध्ययनों में दो-तिहाई माता-पिता और आधे से अधिक बच्चों ने माना कि मोबाइल ने रिश्तों की ऊष्मा घटा दी है।

भोजन की मेज, जो कभी संवाद का केंद्र थी, अब रील्स का मंच है। बच्चे बोलना चाहते हैं, पर माता-पिता स्क्रीन पर हैं; माता-पिता संवाद चाहते हैं, तब बच्चे स्क्रॉल करते हैं। सामने बैठे व्यक्ति की उपेक्षा कर मोबाइल में डूबे रहने की आदत, यानी 'फुबिंग' सामान्य हो रही है। रिश्ते अचानक नहीं टूटते; वे पहले सुनना, फिर महसूस करना छोड़ते हैं। अंततः केवल औपचारिक संपर्क बचता है। घर अब भी हैं, लेकिन आत्मीयता 'साइलेंट मोड' में है। जनचर्चा की चौपाल अब एल्गोरिदम के दरबार में बदल चुकी है। कभी राजनीति जनसभाओं, बहसों और प्रत्यक्ष संवाद से चलती थी; आज स्क्रीन पर सिमट गई है। परिवार भी इन सबसे अछूते नहीं रहे।

सभ्यताएं एक दिन में नहीं बदलतीं; वे आदतों में बदलती हैं। पहले पत्रों की जगह संदेश आए, फिर संदेशों की जगह इमोजी ने भावनाएं ले लीं। बातचीत स्टेटस में सिमट गई और साथ होने की जगह ऑनलाइन दिखना पर्याप्त हो गया। हर सुविधा के साथ संवाद घटा। नई तकनीक ने समय तो बचाया, मगर उसने थोड़ी मनुष्यता भी छीन ली। अब असहमति को समझने से आसान 'म्यूट' कर देना, दुख बांटने से आसान उसे छिपाना और प्रेम निभाने से आसान उसे पोस्ट कर देना है। सुविधाएं धीरे-धीरे संवेदना पर भारी पड़ती गईं। आधुनिक जीवन ने नियंत्रण दिया, पर मानवीय स्पर्श छीन लिया। यही इस युग का सबसे अदृश्य सौदा है। सौभाग्य से, निर्णय हमारे हाथ में है। परिवार फोन-फ्री डिनर का नियम बना सकते हैं। कुछ पल किताबों, अखबारों को दे सकते हैं। भविष्य हमारे समाज का आकलन तकनीक से नहीं, बचाए गए संवाद से तय करेगा।

आरके जैन 'अरिजीत', शिक्षाविद

अनुलोम-विलोम

परिवार

परिजनों में जुड़ाव पहले से अधिक बढ़ा

पिछले कुछ दशकों में यह धारणा तेजी से बनी है कि आधुनिकता, शहरीकरण और तकनीकी विकास के कारण परिवार की भूमिका सीमित हो जाएगी। संयुक्त परिवारों के विघटन, एकल परिवारों के बढ़ते चलन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बढ़ते जोर ने इस सोच को बल दिया। हालांकि, आज का सच यही है कि जितनी तेजी से समाज आधुनिक हुआ है, उतनी ही तेजी से परिवार की आवश्यकता भी बढ़ी है। आज के समय में परिवार केवल एक सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा का सबसे विश्वसनीय आधार बनकर उभरा है।

कोविड-19 महामारी ने इस सच्चाई को सबसे स्पष्ट रूप में सामने रखा। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन, बीमारी और अनिश्चितता से जूझ रही थी, तब परिवार ही वह इकाई थी, जिसने अपने सदस्यों को संभाला। लाखों लोग नौकरी गंवाने के बाद अपने घर और परिवार के सहारे खड़े हो सके। बुजुर्गों की देखभाल से लेकर बच्चों की शिक्षा तक, हर क्षेत्र में परिवार ने संकटमोचक की भूमिका निभाई। महामारी के दौरान यह अनुभव हुआ कि कठिन समय में न तो सोशल मीडिया काम आता है और न ही आभासी मित्रता; परिवार ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। आज कई लोग शिकायत करते हैं कि वे आभासी दुनिया में अधिक जी रहे हैं, लेकिन यह कमजोरी उनकी है। बहुतायत में देखें, तो लोग अब पहले से कहीं अधिक परिवार का महत्व समझने लगे हैं। 'स्क्रीन टाइम' को लेकर भी उनमें जागरूकता बढ़ी है। कहना गलत नहीं होगा कि आज मानसिक स्वास्थ्य की समस्या वैश्विक चिंता का विषय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अवसाद, तनाव और अकेलेपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। महानगरों में रहने वाले अनेक युवा बेहतर वेतन और करियर के बावजूद मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। ऐसे में, परिवार भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। परिजनों का सहयोग व्यक्ति को संकट से उबरने की शक्ति देता है। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक भी मजबूत पारिवारिक संबंधों को अहम मानते हैं।

परिवार सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का प्रमुख माध्यम है। नैतिकता, अनुशासन, सहिष्णुता और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे गुण हम परिवार में ही सीखते हैं। निस्संदेह, परिवारों का स्वरूप बदल रहा है, संयुक्त परिवारों की संख्या घट रही है और एकल परिवार बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे परिवार का महत्व कम नहीं हुआ है। अलबत्ता, तकनीक ने तो दूर रहने वाले परिजनों को भी भावनात्मक रूप से जोड़े रखने में मदद की है। हमें मौजूदा समय में परिवार को हमें इसी रूप में देखना और समझना चाहिए।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

अधूरे नक्शों से पूरा न होगा सफर

बचपन से हमें सफलता की अधूरी कहानियां थमा दी जाती हैं। जब जिंदगी का नक्शा ही अधूरा हो, तो दोष अकेले मुसाफिर का कैसे हो सकता है? हम जिंदगी के जटिल रास्तों को सफलता के सरल सूत्रों में समेट देते हैं और उन पगडंडियों को छिपा देते हैं, जहां हमारा सामना रोज के संघर्षों से होता है। हमें सरल नहीं, सच्चे नक्शे चाहिए।

मुथोनी अमरान

कई हफ्तों से एक विचार बार-बार मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वह विचार है- अगर आप लोगों को अधूरे नक्शे बेच रहे हैं, तो उन्हें रास्तों से भटक जाने का दोष मत दीजिए। जितना मैं अपने आसपास देखती हूं, उतना ही यह महसूस करती हूं कि एक समाज के रूप में हमारे भीतर जो असंतोष और निराशा है, वह केवल बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता या पैसों की कमी के कारण नहीं है। उनकी जड़ उन कहानियों में भी है, जो हम एक-दूसरे को सुनाते हैं।

बचपन से ही हमें जीवन का एक नक्शा थमा दिया जाता है। वह बताया जाता है कि जिंदगी इस तरह से आगे बढ़ेगी-

'पूरे मन से पढ़ोगे, तो जिंदगी बन जाएगी।'

'मेहनत करोगे, तो सफलता जरूर मिलेगी।'

'बचत करते रहोगे, तो अमीर बन जाओगे।'

'सही जीवनसाथी मिल जाए, तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है।'

'खुद पर भरोसा रखो। सकारात्मक रहो।'

ऐसी ही कई बातें, है जो हमें बचपन से बताई जाती है। इनमें से कोई भी बात गलत नहीं है, पर पूरी तरह सच भी नहीं है।

जिंदगी की अनकही बातें

समस्या यह नहीं कि हमें क्या बताया गया है। समस्या यह है कि हमें क्या नहीं बताया गया। किसी कहानी में जो बातें छोड़ दी जाती हैं, वे भी अस्रदार होती हैं। जैसे-

- हमें नहीं बताया जाता कि सही समय भी मायने रखता है।
- हम परिवार के सहयोग का जिक्र नहीं करते।
- हम नहीं बताते कि कुछ बातें हमारे बस में नहीं होतीं।
- हम विशेष अवसरों, फायदों और मिली हुई सुविधाओं की बात नहीं करते।
- हम बीमारी, दुख और शोक के असर की बात नहीं करते।
- हम उन असफल कोशिशों की बात नहीं करते, जिन्होंने हमें सिखाया।
- हम रिश्तों व नेटवर्क की बात नहीं करते।
- हम उस जीवनसाथी की बात नहीं करते, जिसने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई, ताकि दूसरे आगे बढ़ सकें।

जीवन को पूर्णता में स्वीकारें

दो लोग बिल्कुल एक जैसे समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं, फिर भी उनके परिणाम पूरी तरह अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। दूसरे को सही समय पर एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है। एक व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म लेता है, जहां संसाधनों की कोई कमी नहीं है। दूसरा अपनी पढ़ाई ऐसे समय पूरी करता है, जब अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही होती है और नौकरियां मिलना मुश्किल होता है।

एक ही नक्शा, हर किसी को एक ही मंजिल तक नहीं पहुंचाता। फिर भी हम कहानियां ऐसे सुनाते रहते हैं, मानो सबके लिए रास्ता एक जैसा हो। शायद यही वजह है कि मैं प्रेरणादायक कहानियों से अधिक ईमानदार कहानियों की कद्र करती हूं। मुझे लगता है कि ईमानदार कहानियां ही वास्तव में सही मार्गदर्शन करती हैं।

हाल में मैंने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी देखी, जो अपने गांव में घर बना रहा था। सालों बीत गए, लेकिन वह घर आज भी अधूरा है। जिंदगी बीच में आ गई। प्राथमिकताएं बदल गईं। पैसा दूसरी जरूरतों में खर्च हो गया। मेरे लिए यह कहानी सच्ची थी, जहां सपने रोज की चुनौतियों से संघर्ष करते हैं। यह असफलता की कहानी नहीं थी, वह एक पूरा नक्शा था।

जीवन जैसी जटिल यात्रा को केवल एक फैसले, एक आदत या एक सोच तक सीमित नहीं किया जा सकता। न केवल धन। न केवल काम। न केवल विवाह। न केवल प्रतिष्ठा। एक अच्छा जीवन कई स्तंभों पर खड़ा होता है- सेहत, मित्रता, मकसद, समुदाय, विश्राम, जिज्ञासा, दूसरों के लिए योगदान, प्रेम, आर्थिक सुरक्षा और हालात के बदलने पर अपनी दिशा बदलने की आजादी।

इसके बजाय... हम लोगों को एक बेहद जटिल यात्रा के लिए एक बहुत ही सरल और सुंदर सा बना हुआ नक्शा थमा देते हैं। जब लोग उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, तो हम उन्हें ही गलत मान लेते हैं। अनुशासन या संकल्प की कमी को दोष देते हैं। बहुत कम ही लोग असफलता के अधूरे नक्शों के बारे में विचार कर पाते हैं।

यही कारण है कि अब मुझे उन तथाकथित 'सफलता के मंत्रों' से असहजता होने लगी है। लोग सफलता को कुछ ऐसे आकर्षक शीर्षकों में पेश करते हैं-

'सुबह की एक दिनचर्या, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी'

'एक आदत, जिसने सब कुछ बदल दिया'

'सफलता पाने के पांच आसान कदम'

'वह सोच, जिसने मुझे अमीर बना दिया आदि

> हमें सिर्फ प्रेरणादायक भाषणों की जरूरत नहीं है। हमें बेहतर नक्शों की जरूरत है। ऐसे नक्शे, जो अनिश्चितताओं को स्वीकार करें, पर हमें निराशावादी न बनाएं। ऐसे नक्शे, जो किस्मत के लिए भी जगह छोड़ें, पर मेहनत की अहमियत कम न करें। ऐसे नक्शे, जो दिखाएं कि एक सार्थक जीवन जीने के अनेक रास्ते हो सकते हैं।

दरअसल, हमें यह अच्छा लगता है कि अगर हमें पता चल जाए कि सफल लोगों ने ऐसा कौन-सा एक काम किया था, जिसे अपनाकर हम भी सफल हो सकते हैं। हालांकि, जिंदगी कभी इस तरह काम नहीं करती, न केन्या में, न भारत में और न ही दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में।

जीवन सरल है और जटिल भी

दूसरों की कहानियां सुनकर अगर हम यह मान रहे हैं कि सफलता केवल मेहनत का नतीजा है, तो अथक मेहनत करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलेगी, हम खुद को ही दोष देंगे। अगर हम मान लें कि खुशी का कोई तय समय होता है, तो जब जिंदगी उस समय-सारिणी के अनुसार नहीं चलेगी, तब हमें लगेगा कि हम पीछे छूट गए हैं।

अगर आप सोचते हैं कि अच्छे रिश्ते अपने आप बन जाते हैं, तो शायद यह कभी समझ न पाएं कि सच्ची दोस्ती के लिए अपना मन खोलना पड़ता है, अस्वीकार किए जाने का जोखिम उठाना पड़ता है और लगातार प्रयास करने पड़ते हैं।

अधूरे नक्शे केवल गलत जानकारी नहीं देते। वे लोगों की सोच भी बदलते हैं। शायद यही कारण है कि मैं बार-बार एक ही प्रश्न पर लौट आती हूं-हम आखिर कैसा समाज बना रहे हैं, यदि हम केवल मंजिल का जश्न मनाते हैं, पर उस रास्ते की कभी बात नहीं करते जिससे होकर वहां पहुंचा गया?

हमारी असल जिंदगी तो रास्ते में ही बीतती है। यहीं करियर रुक जाते हैं। यहीं व्यवसाय असफल होते हैं। यहीं विवाह कठिन दौर से गुजरते हैं। यहीं सेहत साथ छोड़ने लगती है। यहीं योजनाएं बदल जाती हैं। यहीं लोग चालीस, पचास या सत्तर वर्ष की उम्र में फिर से नई शुरुआत करते हैं। यहीं कोई व्यक्ति एक सुरक्षित नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि वह उसके तन-मन पर भारी पड़ रही होती है। यहीं कोई अपनी नौकरी से नाखुश होते हुए भी उसे नहीं छोड़ पाता।

यहीं है असली रास्ता। उलझा हुआ और विरोधाभासों से भरा हुआ। जिंदगी की यह राह किसी आसान निष्कर्ष में नहीं सिमटती। शायद यही वजह है कि हम इसे अपनी कहानियों से हटा देते हैं। सीधी कहानियां, उलझी हुई कहानियों से अधिक पसंद की जाती हैं, लेकिन यह आधी-अधूरी सरल कहानियां अक्सर हमारे जीवन का अच्छा नक्शा नहीं बन पातीं।

-kenyaonashoestring.co.ke

इच्छाओं के बढ़ने से कम होता सुकून

एक के बाद एक कुछ नया हासिल करने के लिए दौड़ते रहना हमें बेचैन बनाए रखता है। हर नई उपलब्धि के बावजूद हमारा मन संतुष्ट नहीं हो पाता। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस खुशी की तलाश में हम दिन-रात भागते हैं, कहीं वह पहले से ही हमारे पास तो नहीं?

कई बार हम अपने जिस चश्मे को पूरे घर में ढूंढ़ रहे होते हैं, वह हमारे सिर पर ही लगा होता है। चश्मे की ही तरह जिंदगी में अक्सर हम उन चीजों की तलाश में भटकते रहते हैं, जो चीजें हमारे पास पहले से ही होती हैं। खुशी भी कुछ ऐसी ही है।

कुछ लोगों को अपनी खुशी नई कार, बड़ा घर या महंगे सामान में मिलती है। कुछ के लिए पदोन्नति, महंगे कपड़े या दूसरों से आगे निकलना ही सफलता है। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि एक लक्ष्य पूरा होते ही मन अगले लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ता है, इसलिए संतुष्टि कभी टिकती नहीं। हम कुछ और पाने की चाह में यह भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है, वह भी शायद पर्याप्त है।

हमारे आसपास बहुत से लोग और कई बार हम स्वयं भी अपनी सफलता और संपन्नता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। मानो दुनिया से कहना चाहते हों, 'देखो, मैं सफल हूं और आपसे बहुत आगे हूं।' हालांकि, सफलता की इस कमी न खत्म होने वाली दौड़ की हमें कीमत भी चुकानी पड़ती है। जीवन में तनाव, चिंता, असंतोष और उन रिश्तों से दूरी बढ़ने लगती है, जो हमारे जीवन को वास्तव में खुशहाल बनाते हैं।

सुकून के दुश्मन

लोकप्रिय बनने की चाह : कई लोग सम्मान से ज्यादा लोकप्रिय दिखना चाहते हैं। दिखावा धीरे-धीरे आत्मसम्मान की जगह ले लेता है।

हर समय तुलना करना : ऐसे लोग अपनी कीमत इस बात से तय करते हैं कि वे दूसरों से कितने आगे या पीछे हैं।

रिश्तों से ज्यादा चीजों को महत्व देना : सफलता का मतलब सिर्फ पैसा और महंगे सामान नहीं है। असली सफलता अच्छे रिश्ते, यादगार पल और दूसरों के जीवन पर सकारात्मक असर छोड़ना है।

इच्छा और जरूरत में अंतर : लोग कई बार अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर बैठते हैं। वित्तीय विशेषज्ञ डेव रैमसे कहते हैं, 'हम उन चीजों को खरीदते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, उस पैसे से जो हमारे पास नहीं होता, ताकि उन लोगों को प्रभावित कर सकें, जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते।'

जो है, उसकी कद्र न करना : छोटी-छोटी खुशियां, सच्चे दोस्त व परिवार का साथ पीछे छूट जाता है, क्योंकि नजर हमेशा अगली उपलब्धि पर टिकी रहती है।

बढ़ जाती वर्तमान से दूरी

'और अधिक' पाने की यह आदत केवल आर्थिक बोझ नहीं बढ़ाती, बल्कि मानसिक शांति भी छीन लेती है। कर्ज, तनाव और लगातार बेहतर बनने की होड़, हमें उन चीजों से दूर कर देते हैं, जो वास्तव में कीमती हैं। जब पूरा ध्यान भविष्य की अगली उपलब्धि पर होता है, तो वर्तमान की खुशियां अनदेखी रह जाती हैं। धीरे-धीरे हमारी अपनी इच्छाएं तनाव का सबसे बड़ा कारण बन जाती हैं।

फ्रैंक सोनेनबर्ग

franksonnenbergonline.com

चुनाव आपको ही करना होगा

आखिरकार जीवन हमें दो ही रास्ते देता है-

पहला, दूसरों की स्वीकृति से ज्यादा अपने आप पर गर्व करना सीखिए। अगर आप अपने व्यक्तित्व और अपने काम से संतुष्ट हैं, तो वही सबसे बड़ी सफलता है।

दूसरा, यह समझिए कि हर बार अधिक होना ही बेहतर नहीं होता। असली खुशी तब मिलती है, जब इंसान यह कहना सीख जाए-'मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है।'

जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करना सीख लेता है, उसे हर समय कुछ नया पाने की बेचैनी नहीं सताती। अंत में चुनाव आपका है-या तो पूरी जिंदगी अगली उपलब्धि के पीछे भागते रहिए या फिर पहचानिए कि आपके लिए कितना पर्याप्त है? असली खुशी इसी संतुष्टि में छिपी है।

विविध

मन की थकान हावी न होने दें

मन की थकान चुपके से दस्तक देती है और भीतर ही बढ़ती रहती है। लंबे समय तक दबी हुई भावनाएं और हर चीज काबू में करने की कोशिश भीतर से खाली कर सकती है। इस भावनात्मक थकान से कैसे उबरें, आइए जानें-

तन की थकान दिख जाती है, पर भीतर बढ़ती मन की थकान आसानी से समझ नहीं आती। कई बार यह थकान सामान्य काम न संभाल पाना, समय पर काम पूरे न होना या रोज के छोटे-छोटे फैसले लेने में परेशानी होने के रूप में भी सामने आती है। खासकर, भावनात्मक थकान तो सफल, अति-सक्रिय, समय पर काम पूरा करने वाले और दूसरों का खयाल रखने वालों में बड़े स्तर पर दिखती है। ऐसे में बाहर से सब सामान्य नजर आता है, पर भीतर से एक खालीपन और बेचैनी बढ़ती जाती है।

भावनात्मक थकान कमजोरी या असफलता नहीं है। यह एक चेतावनी है, जिसे पहचानना जरूरी है।

भावनात्मक थकान के लक्षणों को पहचानें

बढ़ता चिड़चिड़ापन : उन सामान्य कामों को करना कठिन हो जाना, जो पहले आसानी से हो जाते थे। काम वही रहता है, बस भीतर की ऊर्जा व सहनशीलता कम हो जाती है।

भावनात्मक दूरी : आप सामाजिक या पेशेवर सभी काम रहे होते हैं, पर उससे जुड़ाव कम हो जाता है। बातचीत औपचारिकता बन जाती है। खुशियां फीकी लगने लगती हैं।

बहुत अधिक सोचना : जब हम लंबे समय से तनाव से जूझ रहे होते हैं, तो हर चीज काबू करने की कोशिश में बहुत अधिक सोचने लगते हैं। लंबे समय तक ऐसा रहने से भावनात्मक थकान बढ़ जाती है।

कठोर आत्म-समीक्षा : इंसान खुद से बहुत उम्मीदें रखता है। खुद से नरमी से पेश नहीं आ पाता। यह भीतरी दबाव धीरे-धीरे मानसिक लचीलापन कम कर देता है।

संतुलन के लिए अपनाएं ये कदम

1. खुद को दोष न दें, नया सीखें : मेरे साथ क्या गलत है या मेरी ही गलती है, ऐसा न सोचें। यह अनुभव मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, इस पर विचार करें। यह आत्म सजगता है, यहीं से असल बदलाव शुरू होता है।

2. भावनात्मक नियंत्रण : तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। अपनी भावना और उस पर प्रतिक्रिया के बीच एक उचित दूरी बनाएं। कुछ देर के लिए तनावपूर्ण जगह से हट जाना, गहरे सांस लेना, व्यायाम करना या टहलना जैसे अभ्यास दिमाग शांत करते हैं।

3. सीमाएं तय करना : हर बात पर 'हां' कहने से बचें। सीमाएं बनाने का मकसद खुद को अलग-थलग करना नहीं, बल्कि स्वयं को रीचार्ज करना है।

4. खुद से जुड़ें : कुछ पल ठहरें और खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं?

एकदा

सच्चा तीर्थ

पिताजी, आपका सामान तैयार है। कुछ और रखना हो तो बता दीजिए', सिया ने कहा।

जवाहर जी हर वर्ष अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार जाते थे। अगले दिन भी उनकी यात्रा तय थी। रात को सिया की सास चश्मा ढूंढ़ते हुए उसके कमरे तक पहुंची। सिया फोन पर अपनी सहेली से रोते हुए कह रही थी, 'मैं अपनी बूढ़ी दादी को यहां कैसे रखूं? हो सकता है ससुराल वालों को पसंद न आए।'

सिया बचपन से अपनी दादी की गोद में पली थी। माता-पिता के निधन के बाद उन्होंने ही सिया को पाला था। सिया की शादी जवाहर जी के बेटे आकाश से हुई थी। उसके बाद उसकी दादी अकेले रह रही थी।

अगली सुबह जवाहर जी हरिद्वार के लिए निकल गए, लेकिन शाम को अचानक लौट आए। सिया ने आश्चर्य से पूछा, 'पिताजी, आप इतनी जल्दी वापस आ गए?'

जवाहर जी मुस्कुराए, 'हां बेटी। अब हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। हम सारे तीर्थ अपने घर ले आए हैं', यह कहकर उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला। भीतर सिया की दादी बैठी थीं। उन्हें देखते ही सिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह दौड़कर दादी से लिपट गई।

जवाहर जी बोले, 'बेटी, माता-पिता और बुजुर्गों की सेवा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। यदि अपने ही बुजुर्ग उपेक्षित हों, तो तीर्थयात्रा और पूजा-पाठ सब अधूरे हैं।'

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन परेशान रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में भागदौड़ बढ़ सकती है। किसी मित्र से किसी नए कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। यात्रा के योग हैं।

वृष : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। लेखनादि कार्यों से आय में बढ़ोतरी हो सकती है। कारोबार में भागदौड़ बढ़ सकती है।

मिथुन : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में बढ़ोतरी होगी। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

कर्क : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी भी रहेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। माता-पिता की सेहत का ध्यान भी रखें।

सिंह : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। बातचीत में संतुलित रहें। पढ़ाई के प्रति सचेत रहें। व्यवधान आ सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें।

कन्या : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। कारोबार के विस्तार के लिए परिवार से धन की प्राप्ति हो सकती है।

तुला : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के लिए अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। स्थान परिवर्तन के योग हैं।

वृश्चिक : मन परेशान हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें। संतान सुख में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। वस्त्र उपहार में मिल सकते हैं।

धनु : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में लाभ होगा।

मकर : आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। मन परेशान भी हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। खर्चों में वृद्धि होगी।

कुंभ : किसी अज्ञात भय से मन परेशान हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। कारोबार में परिवर्तन हो सकता है। यात्रा पर भी जा सकती है।

मीन : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। पढ़ाई में सफलता मिलेगी। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिलेंगे। आय में बढ़ोतरी होगी।

वर्ग पहेली : 8416

बाएं से दाएं

1. जीवन कठिन करना; निर्वाह कठिन करना (2,3,3)
6. चर्चा करना; संवाद शुरू करना (2,3)
8. जो कीचड़ से उत्पन्न हो; कमल; सारस (3)
9. भुजंग; सांप; बादल; मेघ; हाथी (2)
11. कन्नी; किनारा; सुनहला रुपहला पतला गोटा (3)
12. पर्वत; नगीना; मणि; रत्न; अदद (2)
15. मानदंड; स्तर (3)
16. कमर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा; पेटी; नाड़ा (5)
18. घूम कर लेटना; पलटा खाना; बेचैनी से पहलू बदलना; सो न पाना (4,4)

ऊपर से नीचे

2. ईश्वर पर अविश्वास; नास्तिकता का भाव (4)
3. सुख; स्वाद; अमृत; सुधा; निचोड़; द्रव; नीर; शोरबा; सार (2)
4. कला प्रेमी; आनंद लेने वाला (5)
5. तरल पदार्थ को इतना गरम करना कि वह उफनने लगे; जोश देना; तेज आंच पर गरम करना (4)
7. आश्लेषा नक्षत्र; नागों में अनंत आदि 8 सर्प (5)
10. आकाशगामी; नभचर; पक्षी; ग्रह; नक्षत्र (5)
13. बरतन का ऊपरी भाग; सिर को धड़ से जोड़ने वाला अंग; गला; ग्रीवा (4)
14. स्वर और ताल; सुर व ताल; संगीत (4)
17. किनारा; कूल; तीर; पुलिन; बेला; साहिल (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली

(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8415

1 आ	2 रा	म	ह	3 रा	म	4 क	र	ना
■	ष्ट्री	■	■	ग	■	रा	■	■
5 आ	य	त	6 न	■	7 श	ह	ना	8 ई
धि	■	■	9 ग	ला	■	ना	■	मा
10 का	ल	■	र	■	11 वि	■	12 दा	न
रि	■	13 बा	■	14 क	ला	■	■	दा
15 के	स	र	त	■	16 पु	रि	17 स	र
■	■	बा	■	18 पू	■	■	री	■
19 बा	ह	र	का	रा	स्ता	दि	खा	ना

सुडोकू : 8370

* कठिन

	9			3				6
	4			8		5		
		2		5				
8			6		9			2
4		3		7				5
			1			7		
	3		9				1	
7			8				4	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8369

4	9	3	2	6	7	1	8	5
7	6	5	3	1	8	9	2	4
8	1	2	5	9	4	3	7	6
1	8	4	7	2	6	5	9	3
2	5	7	1	3	9	6	4	8
6	3	9	8	4	5	2	1	7
3	2	8	4	5	1	7	6	9
9	7	1	6	8	3	4	5	2
5	4	6	9	7	2	8	3	1

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

10 अगस्त, सोमवार, शक संवत् : 19 श्रावण (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 26 श्रावण मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 26 सफर, 1448, **विक्रमी संवत्** : द्वादशी तिथि प्रातः 08.01 मिनट तक पश्चात त्रयोदशी रात्रि 04.55 मिनट तक, तैतिल करण। चंद्रमा मिथुन राशि में रात्रि 04.44 बजे तक उपरांत कर्क राशि में। **सूर्य दक्षिणायन।** सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 04.55 बजे से। सोम प्रदोष व्रत। श्रावण सोमवार व्रत। त्रयोदशी तिथि का क्षय।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

सावन में किए जाने वाले कुछ उपाय-

- यदि विवाह में अड़चने आ रही हो, तो इस माह में पांच बार शिव-पार्वती का गठबंधन करवाएं। कन्या हो तो मां पार्वती को शृंगार सामग्री अर्पित करें। युवकों को भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करना चाहिए। यदि बिना बात के विरोधी पैदा हो रहे हैं, तो शिवलिंग के नाग पर शहद चढ़ाएं। यदि बच्चे सुनते नहीं हो या पढ़ते नहीं हो, तो गणेशजी को 6 पेन या पेंसिल अर्पित करें, फिर उसमें से एक पेन या पेंसिल ले आएं और वो बच्चे को काम करने के लिए दें। साथ ही यदि गणेश चालीसा का पाठ करें। यह कार्य बुधवार को करें।
- वाहन खरीदने के लिए साधन नहीं बन पा रहे हैं, तो मंदिर में नंदीजी को गुड़ चढ़ाएं।

युवा देश का भविष्य होते हैं। वे परिवर्तन के वास्तविक वाहक हैं। - नेल्सन मंडेला

तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों हुआ रक्षा समझौता पश्चिम एशिया की बदलती सामरिक तस्वीर में एक नए आयाम के जुड़ने का संकेत है। इससे भारत के लिए तत्काल कोई खतरा तो नहीं, पर मुस्लिम नाटो को लेकर पाकिस्तान के उत्साह को देखते हुए उसे सतर्क रहने की जरूरत है।

मुस्लिम नाटो की राह

पिछले दिनों मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुआ रक्षा समझौता, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला, तीनों देशों पर सामूहिक हमला माना जाएगा, पश्चिम एशिया की बदलती सामरिक तस्वीर में एक नए आयाम के जुड़ने का संकेत है। उल्लेखनीय है कि समझौता आधिकारिक तौर पर किसी देश को साझा शत्रु के रूप में चिह्नित करने से बचता है, लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह से समझौते की घोषणा के अगले ही दिन मुस्लिम देशों से इस्राइल के खिलाफ एकजुट होने और साझा सैन्य मोर्चा बनाने का आह्वान किया है, वह येरूशलम के साथ-साथ भारत जैसे देशों की चिंताएं भी बढ़ाने वाला है। दरअसल, सामूहिक रक्षा समझौते का औचित्य तभी तक विश्वसनीय रहता है, जब तक उसका उद्देश्य अपने सदस्यों की सुरक्षा तक सीमित हो। लेकिन, अगर यही व्यवस्था किसी धार्मिक या राजनीतिक पहचान के आधार पर साझा शत्रु गढ़ने का जरिया बन जाए, तो उसके नतीजे कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं और यही इस समझौते का सबसे बड़ा जोखिम भी है। खास बात यह है कि तीनों देशों की क्षमताएं भी एक-दूसरे की पूरक हैं। सऊदी अरब के पास आर्थिक शक्ति और रक्षा पर भारी निवेश की क्षमता है। तुर्किये के पास विकसित रक्षा उद्योग, ड्रोन तकनीक, सैन्य अनुभव और नाटो सदस्य होने के नाते रणनीतिक पहुंच है। पाकिस्तान के पास भी बड़ी और अनुभवी सेना, मिसाइल क्षमता तथा परमाणु प्रतिरोधक क्षमता है। लिहाजा यह समझौता केवल प्रतीकात्मक नहीं रह जाता, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की भी पूरी क्षमता रखता है। यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ की मुस्लिम नाटो बनाने का संकेत देती टिप्पणी को महज राजनीतिक बयान मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि जो वह कह रहे हैं, वह इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान बेशक इस्राइल को मान्यता न दे, लेकिन तुर्किये का मामला बिल्कुल अलग है। वह इस्राइल को मान्यता देता है और कुछ तनावों

के बावजूद दोनों के बीच दशकों से राजनयिक संबंध भी रहे हैं। इसी तरह, अमेरिका के साथ संबंधों के मद्देनजर सऊदी अरब के लिए भी यह आसान नहीं होगा कि वह सीधे तौर पर इस्राइल के खिलाफ खड़ा हो जाए। जहां तक भारत की बात है, तो उसने पश्चिम एशिया के लगभग सभी प्रमुख देशों के साथ अलग-अलग स्तर पर मजबूत संबंध बनाए हैं, जो उसकी संतुलित और बहुस्तरीय विदेश नीति की सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी भी है। फिर भी, मुस्लिम नाटो के गठन को लेकर पाकिस्तान के उत्साह को देखते हुए उसे क्षेत्र की बदलती भू-राजनीति पर सतर्क निगाह रखने की जरूरत है।

जेन-जी को जेन-जी ही रहने दें

जेन-जी के पास भी भारत के जटिलतम सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक ताने-बाने को आनन-फानन में ठीक करने वाली कोई 'जादुई छड़ी' नहीं है कि उसे घुमाया और सब ठीक हो गया। 'बदलाव' का मुहावरा प्यारा होते हुए भी 'धोखे भरा' हो सकता है।

जेन-जी पीढ़ी बड़े भागों वाली है। कोई उसे पटा रहा है। कोई फुसला रहा है। कोई उकसा रहा है कि 'जेन-जी' तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जेन-जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई कह रहा है कि 'अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो'! कोई उसे अपना चेला बनाने के चक्कर में है, तो कोई उसे 'भगवान' की तरह पधारने के चक्कर में है। कोई कह रहा है कि जेन-जी ने चमत्कार कर दिया। उसने असंभव को संभव कर दिखाया। जिसे कोई न कर पाया, उसने कर दिखाया। ऐसी जेन-जी पीढ़ी की जय हो! जय हो! एक बेहद घमंडी सरकार को उसने बात की बात में हिला दिया। जो किसी की नहीं मानती थी, उससे अपनी सारी मांगें मनवा लीं। बड़े-बड़े मंत्री कुछ 'जेन-जी' के आगे पीछे चक्कर मारते दिखे। उनके एक से एक नाज-नखरे उठाते दिखे।

सुधीश पचौरी
वरिष्ठ साहित्यकार

जिस शिक्षा मंत्री को कोई नहीं हटा पाया, जेन-जी ने उसे हटवा दिया। छात्रों पर सारे केस वापस करवा दिए। 'नीट पेपर लीक' से पैदा हुई हताशा के कारण 'आत्महत्या' करने वाले छात्रों को कंपसेशन दिलाने की गारंटी ले ली। किसी से भी बात न करने वाले पीएम तक को सोशल मीडिया के जरिये जेन-जी से बात करने को मजबूर होना पड़ा।

एक दिन भारत के 'चीफ जस्टिस' द्वारा 'चलते-चलते' किए कटाक्ष की प्रतिक्रिया में अमरीका में बैठे कुछ भारतीय 'जेन-जी जनों' ने 'कांकरोच जनता पार्टी' बना डाली। यही जेन-जी भारत सरकार की गले की हड्डी बन गए। 'चौबीस बाई सात' के मीडिया कवरेज ने 'जेन-जी पीढ़ी' को 'जंतर मंतर' में 'विरोध का देवता' बना दिया। अंततः सरकार झुकी और प्रधानमंत्री को कई 'रीलों' के जरिये जेन-जी पीढ़ी से संवाद करने की जरूरत हुई। नतीजतन जेन-जी पीढ़ी को 'अपरिभाषेय मिथक' में बदल दिया गया।

फिर 'संघ' के मुखिया मोहन भागवत ने जेन-जी से बातचीत करके, जेन-जी के 'भाव' को और बढ़ा दिया कि जेन-जी ज्यादा ईमानदार है...कि

जेन-जी के सवालों का जबाव देना होगा...कि जेन-जी की शिकायतें सही हैं...कि जेन-जी से पहले बात करनी चाहिए थी...कि आंदोलन भी संवाद का तरीका है...कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में कमी है...कि शिक्षा का बजट 'छह प्रतिशत' होना चाहिए...कि जेन-जी राष्ट्र विरोधी नहीं...कि संवाद की जरूरत है, मतभेद की नहीं...आदि। यह एक प्रकार की 'मनोवैज्ञानिक 'नजलिंग' थी। 'नजलिंग' यानी टहोका या हल्का धक्का मारकर किसी रूठे को मनाने, उसे 'पुचकार'(पैपर) कर, उसको 'अलेले मेला मुन्ना मुन्नी' आदि कह, उसकी 'लल्ली-चप्पो' कर उसे चुप करने की कोशिश। किसी रोते हुए शिशु को चुप करने के लिए माता-पिता द्वारा उसके मुंह में 'पूप्सी फीडर' या 'सूदर' दूंस देना, फिर लोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश करना! बताइए, ऐसी अखंड चापलूसी सुन कोई बालक बावला क्यों न हो जाए? और जो पीढ़ी 'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर 'अधिकाधिक व्यूज' को पाकर अपने को 'आभासी दुनिया' का 'खुदा' समझती हो, वह क्यों न इतराए?

इस जेन-जी पीढ़ी को भूख हड़ताल और धरने पर बैठने के कारण मिली हमदर्दी ने हीरो बना दिया। बहुत से युवाओं के 'आउट ऑफ कंट्रोल' हो जाने पर भी पुलिस तो टारगेट बनी, लेकिन उनके प्रति हमदर्दी कम न हुई और सरकार उनके आगे 'लंबलेट' नजर आई। अब भी उनकी जरा-सी धमकी भी राज्य की सारी मशीनरी को हकबका देती है। भाजपा के जिस अश्वमेध के घोड़े को बारह साल से कोई नहीं रोक पाया, उसे कुछ जेन-जी युवाओं ने अपने पिछवाड़े बांध लिया। इसे देख विपक्ष भी अपने फॉर्म में आ गया। इसीलिए लगभग सभी दल, नेता व बुद्धिजीवी, जेन-जी की लल्ली चप्पो करते, उसे मनाते से, उसकी हां में हां मिलाते नजर आते हैं। कुछ विपक्षी जेन-जी को 'दुलारने'(पैपरिंग) में लगे दिखते हैं, कुछ 'जेन-जी' का 'बिजूका' दिखाकर सत्ता को डराते दिखते हैं कि अगर अब भी तुम्हारा अहंकार कम न हुआ व तुम न संभले और सड़ी-गली शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारा, बेरोजगारों को रोजगार न दिया, तो जेन-जी आ जाएगी और तुमको खा जाएगी। इसे देख कुछ ने 'कांकरोच पार्टी' के कुछ नेताओं को 'आप पार्टी' का पूर्व सदस्य बताकर उन्हें एक्सपोज करने की भी कोशिश की। कुछ ने उन्हें 'भारत विरोधी' अरबपति 'जार्ज सोरोस' से जुड़ा बताया, लेकिन जेन-जी का जलवा और धमक कम नहीं हुई। कल को कोई कहने लगे कि ये जेन-जी उसके या इसके एजेंट हैं, उससे भी उनका रुतबा कम नहीं होने वाला, क्योंकि एक तो 'जेन-जी' प्रकारांतर से हमारे जैसे 'बेबी बूमर्स व ओल्डर मिलेनियल्स' के ही बच्चे हैं, हमारे जैसों के ही 'नाती-पोते' हैं। ऐसे में हम भी भला अपने बच्चों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं?

यह 'कैच 22' वाली स्थिति है। कांकरोच पार्टी ने अचानक इन्हीं 'बेबी बूमर्स व ओल्ड मिलेनियल्स' के मन को दो फाड़ कर दिया है, जिनमें से बहुत से भाजपा के भी हो सकते हैं। इसीलिए मोदी से लेकर भागवत तक जेन-जी के आगे-पीछे करते नजर आते हैं। यह सच है कि कोई भी अपने बच्चों से दुश्मनी नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि कोई अपने बच्चों को भगवान बनाकर अपने सिर पर नहीं बिठा सकता। और इन जेन-जी के पास भी भारत के जटिलतम सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक ताने-बाने को आनन-फानन में ठीक करने वाली कोई 'जादुई छड़ी' नहीं है कि उसे घुमाया और सब ठीक हो गया। पहले भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ लोग संपूर्ण क्रांति किए हैं, लेकिन उसके अंत में भ्रष्टाचार ने कैसे-कैसे 'फूल' खिलाए हैं, यह हम सब जानते हैं। ऐसे में कहीं ये 'जेन-जी' भी तो इतिहास रिपीट करने नहीं आए?

लंबी अधीनता में जीने व उपनिवेशवादियों के अपने हितों के लिए बनाए और अब तक जड़ीभूत हो चुके सिस्टम को आमूल-चूल बदलना न दो दिन में संभव है, न आसानी से हो सकता है। 'बदलाव' का मुहावरा प्यारा होते हुए भी 'धोखे भरा' हो सकता है। यों, अपने जैसे समाज में किसी को 'भगवान' बना लेना आसान है, लेकिन भगवान को झेलना उतना ही कठिन है और भगवान को सिर पर ढोना तो और भी असंभव। इसीलिए भगवानों के विग्रहों को मंदिरों में पूजा जाता है। घर में भी उनको चौबीस घंटे सिर पर नहीं बिठाया जाता। अपने भगवान तो स्वयं भी किसी पर लदकर नहीं चलते, फिर भगवान भी एक-दो दिन में नहीं बनते, वे सदियों में बना करते हैं। इसीलिए हमारा निवेदन है कि 'जेन-जी' को 'जेन-जी' ही रहने दें, भगवान न बनाएं। किसी के पीछे दौड़ने की जगह खुद में भगवानत्व पैदा कीजिए। उसके कुछ गुण अपने में ले आइए, तब किसी कांकरोच या छिपकली के अवतार की जरूरत नहीं होगी।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

संत तिरुवल्लुवर

जिस हृदय में दया बसती हैं, वहां ईश्वर को अलग से खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि करुणा ही वह स्थान हैं, जहां मानवता और दिव्यता एक-दूसरे का स्पर्श करती हैं।

करुणा ही जीवन को सार्थक बनाती है

मनुष्य अपने ज्ञान पर गर्व कर सकता है, शक्ति पर अभिमान कर सकता है, धन को देख कर खुश हो सकता है। वह उत्तम वाणी बोल सकता है, शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, न्याय की बातें कर सकता है और संसार में सम्मान भी पा सकता है। पर यदि उसके हृदय में दया नहीं है, तो उसके ये सारे गुण उस वृक्ष के समान हैं जिसकी शाखाएं तो हरी दिखाई देती हैं, किंतु जिसकी जड़ें सूख चुकी हों। कुछ समय तक वह वृक्ष खड़ा तो रह सकता है, पर फिर उसमें जीवन नहीं रह जाता।

दया केवल एक गुण नहीं है। वह सभी गुणों की आत्मा है। जैसे शरीर में प्राण न हों, तो सुंदर अंग भी निष्प्राण हो जाते हैं। वैसे ही करुणा के बिना विद्या अहंकार व शक्ति अत्याचार बन जाती है। न्याय कठोरता में बदल सकता है। इसलिए यह मत देखो कि किसी मनुष्य के पास कितनी संपत्ति है या उसने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, पहले यह देखो कि दूसरे के दुख को देख कर उसका हृदय पिघलता है या नहीं। यही उसके चरित्र की सबसे बड़ी और सच्ची परीक्षा है। जो मनुष्य दूसरों के आंसू देख कर भी विचलित नहीं होता, वह संसार को केवल अपने लाभ की दृष्टि से देखता है। लेकिन जहां दया रहती है, वहां मनुष्य दूसरे में स्वयं को देखना सीखता है। तब वह किसी की सहायता इसलिए नहीं करता कि लोग उसकी प्रशंसा करें, बल्कि इसलिए कि किसी का कष्ट उसे अपना कष्ट प्रतीत होता है। प्रकृति को देखो। सूर्य कभी यह भेद नहीं करता कि किस पर प्रकाश डाला जाए और किस पर नहीं। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीतीं। उनका अस्तित्व दूसरों के हित में है। यदि प्रकृति का प्रत्येक तत्व देने में आनंद अनुभव करता है, तो मनुष्य फिर केवल अपने लिए क्यों जिए? उसकी श्रेष्ठता तो इसी में है कि वह अपने विवेक को करुणा के साथ जोड़ दे। कभी-कभी एक मधुर शब्द किसी भूखे को भोजन देने से भी अधिक मूल्यवान हो सकता है। किसी की बात धैर्य से सुन लेना ही करुणा है। इसलिए करुणा केवल हाथ से नहीं, वाणी, दृष्टि व विचार से भी प्रकट होती है।

कठोर होना सरल है, मगर कोमल होना कठिन है। यदि तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले अपने हृदय को निर्मल बनाओ। जिस ज्ञान से विनम्रता न आए, वह ज्ञान अधूरा है। जिस पूजा से दया न जागे, वह केवल कर्मकांड है। जिस तपस्या से दूसरों के प्रति प्रेम न बढ़े, वह तपस्या शरीर को सिर्फ कष्ट देना है। धर्म का फल करुणा है, यदि यह फल नहीं मिला, तो समझो वृक्ष अभी फलदायी नहीं हुआ। विद्या का मूल्य इस बात से नहीं कि उसने कितनी बहसें जीतीं, बल्कि इस बात से है कि उसने कितने हृदयों में प्रकाश पहुंचाया। इसलिए अपने भीतर करुणा का दीपक जलाए रखो। वही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। जिस हृदय में दया बसती है, वहां ईश्वर को अलग से खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि करुणा ही वह स्थान है, जहां मानवता और दिव्यता एक-दूसरे का स्पर्श करती हैं।

निःस्वार्थ बनें

सूत्र

मनुष्य की सच्ची महानता उसके ज्ञान, धन, शक्ति या सम्मान में नहीं, बल्कि उसके हृदय की करुणा में है। जिस ज्ञान से विनम्रता, जिस धर्म से दया और जिस शक्ति से दूसरों का हित न हो, वह अधूरा है। इसलिए दूसरों के दुख को समझें, उनके आंसुओं में अपना दर्द महसूस करें और बिना किसी स्वार्थ के सहायता करें। करुणामय बने रहना ही वास्तविक मनुष्यता है।

दूसरा पहलू

जलवायु परिवर्तन व प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण तितलियां अपने पारंपरिक क्षेत्रों को छोड़कर नए घर ढूंढने को मजबूर हैं।

आखिर कहां गायब हो रही हैं तितलियां

■ *शवन चौधरी*

कल्पना कीजिए कि एक दिन आपके बगीचे में तितली की ऐसी प्रजाति दिखाई दे, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा हो। यह खुशी का एक छोटा-सा पल लगता है, लेकिन यदि वह तितली अपने पुराने आवास में बढ़ती गर्मी, सूखे या पर्यावरणीय क्षरण के कारण मजबूर होकर यहां तक पहुंची हो, तो यह उत्साह नहीं, बल्कि प्रकृति के बदलते संतुलन का संकेत है। दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन व प्राकृतिक आवासों के तेजी से नष्ट होने के कारण तितलियां अपने पारंपरिक क्षेत्रों को छोड़कर नए घर ढूंढने को मजबूर हैं।

एक नए वैश्विक अध्ययन में पाया गया है कि दुनिया की ज्ञात हर दस तितली प्रजातियों में से एक पहले ही अपना क्षेत्र बदल चुकी है।

इस प्रक्रिया को स्पीशीज रेंज शिफ्ट कहा जाता है। एक नए वैश्विक अध्ययन में पाया गया है कि दुनिया की ज्ञात हर दस तितली प्रजातियों में से एक पहले ही अपना क्षेत्र बदल चुकी है। यह निष्कर्ष 105 देशों में 1,758 प्रजातियों पर किए गए व्यापक अध्ययन पर आधारित है। अध्ययन के अनुसार, लगभग 80 प्रतिशत तितली प्रजातियों ने अपने वितरण क्षेत्र का विस्तार किया है, जबकि 27 प्रतिशत प्रजातियों का क्षेत्र सिकुड़ गया है। तितलियों का स्थान परिवर्तन कई पर्यावरणीय कारणों का परिणाम है। तितलियों के लिए केवल अनुकूल मौसम पर्याप्त नहीं होता। उनकी इल्लियां विशेष पौधों पर निर्भर रहती हैं, जबकि वयस्क तितलियों को फूलों का रस, सुरक्षित प्रजनन स्थल चाहिए। जब शहरों का विस्तार होता है, तो उनका जीवन चक्र प्रभावित होता है और वे नए ठिकानों की तलाश करने लगती हैं। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इसके स्पष्ट उदाहरण मिल रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की टॉनी कॉस्टर तितली अब दक्षिण-पूर्व एशिया से होती हुई ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, लेकिन वनों की कटाई, शहरीकरण और आवासों का विनाश भी उतने ही जिम्मेदार हैं। किसी क्षेत्र से तितलियों का गायब होना इस बात का संकेत है कि वहां का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बदल रहा है। इसलिए संरक्षण की रणनीति भी बदलनी होगी। संरक्षण का मतलब सिर्फ उन जगहों को बचाना नहीं है, जहां जीव-जंतु पहले रहते थे, इसमें वे जगहें भी शामिल होनी चाहिए जहां वे नई जगह बसेंगे, और वे वाइल्डलाइफ कॉरिडोर भी जिनका इस्तेमाल वे वहां पहुंचने के लिए करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हो सकता है कि हम बीते कल की प्रकृति को तो बचाते रहें, लेकिन आने वाले कल की प्रकृति के पास जाने के लिए कोई जगह ही न बचे।

-साथ एलेटा बॉन और जोनाथन लेनो (द कन्वर्सेशन से)

तितलियों का स्थान परिवर्तन कई पर्यावरणीय कारणों का परिणाम है। जलवायु परिवर्तन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, लेकिन वनों की कटाई, शहरीकरण और आवासों का विनाश भी उतने ही जिम्मेदार हैं।

आंकड़े

अंग प्रत्यारोपण

देश में अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में पिछले एक दशक में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। लोग अब जागरूक हो रहे हैं और जरूरतमंदों को नया जीवन मिल रहा है।

2025	20,138
2024	18,911
2020	7,443
2019	12,666
2013	4,990

आंकड़े देश में अंग प्रत्यारोपण के, संख्या में। | स्रोत : राष्ट्रीय अंग एवं उतक प्रत्यारोपण संगठन

जब देवताओं के सभी अस्त्र विफल हो गए और धर्म संकट में पड़ गया, तब भगवती ललिता ने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया और समस्त आसुरी सेना भस्म हो गई।

तपस्या और वरदान

अंतर्यात्रा
संकलित

पौराणिक कथाओं के अनुसार, भंडासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने अपने पराक्रम से देवताओं, ऋषियों व समस्त लोकों को भयभीत कर दिया। उसने कठोर तपस्या कर अनेक वरदान प्राप्त किए थे, जिसके कारण उसे पराजित करना लगभग असंभव हो गया। जब सभी उपाय निष्फल सिद्ध हुए, तब देवताओं ने आदिशक्ति की आराधना की। उनकी प्रार्थना से भगवती ललिता त्रिपुरसुंदरी प्रकट हुईं। देवी ने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर अपनी अनगिनत शक्तियों और देवसेना के साथ भंडासुर के विरुद्ध धर्मयुद्ध का संकल्प लिया।

युद्ध कई दिनों तक चला। भंडासुर ने अपनी मायावी शक्तियों, असंख्य अस्त्र-शस्त्रों और विशाल सेना के बल पर देवी की सेना को रोकने का प्रयास किया, किंतु भगवती ललिता की दिव्य शक्ति के सामने उसका प्रत्येक प्रयास विफल होता गया। अंततः भगवती ललिता ने अपने दिव्य महाकामेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया, जिसकी प्रचंड शक्ति से भंडासुर और उसकी समस्त आसुरी सेना भस्म हो गई। भंडासुर के वध के साथ ही तीनों लोकों में पुनः धर्म, शांति और संतुलन की स्थापना हुई। देवताओं ने भगवती ललिता की स्तुति कर उनका आभार व्यक्त किया।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 10 अगस्त, 1954

स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी

मंदी के कारण स्कूलों में पढ़ने वाले बालकों की संख्या में कमी

उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, पर छात्रों की संख्या घट रही है। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते और उन्हें कमाने के लिए कहते हैं। इसलिए बाल मजदूरी भी बढ़ रही है।

विदेशी फंडिंग के नियमन में एक अहम मोड़

एफसीआरए संशोधन बिल विदेशी फंडिंग के नियमन के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जो थोड़े संदेह हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

विनीत नारायण | **मुद्दा**

एक बार फिर संसद के मानसून सत्र में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह संशोधन विधेयक एफसीआरए, 2010 में बड़े बदलाव ला सकता है। सरकार इसे विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाला कदम बता रही है, जबकि विपक्ष और नागरिक समाज संगठन इसे गैर-सरकारी संगठनों, ट्रस्ट और धार्मिक संस्थाओं पर राज्य के नियंत्रण का विस्तार मान रहे हैं।

एफसीआरए विदेशी दान को विनियमित करने वाला कानून है। इसके तहत एनजीओ, ट्रस्ट, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थाओं को विदेशी योगदान पाने के लिए पंजीकरण कराना पड़ता है, जिसे पांच साल पर नवीनीकरण कराने की जरूरत होती है। आंकड़ों के अनुसार जुलाई, 2026 तक करीब 14,449 सक्रिय एफसीआरए पंजीकरण थे, जबकि 22,498 रद्द हो चुके थे और 15,212 समाप्त माने गए। 2019-2022 के बीच

पंजीकृत संगठनों को लगभग 55,741 करोड़ रुपये का विदेशी योगदान मिला। कई रद्द या समाप्त पंजीकरणों के बाद विदेशी फंड से बनी संपत्तियों के प्रबंधन का स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं था। नया विधेयक इसी खामी को भरने का दावा करता है।

विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान एक 'नामित प्राधिकरण' का निर्माण है। इसके अनुसार, जब किसी संगठन का एफसीआरए प्रमाणपत्र रद्द, सरेंडर या नवीनीकरण न होने के कारण समाप्त हो जाता है, तो विदेशी योगदान और उससे बनी संपत्तियां अस्थायी रूप से इस प्राधिकरण में निहित हो जाएंगी। यदि निर्धारित अवधि में पंजीकरण बहाल नहीं होता, तो वे स्थायी रूप से निहित हो सकती हैं और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल या बिक्री भी हो सकती है। बिक्री की राशि भारत की समेकित निधि में जाएगी। साथ ही धार्मिक चरित्र वाली संपत्तियों के संरक्षण का प्रावधान भी है। प्रभावित संगठन 90 दिनों में पुनरीक्षण और जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकते हैं। इसके अलावा, नवीनीकरण के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपये के विदेशी योगदान के उपयोग की शर्त रखी गई है। अधिकतम कारावास पांच साल से घटाकर एक साल किया गया है और जांच से पहले केंद्र की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।

सरकार का तर्क है कि यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए आवश्यक है। रद्द या समाप्त पंजीकरणों के बाद हजारों करोड़ की संपत्तियां अधर में लटकी रह जाती थीं। राज्य सरकारें उन्हें न तो कब्जे में ले सकती थीं और न प्रबंधित कर सकती थीं। नया ढांचा इन संपत्तियों की सुरक्षा, प्रबंधन और उचित उपयोग सुनिश्चित करेगा। सरकार की दलील है कि यह सिविल सोसाइटी को कमजोर नहीं करता, बल्कि विदेशी योगदान को वैध प्रयोजनों तक सीमित रखता है और शासन को मजबूत बनाता है।

विपक्ष इसे 'दमनकारी' मानता है। उसका तर्क है कि नामित प्राधिकरण को व्यापक शक्तियां मिलने से सरकार एनजीओ की संपत्तियों पर कब्जा कर सकती है। पंजीकरण का स्वतः समापन प्रक्रियात्मक देरी से भी हो सकता है। नवीनीकरण आवेदन लंबित रहने या समय पर न लगाने पर संगठन पंगु हो जाएंगे। यह छोटे संगठनों, धार्मिक संस्थाओं (चर्चों और अल्पसंख्यक समूहों से जुड़े ट्रस्ट) और आलोचनात्मक आवाजों को निशाना बना सकता है। विपक्ष का कहना है कि नया विधेयक कार्यपालिका की शक्ति को और बढ़ाता है, न्यायिक समीक्षा को कमजोर करता है और लोकतांत्रिक स्थान को संकुचित करता है। केरल जैसे राज्यों में विदेशी फंड पर निर्भर स्कूल, अस्पताल और कल्याणकारी संस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं।

विशेषज्ञों का एक वर्ग इसे मौजूदा खामियों को भरने वाला व्यावहारिक कदम मानता है, जबकि दूसरे वर्ग का कहना है कि यह एफसीआरए को विनियमन से आगे ले जाकर सिविल सोसाइटी पर व्यापक राज्य नियंत्रण का औजार बना रहा है। एफसीआरए संशोधन विधेयक, 2026 विदेशी फंडिंग के नियमन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। सरकार की मंशा राष्ट्रीय हित और पारदर्शिता की है, लेकिन प्रावधानों में कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार विपक्ष और नागरिक समाज की चिंताओं को जायज ठहराता है। सच्चा लोकतंत्र पारदर्शिता और स्वतंत्र सिविल सोसाइटी, दोनों की मांग करता है। ऐसे में विधेयक पर विस्तृत चर्चा, स्वतंत्र निगरानी तंत्र और छोटे संगठनों के लिए राहत के बिना इसे पारित करना अनुचित होगा। कानून का उद्देश्य विदेशी योगदान को नियंत्रित करना होना चाहिए, न कि वैध सामाजिक कार्यों को बाधित करना। संसद को इस संतुलन को साधना चाहिए, ताकि पारदर्शिता के नाम पर स्वतंत्रता का गला न घोंटा जाए।

अमर उजाला Job Alert
Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

पंजाब नेशनल बैंक
लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर करें आवेदन
pnb पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank
545 पद
आवेदन की अंतिम तिथि : 16 अगस्त, 2026
पात्रताएं : ग्रेजुएट व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : pnb.bank.in

यूकेएसएसएससी की अधिसूचना ■ 379 पद
लेखाकार व अन्य पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि : 15 अगस्त, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष
यहां आवेदन करें : sssc.uk.gov.in

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ■ 114 पद
असिस्टेंट इंजीनियर व अन्य पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 31 अगस्त, 2026
योग्यताएं : इंजीनियरिंग व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : ngel.in

कोंकण रेलवे में नौकरी के मौके ■ 134 पद
अप्रेंटिसशिप के लिए करें आवेदन
दस्तावेजों के सत्यापन की तिथि : 24-28 अगस्त, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 25 वर्ष
यहां आवेदन करें : konkanrailway.com

आरसीएफ लिमिटेड ■ 94 पद
मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर निकली भर्ती
आवेदन की अंतिम तिथि : 24 अगस्त, 2026
योग्यताएं : बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : rcfltd.com

संघ लोक सेवा आयोग ■ 34 पद
असिस्टेंट डायरेक्टर व अन्य पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 28 अगस्त, 2026
योग्यताएं : ग्रेजुएशन व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : upsc.gov.in

यहां भी रोजगार की संभावनाएं ...
योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा : रजिस्ट्रार व अन्य पदों पर निकली भर्ती।
■ आवेदन की अंतिम तिथि : 15 सितंबर, 2026
■ spav.ac.in
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल : सहायक पंजीयक व अन्य पदों पर मौके।
■ आवेदन की अंतिम तिथि : 19 अगस्त, 2026
■ nitw.ac.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

रोशनी यहां है

इस बार
कंडुला जेसी
क्यों
चंद्र क्यूबसैट मिशन के लिए हुआ चयन

सरकारी स्कूल से पढ़ाई, छोटी उम्र में ही अंतरिक्ष क्षेत्र में बनाई पहचान

आंध्र प्रदेश की 14 वर्षीय कंडुला जेसी ने अपनी प्रतिभा और जिज्ञासा से अंतरिक्ष की दुनिया में खास पहचान बनाई है। सरकारी स्कूल की छात्रा जेसी को दुनिया के पहले ऑल-गर्ल्स लूनर क्यूबसैट मिशन 'शक्तिसैट' के लिए चुना गया है। वह इस मिशन में चुनी गईं 20 भारतीय छात्राओं में शामिल हैं।

बात मई 2025 की है। जेसी गर्ल्स हाईस्कूल, धवलेश्वरम में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे अपने बोर्ड इम्तिहान की तैयारियों में जुटे थे। लेकिन चौदह वर्षीय एक बच्ची ऐसी भी थी, जिसकी निगाहें किताबों से आगे एक बड़े सपने पर टिकी थीं। विज्ञान की दुनिया में कुछ अनोखा करने का जुनून और जिज्ञासा ने उस साधारण सरकारी स्कूल की छात्रा को आज देशभर में चर्चा का विषय बना दिया है। हम बात कर रहे हैं कंडुला जेसी की, जिन्हें दुनिया के पहले अंतरराष्ट्रीय ऑल गर्ल्स लूनर क्यूबसैट मिशन 'शक्तिसैट' के लिए चुना गया है। कंडुला जेसी करीब 12,000 आवेदकों और 108 देशों की प्रतिभागियों के बीच चुनी गई 20 भारतीय छात्राओं में शामिल हैं और आंध्र प्रदेश से इस दल की एकमात्र प्रतिभागी हैं। इस मिशन के तहत छात्राओं की टीम द्वारा तैयार किए गए लूनर क्यूबसैट को 11 अक्तूबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाने की योजना है। यह दुनिया का पहला ऐसा मिशन है, जिसमें केवल छात्राएं मिलकर चंद्र मिशन के लिए क्यूबसैट तैयार कर रही हैं। मिशन के तहत जेसी को सैटेलाइट सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी और अन्य तकनीकी विषयों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार और स्कूल का नाम रोशन किया है, बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक नई उम्मीद पैदा की है।

पिता एक कारपेंटर हैं

आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के धवलेश्वरम की रहने वाली 14 वर्षीय कंडुला जेसी की कहानी एक छोटे से शहर से निकलकर अंतरिक्ष विज्ञान के बड़े मंच तक पहुंचने की है। साधारण परिवार से आने वाली जेसी के पिता कारपेंटर हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने के कारण उनके माता-पिता ने उन्हें निजी स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। कक्षा दसवीं की छात्रा जेसी वर्तमान में जिला परिषद गर्ल्स हाईस्कूल, धवलेश्वरम में पढ़ाई कर रही हैं।

शिक्षिका ने पहचानी प्रतिभा

जेसी की विज्ञान के प्रति रुचि को सबसे पहले उनकी शिक्षिका ने पहचाना। उन्होंने जेसी की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उसका पंजीकरण मिशन शक्तिसैट कार्यक्रम में कराया। जेसी का सपना इसरो में काम करना है। अपनी उपलब्धि तक सीमित न रहते हुए जेसी ने स्कूल की अन्य छात्राओं को भी इस अवसर के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में तकनीकी समस्या के कारण वह ऑनलाइन कोर्स पूरा नहीं कर पाई थीं, लेकिन उनकी शिक्षिका के प्रयासों से उन्हें दोबारा मौका मिला। इसके बाद जेसी ने चयन प्रक्रिया के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया और अंतिम चयन में अपनी जगह बनाई।

बोर्ड के साथ स्पेस साइंस की पढ़ाई

कक्षा 10वीं की पढ़ाई और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ जेसी ने मिशन शक्तिसैट की ऑनलाइन कक्षाओं में भी पूरी लगन के साथ हिस्सा लिया। पढ़ाई के दबाव के बावजूद उन्होंने इस विशेष कार्यक्रम के लिए निर्धारित समय निकाला और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े नए विषयों को समझने का प्रयास किया। कई तकनीकी अवधारणाओं को समझने के लिए उन्हें अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। इसके बावजूद जेसी ने चुनौतियों से घबराने के बजाय अपने शिक्षकों की मदद ली, अध्ययन सामग्री को समझा और धीरे-धीरे इन जटिल विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत की। बोर्ड परीक्षा की तैयारी और मिशन की ट्रेनिंग दोनों को साथ संभालते हुए जेसी ने इस कार्यक्रम के हर चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया।

अंग्रेजी सुधारी, फिर दिया इंटरव्यू

मिशन शक्तिसैट में चयन के लिए जेसी की सबसे बड़ी चुनौती इंटरव्यू था, क्योंकि यह पूरी तरह अंग्रेजी भाषा में होना था। इसके लिए जेसी ने शिक्षकों की मदद ली और ऑनलाइन शैक्षणिक वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी बोलने का लगातार अभ्यास किया। कई हफ्तों की तैयारी के दम पर जेसी ने इंटरव्यू में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी मेहनत का परिणाम रहा कि उन्होंने चयन प्रक्रिया के सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे किए और मिशन शक्तिसैट के लिए चुनी गईं 20 भारतीय छात्राओं में अपनी जगह बनाई।

युवाओं को सीख

- नए अवसरों को पहचानना और उन्हें पाने के लिए प्रयास करना जरूरी है।
- कठिन विषयों या चुनौतियों से डरने के बजाय लगातार सीखते रहना चाहिए।
- अपनी उपलब्धियों तक सीमित न रहकर दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

10 अगस्त, 2003 आज का दिन

रूसी कॉस्मोनॉट यूरी मालेन्चेंको ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हुए एकातेरिना दिमित्रीव से वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक के जरिये विवाह किया था।

- 1793 : पेरिस में लूव्र संग्रहालय जनता के लिए खुला था।
- 1950 : हॉलीवुड फिल्म 'सनसेट बुलेवार्ड' का विश्व प्रीमियर हुआ था।
- 1986 : जाने-माने स्वदेश खिलाड़ी सौरव घोषाल का जन्म हुआ था।
- 1995 : मृगेन्द्र व्यंग्यकार और लेखक हरिशंकर परसाई का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : श्रावण कृष्ण पक्ष द्वादशी/त्रयोदशी।
कल : श्रीनंगजल से रुद्राभिषेक, मास शिवरात्रि व्रत, वर्षा ऋतु, सूर्य दक्षिणायने, उत्तर गोले।
राहुकाल : दिन में 15.00 से 16.30 तक।

कल का पंचांग

सूर्योदय : 05.52
सूर्यास्त : 19.00
(भारतीय मानक समयानुसार)

विक्रमी संवत 2083, 20 श्रावण मास शक 1948, श्रावण मास 27 प्रविष्टे, 27 सफर हिजरी 1448, श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 25.53 तक उपरांत अमावस्या, पुनर्वसु नक्षत्र 10.09 तक उपरांत पुष्य नक्षत्र, सिद्धि योग 18.51 तक उपरांत व्यतिपात योग, विष्टि (भद्रा) करण 15.23 तक उपरांत शकुनि करण, चंद्रमा कर्क राशि में दिन-रात।

राशिफल

amarujala.com/astrology
पं. विनोद त्यागी

मेष : मन में आशा का संचार होगा। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में नूतन पद भार संभव है।
वृष : व्यक्तिगत संबंध सहायक रहेंगे। अटका धन मिल सकता है। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा।
मिथुन : आत्मबल बना रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। नौकरी में उन्नति के संकेत मिल सकते हैं।
कर्क : सकारात्मक सोच बनाए रखें। योजना में सफलता मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन संभव है। व्यय अधिक होगा।
सिंह : स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यक्तिगत संबंध सहायक रहेंगे। विरोधी परास्त होंगे। नौकरी में मान-सम्मान बढ़ेगा।
कन्या : सकारात्मक सोच बनाए रखें। कार्य विशेष में सफलता मिलेगी। नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे।
तुला : स्वजन सहयोग मिलेगा। नौकरी में उन्नति के संकेत मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी।
वृश्चिक : मानसिक तनाव बना रहेगा। स्वजन सहयोग मिलेगा। नए कार्य में पूंजी निवेश से बचें। व्यवसाय में मंदी रहेगी।
धनु : पूर्व में किए श्रम के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नौकरी प्राप्ति के प्रयास सफल होंगे। परिवार में आनंद रहेगा।
मकर : क्रोध पर नियंत्रण रखें। नौकरी में आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना होगी। अटका धन मिल सकता है।
कुंभ : व्यवहार कुशलता बनाए रखें। किसी परेशानी का हल मिलेगा। नौकरी में नए प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं।
मीन : राजनीतिक संबंध सहायक रहेंगे। भू-संपत्ति का अटका कार्य बन सकता है। नौकरी में कार्य भार बढ़ेगा।

सुडोकू

8	2			5				
5	6				1		2	
		4	7					
	9		1			8	5	7
2	3	5			9		1	
					7	6		
	4		5				8	9
				9			7	5

8	2	7	6	5	3	1	9	4
5	6	3	9	4	1	7	2	8
9	1	4	7	8	5	6	3	2
4	9	6	1	3	2	8	5	7
1	7	8	4	6	5	9	3	2
2	3	5	8	7	9	4	1	6
3	5	9	2	8	7	6	4	1
7	4	2	5	1	6	3	8	9
6	8	1	3	9	4	2	7	5

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

देश

4200 करोड़ का एक्सप्रेसवे और दस जगह धंसा

कानपुर से लखनऊ तक सभी जगहों पर पानी निकासी के नहीं मिले ठोस इंतजाम...सड़क पर भरा मिला पानी

संवाद न्यूज एजेंसी

उन्नाव। 4200 करोड़ रुपये का कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे फिर दस जगहों पर धंस गया। पानी निकासी के ठोस इंतजाम न होने के कारण रविवार को हुई बारिश के दौरान कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन पर कुछ जगहों पर जलभराव जैसी स्थिति रही। एक दिन पहले ही एनएचएआई की केंद्रीय टीम के तकनीकी सदस्य ने एक्सप्रेसवे के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल खड़े किए थे।

रविवार को असोहा में किलोमीटर संख्या 47.9 से लेकर 47.1 तक आठ सौ मीटर, किमी संख्या 46.6 से किमी संख्या 46.3 तक तीन सौ मीटर और किमी संख्या 45.5 पर बरसाती पानी भरा नजर आया। इन स्थानों पर सड़क भी धंस गई।

दो साल में ही दरकने लगा 30 करोड़ का रेलवे ओवरब्रिज

कानपुर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 30 करोड़ रुपये की लागत से बना सरसौल रेलवे ओवरब्रिज दो साल में ही दरकने लगा है। जुलाई 2024 में जनता के आवागमन के लिए शुरू किए गए इस ब्रिज की सड़क के दोनों ओर की दीवारें कई जगह से धंसने लगी है। आरसीसी के टुकड़े टूट-टूटकर नीचे लोगों पर गिर रहे हैं। आरओबी के नीचे से रोजाना सैकड़ों राहगीर, छात्र और वाहन गुजरते हैं। ऐसे में बारिश में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सरसौल ओवरब्रिज की आधारशिला एक जनवरी 2022 को रखी गई थी। संवाद

राहगीरों पर गिर रहे आरसीसी के टुकड़े

बांकेबिहारी से लाड़ लड़ाने को उमड़े श्रद्धालु

कामिका एकादशी पर श्रद्धालुओं ने पंचकोसीय परिक्रमा भी लगाई

वृंदावन। कामिका एकादशी पर रविवार को ठाकुर बांकेबिहारी से लाड़ लड़ाने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आराध्य श्रीबांकेबिहारी के दर्शन के लिए देश के कोने-कोने से हजारों श्रद्धालु वृंदावन पहुंचे।

मंदिर मार्ग पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को पसीना बहाना पड़ा। जगह-जगह रस्सी और बैरियर लगाकर श्रद्धालुओं को कुछ समय के लिए रोककर मंदिर की ओर आगे बढ़ाया गया। तेज धूप और उमस भरी गर्मी में श्रद्धालुओं ने मिनटों का रास्ता घंटों में तय किया। सुबह से ही मंदिर की ओर जाने वाले प्रमुख मार्ग भक्तों से भर गए। बांकेबिहारी लाल की जय और राधे-राधे के जयकारों से आसपास का क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। भीड़ और गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद जब भक्तों को ठाकुरजी की एक झलक मिली तो उनकी सारी थकान दूर हो गई। संवाद

आयोग ने जामा मस्जिद कमेटी के सदर को माना अफवाह का जिम्मेदार

संभल। 24 नवंबर 2024 का बवाल मस्जिद के वजूखाने के हौद में खोदाई की अफवाह के बाद शुरू हुआ। यह अफवाह फैलाने का आरोप जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली और मस्जिद की कमेटी के अन्य पदाधिकारियों पर है। इसका उल्लेख न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में किया गया है।

कमेटी के सदर ने किसी व्यक्ति के कान में कुछ कहकर बाहर भेजा इसके बाद ही हुआ संभल में बवाल

अलग-अलग दौर की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए थे सदर : एसआईटी ने अलग-अलग समय में पूछताछ की थी। जब उनके खिलाफ पुलिस को बवाल की साजिश के सबूत मिले तो 23 मार्च 2025 को एसआईटी ने कोतवाली में पूछताछ के बाद जफर अली को गिरफ्तार कर लिया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 नवंबर 2024 की सुबह जामा मस्जिद का सर्वे चल रहा था। जामा मस्जिद कमेटी के सदर व अन्य पदाधिकारी आधा घंटे के लिए गायब हुए थे। इस दौरान भीड़ को उकसाया गया। जामा मस्जिद कमेटी के सदर पर आरोप है कि उन्होंने किसी व्यक्ति को कान में कोई बात कहकर बाहर भेजा था। इसके बाद ही धार्मिक नारों की आवाजें तेज हो गई थीं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बयान में यह दावा किया है कि भीड़ ने ही पुलिस को बताया कि जफर अली ने अंदर से एक व्यक्ति भेजा है। जिसने बताया है कि मस्जिद में वजू का हौद खाली कर खोदाई किए जाने की तैयारी है। इसके बाद ही भीड़ उग्र हो गई और गोलीबारी की गई। संवाद

न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में मुझपर जो आरोप लगाए गए हैं, वह गलत हैं। मैंने भीड़ को समझाया था, न कि उकसाया। - **जफर अली,** सदर, जामा मस्जिद कमेटी

पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए सपोर्ट सेल बनाए केंद्र सरकार

औद्योगिक घरानों की तरह हो व्यवहार : संसदीय समिति

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सरकार को अपने बूते कारोबार खड़ा करने वाले उद्यमियों की मदद के लिए संसदीय समिति ने 'सपोर्ट सेल' बनाने का सुझाव दिया है। इससे पहली पीढ़ी के उद्यमियों को भी बड़े औद्योगिक घरानों, कॉरपोरेट निवेशकों की तरह डिजिटल सिंगल-विंडो तक पहुंच मिल सकेगी। उन्हें फास्ट-ट्रैक सुविधा व अनुपालन संबंधी लाभ मिलने का रास्ता भी साफ होगा।

संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशों के साथ ही खामियां पर चिंता भी जाहिर की है। रिपोर्ट में कहा है कि केंद्र, राज्य व स्थानीय स्तर पर उद्यमियों को मिलने वाले अनुमोदन को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर लाया जाए। सभी आवेदन, दस्तावेज, भुगतान, निरीक्षण और मंजूरी सब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में आकर एकीकृत हों।

कागजी कानूनी प्रक्रियाओं से आगे बढ़ने की जरूरत

समिति ने कहा कि धीमी और कागज-आधारित कानूनी प्रक्रियाओं से आगे बढ़ना आवश्यक है। नियामकीय जिम्मेदारियां अब भी कई प्राधिकरणों के बीच बंटी हुई हैं। इसके कारण अक्सर एक ही कार्य के लिए कई स्तरों पर मंजूरी लेनी पड़ती है। बार-बार निरीक्षण होते हैं और कानूनों की व्याख्या में असंगति देखने को मिलती है।

रेस्तरां, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल क्षेत्रों के लिए एक लाइसेंस

यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार मिलते-जुलते लाइसेंसों को एकीकृत करने पर विचार करे। फैक्टरी एक्ट, बॉयलर्स एक्ट, पेट्रोलियम एक्ट आदि के तहत निरीक्षण संबंधी कार्यों को एकीकृत करे और जोखिम आधारित निरीक्षण व्यवस्था वाले एकीकृत निरीक्षण प्राधिकरण बनाया जाए।

ईडी ने अनिल अंबानी समूह से जुड़े दो मामलों में दाखिल की चार्जशीट

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियों और पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के दो अलग-अलग मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की जानकारी दी। पहले मामले में शनिवार को दिल्ली की द्वारका स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, समूह के पूर्व अधिकारी सतीश सेठ (70) और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की गई। सेठ को जून में ईडी ने गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। उन्होंने 2025 में रिलायंस समूह छोड़ दिया था।

दूसरे मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड से जुड़े केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में पूरक चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले में मुख्य चार्जशीट मार्च में दाखिल हुई थी। ईडी ने बताया कि रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, पूर्व अधिकारी सतीश सेठ, गौतम, अमिताभ झुनझुनवाला और अन्य को आरोपी बनाया गया है। गौतम को जून और सेठ को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की फरवरी की एफआईआर से जुड़ी है। एजेंसी

1857 की क्रांति के गुमनाम नायकों को खोजेंगे इतिहासकार

मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपेक्षित इतिहास को नया आयाम मिलेगा। चौधरी चरण सिंह विधि का इतिहास विभाग इस पर विशेष शोध कर रहा है। यह शोध क्रांति के गुमनाम जननायकों के योगदान को दुनिया के सामने लाएगा। वरिष्ठ इतिहासकार प्रो. केके शर्मा के नेतृत्व में यह शोध हो रहा है। 10 मई 2027 को संग्राम के 170 वर्ष पूरे होने पर विशेष आयोजन होंगे। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, बिजनौर और सहारनपुर के किसानों, मजदूरों ने प्राणों की आहुति दी थी। संवाद

चार जजों को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने की सिफारिश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार न्यायाधीशों को अलग-अलग हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने की सिफारिश की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र त्रिपाठी को बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस रवींद्र वी. घुगे को कलकत्ता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा को यहीं पर मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। एक और फैसले में, कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के दो जजों के तबादले की भी सिफारिश की है। ओडिशा हाईकोर्ट में तैनात जस्टिस मानस रंजन पाठक का तबादला गुजरात कर दिया गया है। ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा का तबादला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में किया गया है। एजेंसी

दारुल उलूम में कल जल चढ़ाने का एलान, सतर्क

माहौल खराब करने वालों को प्रशासन की मिली चेतावनी

देवबंद। हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने 11 अगस्त को दारुल उलूम में जल चढ़ाने का एलान किया है। इसके बाद से पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है।

वहीं, अपने विवादित बयानों और प्रदर्शनों को लेकर ललित शर्मा पहले भी चर्चाओं में रहे हैं। विवादित बयान की वजह से उन पर उत्तराखंड में प्राथमिकी तक दर्ज हो चुकी है। बता दें कि ललित शर्मा ने आठ अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके कहा कि वह 11 अगस्त को दारुल उलूम पहुंचकर जल चढ़ाएंगे। उनका दावा है कि दारुल उलूम परिसर में करीब 14 फीट नीचे शिव मंदिर और शिवलिंग मौजूद हैं। मई में भी ऐसा दावा करते हुए उन्होंने प्रशासन से वैज्ञानिक जांच और खोदाई कराने की मांग की थी। प्रशासन की ओर से उनके दावे की जांच के संबंध में प्रक्रिया की बात कही गई थी। जल चढ़ाने की चेतावनी के मामले में दारुल उलूम ने कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन सतर्क है। हालांकि कांवड़ यात्रा के चलते जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती है। वहीं, खुफिया विभाग के अधिकारी भी ललित शर्मा की चेतावनी के बाद सक्रिय हो गए हैं। सीओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। संवाद

फर्जी डिग्री से वकालत के आरोप में 26 अधिवक्ताओं पर एफआईआर

प्रयागराज। फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर बार काउंसिल में पंजीकरण कराकर वकालत करने के आरोप में 26 अधिवक्ताओं के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव आरके शुक्ला ने एफआईआर दर्ज कराई है। काउंसिल ने सत्यापन में इनकी डिग्री और अंकपत्र फर्जी मिलने का दावा किया है। एफआईआर के मुताबिक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश से जुड़ा है। कफील बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य मामले में हाईकोर्ट ने तीन जून 2026 को आदेश पारित किया था। इसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत एक अधिवक्ता की डिग्री सत्यापन के दौरान फर्जी पाए जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया था। इसके बाद बार काउंसिल ने संबंधित अधिवक्ता के शैक्षिक दस्तावेज का सत्यापन कराया। आरोप है कि लखनऊ निवासी एक अधिवक्ता ने 2013 की स्नातक डिग्री और अंकपत्र अधिवक्ता सीओपी (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) आवेदन पत्र के साथ लगाया था। संवाद